Haryana Vidhan Sabha

Debates

13th January, 1972 (Evening sitting)

Vol. I-No. 4

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Thursday, the 13th January, 1972 (Evening sitting)

	Page
General Discussion on the Budget (Resumtion) (Concld.)	(4) 1-76

HARYANA VIDHAN SABHA

Thusday, the 13th January, 1972 (Evening sitting)

The Vidhan Sabha met in the Hall of the Haryana Vidhan Sabha, Vidhan Bhavan, Sector-1, Chandigarh, at 2.00 P.M. of the Clock. Mr. Mr. Speaker (Brig. Ram Singh) in the Chair.

General Discussion on the Budget (Resumption)

Mr. Speaker: Now we resume discussion on the Budget. Sh. Banarsi Dass Gupta was on his legs.

श्री बनारसी दास गुप्ता (भिवानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रातः काल की बैठक में, मैं अपने विचार व्यक्त कर ही रहा था जब सदन एडजर्न हो गया। मैं अब सवेरे वाली बात पर आता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह कहते हुए मुझे प्रसन्नता होती है कि यह जो बजट सरकार ने पेश किया है, हर प्रकार से पूर्ण है। इस बजट में किसी भी दृष्टि से मुझे कोई भी कमी नजर नहीं आती। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी बोलते हुए कहा था कि सरकार ने प्रदेश मं चहुमुखी प्रगति की है और अगर किसी भी क्षेत्र में कोई ऐसी कमी हमसे रह गई हो तो विरोधी दल के सदस्य, हमें सुझाव दें और मुझे पूरी आशा है कि सरकार उन सुझावों को मानेगी और हर तरह से उस कमी को पूरा करने का प्रयस्त करेगी। परन्तु जैसी मैंने पहले कहा था कि विरोधी सदस्यों के पास कोई सुझाव

तो है नहीं जो हमें दे सकें, वे तो रचनात्मक ढंग से सोचते ही नहीं हैं। सुझाव देने की बजाये नुक्ताचीनी करना ही केवल उनका लक्ष्य रहा है।

अध्यक्ष महोदय, कल जो बजट इस हाउस में प्रस्तुत किया गया था, आपने भी उस पर नजर डाली होगी। सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात तो यह है कि सरकार ने हर क्षेत्र में विकास करते हुए जनता पर कोई भी ऐसा टैक्स नहीं लगाया है, जिससे कि उस पर किसी प्रकार का बोझा पड़े। इसीलिये मैं अपनी वित्तमंत्री महोदया व सरकार से कहूंगा कि वे इसके लिये बधाई के पात्र हैं कि वे बिना टैक्स का बोझा जनता पर डाले हुए इतनी तेजी से विकास का काम करते जा रहे हैं। इस बजट में 15 करोड़ 2 लाख रूपये का घाटा दिखाया गया है और जब बहन ओम प्रभा जैन जी इस बजट को पेश कर रही थीं तो विरोधी दल वाले कहते थे कि यह घाटे की दुकान है लेकिन उनको यह समझ लेना चाहिये कि जिस सरकार का बजट घाटे का होता है, वही सरकार शानदार होती है और वही एक शानदार बजट होता है। अगर कोई सरकार किसी काम के लिये रखे गये पैसे से अधिक खर्च कर दिखाये तो यह सरकार तथा उसके बजट की प्रशंसनीय बात होती है। अध्यक्ष महोदय, आपको भी तजरबा होगा कि आप से पहले आने वाली सरकारें जो बजट में प्रोवीजन करती थीं उससे कम रूपया खर्च किया जाता था और साल के आखिर में बहुत सारा रूपया लैप्स हो जाता था। लेकिन यह सरकार निर्धारित

आंकड़ो के मुताबिक खर्चा करती है और अध्यक्ष महोदय, इससे आगे भी हाउस के सामने साल में 2 या 3 सप्लीमैन्टरी डिमान्डज आती हैं, उनमें रूपया मांग कर ज्यादा खर्चा किया जाता है। अब यह 15 करोड़ 2 लाख रूपये के घाटे का जो बजट है, उसमें 9 करोड़ का घाटा तो पिछले वर्ष का है। इससे साबित होता है कि इस साल का जो नया बजट है इसमें केवल 6 करोड़ रूपया का ही घाटा दिखाया गया है और इसके साथ ही साथ यह भी विश्वास दिलाया गया है कि इस घाटे को जनता के ऊपर किसी प्रकार का टैक्स वगैरहा लगाकर पूरा नहीं किया जाएगा। बल्कि यह घाटा वसूली के द्वारा ही पूरा किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, जो वसूली है और जो लूप–होल थे, आपने देखा होगा कि उनको पूरा करने के लिये काफी चेष्टा की गई है। अध्यक्ष महोदय, चौथी पंचवर्षीय योजना में 225 करोड़ रूपये खर्च करना था जिसका कि एक साल अभी बाकी बचता है लेकिन 267 करोड़ रूपये पहले 4 सालों के दौरान खर्च किये जा चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, सारे सदन को और इस सदन के द्वारा हरियाणा की जनता को यह जानकर खुशी होगी कि जब इस पंचवर्षीय योजना की अवधि समाप्त होगी तो 3.70 करोड़ रूपये इस योजना पर खर्च किया जा चुका होगां जैसे कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में संकेत दिया था कि जहां तमाम हिन्दोस्तान की राष्ट्रीय आय में 5 प्रतिशत वृद्धि हुई है, वहां हरियाणा में 16.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह सब आंकड़े, यह स्थिति, जो अपने मुंह से बोलती है इसी

से पता चलता है कि इस प्रदेश में कितनी तेजी से खुशहाली आ रही है।

अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रदेश की खुशहाली के लिये दो चीजों की ही आवश्यकता होती है। एक कृषि में उन्नति हो और दूसरे उद्योग–धन्धों में। जहां तक कृषि का सम्बन्ध है, हमारी हरियाणा सरकार ने जो तरक्की 5 साल में पूरी करनी थी वह एक साल पहले ही पूरी की जा चुकी है, यह कितनी खुशी की बात है। दूसरी तरफ सरकार की नजर उद्योग–धन्धों की तरफ जाती है, उद्योग–धन्धों को बढ़ावा देने के लिये जो आंकड़े हमारे सामने हैं और वित्तमंत्री महोदया ने अपनी स्पीच में बतलाया है कि पुनर्गठन के समय हरियाणा में 11 स्टील रोलिंग मिल्ज थीं, अब उनकी संख्या 40 हो गई है। इसी प्रकार तारें बनाने वाली यूनिटों की संख्या 7 से बढ़कर 50 हो गई है। टैक्सटाइल इन्डस्ट्रीज में भी वृद्धि हुई है, पब्लिक सैक्टर में भी इन्डस्ट्रीज में वृद्धि हुई है। लेकिन एक बात में चाहता हूं कि जो हमारी औधोगिक नीति है, जो इन्डस्ट्रीयल पोलिसी है, उसमें तबदीली की जरूरत है। जैसे हमने निश्चय किया है कि हमको समाजवाद लाना है, देश को समाजवाद की ओर आगे बढ़ाना है और देश से गरीबी को दूर करना है, हमें इन सब बातों के लिये औधोगिक नीति में परिवर्तन करने की जरूरत है। आज हम देखते है कि कई बड़े–बड़े उद्योगपति, टाटा जैसे, जो करोड़ों और लाखों रूपये के कारखाने चलाते हैं, जहां उनके बड़े बड़े स्टील के कारखाने हैं वहां वे

साबुन और तेल तक भी बनाते हैं। हम देखते है कि एमबैसेडर कार बिरला बनाता है, उसमें जो छोटी–छोटी गरारियां लगती है उनको भी बिरला ही बनाता है। कोई उद्योगपति वनस्पति घी की फैक्टरी लगाता है, उससे जो कचरा बचाता है, उससे साबुन भी वही बनाता है। इस प्रकार साबुन का कारखाना भी वही मालिक लगा लेता है तो हमें इस नीति में परिवर्तन लाना होगा। मैं अपनी सरकार के द्वारा केन्द्रीय सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि हमारी औद्योगिक नीति इस प्रकार की बनानी चाहिए कि जो बड़ी–बड़ी इन्डस्ट्रीज हैं, की–इन्डस्ट्रीज हैं वे तो पब्लिक सैक्टर में लगाई जाएं और जो इसके इलावा बड़े–बड़े कारखाने हैं, उनके लिये बड़े–बड़े उद्योगपतियों को लाईसेन्स दिये जाएं। मगर जो इनसिलरीज जो कि छोटी–छोटी चीजों को बनाते हैं, इसके लिये बड़े कारखानेदारों को लाईसेन्स न दिया जाए, वह बाकी जनता में बांटे जाएं और बड़े–बड़े उद्योगपतियों के ऊपर यह प्रतिबन्ध हो कि वह छोटी–छोटी चीजें न बना पाएं। इस प्रकार मुल्क का उद्योगीकरण ठीक ढंग से हो सकेगा। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि अब हमें इन्डस्ट्रीज को रूरल एरियाज में भी फैलाने की जरूरत है। इससे यह होगा कि जो बोझा जमीन पर पड़ रहा है, वह भी कम हो जाएगा और जो हम जमीन पर प्रतिबन्ध लगाना चाहेंगे या जमीन की सीलिंग को कम करना चाहते हैं वह भी नहीं करना पड़ेगा और लोगों को रोजगार मिल सकेगा। जैसे कि हमारी प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों ऐलान किया कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ तो युद्ध जीत लिया है। लेकिन अब हमारी

एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हुई है और वह लडाई गरीबी के खिलाफ है ओर उसके खिलाफ अगर हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे सामने बड़ा भारी काम करने को है। यह विजय हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम रूरल एरियाज में और देहात के अन्दर उद्योग–धंधों का फैलाव करें, छोटे–छोटे कारीगर जो गांव के अन्दर हैं, चमड़े का काम करने वाले, लोहार, खादी कपड़ा बनने वाले जुलाहे ओर दूसरी तरह–तरह के कारीगर गांव में बैठ हैं और जो सदियों से वही पुरानी जमीनदोज खड्डियों के अन्दर बैठ कर काम करते हैं अगर उनका सही पथ–प्रदर्शन करें, उनके लिये कच्चे माल का प्रबन्ध किया जाये और पूंजी का प्रबन्ध किया जाये तो उन सबको बड़ा भारी लाभ हो सकता है। ऐसा करने से ही वे सब कारीगर उपयोगी साबित हो सकते हैं, बेरोजगारी दूर हो सकती है और राष्ट्रीय आय बढ़ सकती है। आज पानीपत में जाकर देखिये वहां खड्डी का कपड़ा कितने अच्छे–अच्छे डिजायन का बनता है और वह न केवल हिन्दुस्तान में बल्कि मिडल ईस्ट कन्ट्रीज में और दूसरे कई मुल्कों में जाता है और बिकता है।

श्री अध्यक्ष: गुप्ता जी आपको 35 मिनट हो गये हैं।

श्री बनारसी दास गुप्ता: बस जी, मैं दो–तीन मिनट में खत्म कर देता हूं। मैं निवेदन कर रहा था कि आज पानीपत की तरह हरियाणा का प्रत्येक गांव पानीपत बन सकता है, बेरोजगारी खत्म हो सकती है और जिस तरह हमने कृषि के अन्दर प्रगति करके हिन्दुस्तान में नाम पैदा किया है, उद्योग–धंधों के अन्दर भी

तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और नाम पैदा कर सकते हैं। अब अध्यक्ष महोदय, मैं जिस हल्के की नुमाइंदगी करता हूं, भिवानी के हल्के की, वहां जो कुछ कठिनाइयां हैं उनके बारे में दो–चार शब्द कहना चाहता हूं। मेरे हल्के में केवल 20/25 गांव ऐसे हैं जो नाम के ही नहरी गांव हैं क्योंकि वह तमाम इलाका टेल के ऊपर है। आप जानते हैं कि किसान के लिये पानी एक भारी कीमती चीज है ओर जब तक उनको पानी नहीं मिलता तब तक वे नही समझते कि उनके लिये कोई भलाई का काम हुआ है। चाहे और दूसरे कितने ही भलाई के काम कर दिये जायें। टेल के ऊपर होने की वजह से पीछे जितना घाटा पानी में होता है वह मेरे हल्के के गरीब किसानों को भुगतना पड़ता है। होता यह है कि जो तगड़े इन्फलुएंशल आदमी हैं और अफसरों तक जिनकी पहुंच है वे नहर में पाइप डालकर नाजायज तौर पर पानी हासिल कर लेते हैं, कट भी कर लेते हैं ओर इस तरीके से पीछे पानी में कट लगने की वजह से जो टेल पर खेत होते हैं उनको घाटा होता है। इसके अलावा एक बड़ा शोर किसानों के अन्दर है कि मोधे यह आउटलैट जो हैं वे ठीक ढंग से नहीं लगे हैं। इसमें भ्रष्टाचार चलता है ओर छोटे स्तर के जो मुलाजिम हैं बेलदार से लेकर ऊपर पनसाली तक वे पैसे खाते हैं और छोटे स्तर से मोरियां आगे पीछे करते है। इसमें सुधार की जरूरत है और मैं सरकार का धन इस तरफ दिलाते हुए निवेदन करता हूं कि वह ज्यादा मजबूती के सिाथ इस काम को देखे। इस तरफ दिलाते हुए निवेदन करता हूं कि वह ज्यादा मजबूती के साथ इस काम को

देखें। इस तरफ सरकार का ध्यान दिया भी गया है और फलांइग स्कवैड बनाया गया है जो काम कर रहा है लेकिन मैं चाहता हूं कि यह काम और तेजी के साथ हो। इसके अलावा मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं। माइनर के हैड के ऊपर आजकल कड़ियां लगाने का रिवाज है। अध्यक्ष महोदय, कड़ियों को लगाने में कई प्रकार की गड़बड़ हो जाती है। पनसाली जो होता है वह एक कड़ी ज्यादा या कम पैसे खाकर या और लालच में कर देता है। इस प्रकार कड़ियों के बची में से पानी रिसता रहता है। मेरा सुझाव है कि कड़ियों के बजाये हर हैड के ऊपर लोहे के गेट लगा दिये जायें तभी यह गड़बड़ खत्म हो सकती है और जो पानी रिसता रहता है उसका घाटा बंद किया जा सकता है। इसके इलावा एक ओर बात है जिसके लिये किसानों की शिकायत बनी रहती है। आठ दिन की टर्न होती है लेकिन मेरे इलाका का जहां तक ताल्लुक है शुक्रवार की रात को या शनिवार की रात को या शनिवार को नहर में पानी या तो बन्द हो जाता है या उसका स्तर नीचा हो जाता है इसलिये जिनकी बारी शनिवार–इतवार को आती है उनको पानी नहीं मिलता और वह घाटे में रहते हैं और पानी न मिलने से उनकी फसलें तबाह हो जाती हैं। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो टर्न का मामला है हसमें सुधार किया जाये जिससे उन गरीब किसानों की क्षतिपूर्ति हो सके और वे पूरी तरह लाभ उठा सकें। इन शब्दों के साथ में इस बजटा की सराहना करता हूं, इसका स्वागत करता हूं और

वित्तमंत्री महोदया को तथा सरकार को बधाठ देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा बजट सदन में पेश किया है।

चौ. ओम प्रकाश (एलनाबाद): स्पीकर साहब, आज इस हाउस के सामने 1972–73 का बजट विचाराधीन है और बहन ओम प्रभा जी ने बड़े अच्छे ढंग से इसे सदन में रखा है। यह काफी लम्बा चौड़ा है और इस समय सारी बातों के बारे में पूरी तफतील के साथ बात करने का मौका नहीं मिल सकेगा लेकिन चंद एक मदों के ऊपर मैं अपने विचार सदन के सामने रखूंगा और सरकार के ध्यान में लाऊंगा। सबसे पहले बहन ओम प्रभा जी ने इस 14 दिन की भारत–पाक लड़ाई के बारे में विस्तार से लिखा है। डाक्टर साहब, ने बड़े भावपूर्ण तरीके से इस हाउस के सामने उन वीर सैनानियों को जो इस देश की रक्षा करते हुये शहीद हुये, श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्होंने यह भी बताया कि किस ढंग से उनकी इस जीत का प्रचार करके सिर्फ एक ही सरकारी पार्टी उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। (इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुई) उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके द्वारा सदन को बताना चाहता हूं कि जिन दिनों हिन्दुस्तान की सरजमीन की पाकिस्तान के नापाक हाथों ने हमारी सरहदों की खिलाफवर्जी की और हमारे मुल्क पर तीन दिसम्बर की रात को हमला किया गया उस वक्त सारी अपोजीशन पार्टीज इस हरियाणा सरकार और इसके मुख्यमंत्री श्री बंसीलाल के खिलाफ राष्ट्रपति को जो चार्जशीट पेश किया गया था, उस सम्बन्ध में पब्लिक जलसा में

सारी बातें दोहराई जा रहीं थी ताकि जो मुख्यमंत्री उस इनक्वायरी को अपने तौर पर फेस न कर सके तो पब्लिक जलसा मे उन इलजामात को दोहराया जाये और .....

उपाध्यक्षा: देखिये चौ. औम प्रकाश जी आप बजट पर ही बोलें।

श्री बनारसी दास गुप्ता: आन ए प्वायट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदया मैं प्रार्थना करूंगा कि कोई भी सम्मानित सदस्य अगर किसी प्रकार के व्यक्तिगत इजजाम लगायेगा तो हम बरदाश्त नहीं करेंगे। हम आपकी रूलिंग चाहते हैं कि अगर कोई भी बजट के दायरा के बाहर जाकर बोलेगा तो हम बरदाश्त नहीं करेंगे।

उपाध्यक्षा: मैं मैंबर साहिबान से कहूंगी कि वे बजट पर ही बोलें और इधर–उधर की बातें करके हाउस का समय खराब न करें .....

चौ. दलसिंह: आप डिसीजन देने से पहले विचार कर लें कि इन बातों का इस बजट में जिक्र है (विघ्न) मैं जानना चाहता हूं कि बिरला की कारों का और टाटा की कम्पनियों का इस बजट में कहां पर जिक्र है।

चौ. ओम प्रकाश: उपाध्यक्ष महोदया, मैं कह रहा था कि जिस दिन पाकिस्तान ने हमारी सरजमीन पर हमला किया उस दिन सारी अपोजीशन पार्टीज पब्लिक जल्से कर रही थीं और हरियाणा की पब्लिक को बता रही थीं कि किस तरह हमारी सरकार कुरप्शन

कर रही है। जिस वक्त यह हमला हुआ उसी वक्त जहां कहीं भी अपोजीशन पार्टीज जलसा कर रही थीं, जल्से करने बन्द कर दिए और ऐलान किया कि हमें अपना देश प्यारा है, आज हमने देश के लिए लड़ना है क्योंकि हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मान पाकिस्तान है। मौजूदा सरकार के खिलाफ जो हमारा मूवमैंट चल रहा था उसको हमने बन्द कर दिया ताकि हम पाकिस्तान के नापाक इरादों को मलियामेट कर सकें। मेरे कहने का मतलब यह है कि .....(व्यवधान)

Deputy Speaker: Order, Order .... Please continue your speech.

Voices: Speak on the Budget .....

चौ. ओम प्रकाश: मैं बजट पर ही बोल रहा हूं। मेरे कहने का मतलब यह था कि जिस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी इलेक्शन स्टंट बनाने जा रही है उसी बात को लेकर हिन्दुस्तान के हर एक नागरिक ने, हर जगह जहां कहीं भी वह था, देश की रखा के लिये सब कुछ कुरबान किया था। मैं अपनी तरफ से उन सारे सेनानियों को, जिन्होंने देश की सरहदों पर अपने आपको बलिदान किया, हार्दिक श्रद्धाजंलि पेश करता हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जहां पर अपोजीशन पार्टीज का देश के लिये यह रोल था वहां इस मौजूदा सरकार का देश के लिये क्या रोल था। यह सरकार उन दिनों अपोजीशन पार्टीज के लोगों को गिरफ्तार करती रही और परेशान करती रही। डिप्टी स्पीकर

साहिबा, आप इस मामले में अपनी तरफ से एक कमेटी मुकर्रर करें ओर इन्क्वायरी करवाएं। मैं अपने गांव का जिक्र बताता हूं (श्री बनारसी दास जी की तरफ से विघ्न) **** (व्यवधान) (शोर)

श्री बनारसीदास गुप्ता: ****(शोर)****(शोर)**** ****

उपाध्यक्षा: अगर आप बजट पर बोलेंगे तो बड़ीद खुशी की बात है, खुशी से बोलें वरना मैं नहीं बोलने दूंगी।

श्री बनारसी दास गुप्ता: हम इन चीजों को बरदाश्त नहीं करेंगे। .....(व्यवधान)।

चौ. दल सिंह: आन ए प्वांयट आफ आर्डर, मैडम। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपके जरिए हाउस के अन्दर कई बातें होती हैं। अगर श्री बनारसी दास जी को कुछ कहना है तो बाद में कह सकते हैं। बीच में टोकने से हाउस का टाईम जाया होता है। बजट के ऊपर बोलते हुए सारी बातें कही जा सकती हैं, हर चीज पर बोल सकते हैं .....

विकास मंत्री (श्री प्रभु सिंह): लेकिन यहां गालियां नहीं दी जा सकती .....(शोर)

श्री बनारसी दास गुप्ता: उपाध्यक्ष महोदया, इन्होंने एक ही बात को बार–बार दोहराया है। मैंने अपने भाषण में कहा है कि सब पार्टियों ने देश की रक्षा के लिए कुर्बानियां

*Expunged as ordered by the Chair.

की है, हम ही इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहते। फिर बार–बार ऐसा क्यों कहते हैं (व्यवधान) आप मेरा भाषण उठा कर देख लें (व्यवधान) सबके लिए कहा है।

उपाध्यक्षा: मैं आनरेबल मैम्बर्ज से रिक्वैस्ट करूंगी कि मेहरबानी करके बजट पर बोलें। अगर ठीक नहीं बोलेंगे तो मैं उनको बोलने नहीं दूंगी।

चौ. ओम प्रकाश: आप मुझे बताएं, मैंने बजट के अलावा कहा क्या है .....(शोर)

श्री सत्य नारायण सिंगोल: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आकी रूलिंग चाहूंगा। श्री बनारसी दास गुप्ता जी बोल रहे थे तो उन्होंने चौ. हरद्वारी लाल के खिलाफ डायरैक्ट ऐलीगेशन लगाया था। वे यह ऐलीगेशन कौन से बजट के तहत लगा रहे थे, आपने उस वक्त उनको क्यों नहीं रोका .....(शोर) सब उनके पर्सन के खिलाफ है ....(व्यवधान) जब हम बिल्कुल रैलेवैंट और फैक्टस के साथ बोलते हैं तो आप उसको भी बन्द कर देती है।

Deputy Speaker: That was not relevant. Mr. Om Parkash was not relevant.

चौ. जय सिंह राठी: आप उनको तो रोकने की कोशिश ही नहीं करती (शोर) श्री बनारसी दास गुप्ता को एक बार भी नहीं कहा। अपोजीशन के साथ अच्छा तरीका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है .....(शोर)

उपाध्यक्षा: ऐसी बात नहीं है।

श्री प्रभु सिंह: अगर कोई इस तरह डांट मारेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे (शोर)

Sh. S.P. Jaiswal: On a Point of Order, Madam ....(Ch. Jai Singh Rathi rose to speak.)

Deputy Speaker: Mr. Rathi, take your seat. Mr. Jaiswal is not a point of order.

Sh. S.P. Jaiswal: Madam Deputy Speaker, I do not know whether you have heard any objectionable word in the speech of the Hon. Member. Mr. Gupta has used some words which, I think, are highly derogatory both to the Hon. Member behind me and to his father. I would request you to check it from the record and expunge them: any reference made to him or his father.

Deputy Speaker: You should quote the words so that I may expunge them.

Sh. S.P. Jaiswal: If I quote them it would be unparliamentary. A reference was made to him and his father. I would request you to see this from the record. I do not wish to repeat them. I would be ashamed to say such words.

श्री बनारसी दास गुप्ता: डिप्टी स्पीकर साहिबा, पहले इन्होंने कहा कि भिवानी जाकर देखेंगे। अगर आयंदा यह मेरे खिलाफ कुछ कहेंगे तो मैं जवाब दूंगा ..... (शोर)।

उपाध्यक्षा: **** इसमें बड़ा फर्क है। लेकिन फिर भी अगर इनमें कोई ऐसी चीज कही गई हो जो ठीक न हो तो ऐक्सपंज कर दिया जाए। I will request the Hon. Member that he should speak on the Budget. He can criticise the Government but not the persons.

चौ. ओम प्रकाश: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं बजट से एक इंच भी दूर नहीं जाऊंगा। मैंने कोई इर्ररैलेवैंट बात नहीं की थी, मुझे दुख: है कि आपने मेरी स्पीच की इर्ररैलेवैंट बताया है हालांकि मुझे बार बार इन्ट्रस्ट किया जाता रहा है।

Deputy Speaker: Please continue your speech.

चौ. ओम प्रकाश: मैं ला एंड आर्डर पर बोल रहा था कि किस तरह से पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ झूठे केसिज दर्ज किए। आज अगर किसी के खिलाफ हुई ज्यादती का केस पुलिस में जाए तो रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की जाती। अपोजीशन के आदमियों के आदमियों की रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती। मैं अपने गांव की बात बताता हूं, एक हरिजन मैम्बर पंचायत को उसके घर पर लूटा गया लेकिन पुलिस ने उसकी पर्ची तक नहीं काटी बल्कि दफा 107–151 के तहत उसका चालान कर दिया गया। मुझे यह बात चौधरी हरद्वारी लाल ने बताई है (व्यवधान) जब उनको मारने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराने के लिए जाते हैं तो दर्ज नहीं की जाती। टेलीफोन किया, रजिस्टर्ड लैटर भेजा जिसकी अकनौलेजमेंट की रसीद मेरे पास है। यह उस आदमी के खिलाफ

किया गया जो 25 साल से पंचायत मैम्बर रहा है और विधानसभा में डिबेट का रिकार्ड रहा है। अगर उसको पुलिस की तरफ से प्रोटैक्शन न मिले तो बुरी और निहायत शर्मनाक बात है। जब मुख्यमंत्री डबवाली फैक्ट्री में गये तो उन्होंने लोगों से ओपनली कहा कि इनके खिलाफ कुछ भी कर दो, पुलिस की तरफ से प्रोटैक्शन न मिले तो बुरी और निहायत शर्मनाक बात है। जब मुख्यमंत्री डबवाली फैक्ट्री में गये तो उन्होंने लोगों से ओपनली कहा कि इनके खिलाफ कुछ भी कर दो, पुलिस कुछ नहीं करेगी। जहां ला एंड आर्डर की यह हालत हो तो देश कैसे तरक्की करेगां मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां अपोजीशन का यह रोल हो वहां सरकार की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। सरकार को इंटेगरिटी का सबूत देना चाहिए। जब देश में ऐसे हालात थे तो 20 मिनिस्टरों की फौज ओर 13 चेयरमैन बदस्तूर कारों में घूमते रहे और टी.ए.डी.ए. लेते रहे। नैशनल डिफैंस फण्ड कलैक्टर करने के लिए मुख्यमंत्री सरसा में 7, 8, 9 तारीखों को गए थे।

वहां डिफैन्स फंड के नाम पर लोगों से लाखों रूपया इकट्ठा किया और उस रूपये को कांग्रेस पार्टी के नाम पर अनाउंस किया गया। इस रूपये को सरकारी अफसरों ने

*Expunged as ordered by the Chair.

डिफैन्स फंड के नाम पर इकट्ठा किया था और लोगों को रसीद तक नहीं दी गई। इससे ज्यादा गलत बात कोई नहीं हो सकती। (शोर)

श्री बनारसी दास गुप्ता: बिल्कुल गलत बोलता है।

चौ. ओम प्रकाश: डिप्टी स्पीकर साहिबा यह बात बिल्कुल ठीक है कि लोगों को रसीद नहीं दी गई और उसके बाद वह पैसा किसी और मद में दर्ज किया गया। वह पार्टी फंड के हिसाब में दिखाया गया, यह अखबार बताती है।

कृषि मंत्री (भजन लाल): उपाध्यक्ष महोदया, इन्हें बजट पर बोलना चाहिए।

श्री प्रेम सुख दास: डिप्टी स्पीकर साहिबा, सिरसा में जो पब्लिक मीटिंग हुई थी उसमें किसी साहब ने यह इंक्वायरी की थी कि आया यह डिफैन्स रैली मीटिंग है या कांग्रेस मीटिंग है। इस पर सी.एम. साहब ने लैक्चर करते वक्त जवाब दिया था कि यह मीटिंग पार्टी मीटिंग है ओर इसका ताल्लुक सिविल डिफैन्स से नहीं है। उन्होने यह भी कहा था कि इससे पहले जब वे आए थे तो वह सिविल डिफैन्स की मीटिंग थी। इसके अलावा, डिप्टी स्पीकर साहिबा, उस वक्त जो 41 हजार रूपये की थैली दी गई थी उसके बारे में मैंने यह कहा था कि ये रूपये कांग्रेस फंड के नाम से जमा करके शहर की तरफ से पार्टी फंड के लिए आपको दिए जाते हैं।

चौ. दल सिंह: डिप्टी स्पीकर साहिबा, वहां यह भी ऐलान किया गया था कि प्रेम सुख दास को टिकट मिलेगी। (विघ्न)

महंत गंगा सागर: मैडम, आन ए प्वांउट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदया, आनरेबल मैम्बर ने अभी अपनी स्पीच के अन्दर कहा था कि सरकारी अफसरों ने डिफैन्स फंड इक्ट्ठा करके खा लिया। उनको यह बात यहां सरासर नहीं करनी चाहिए। थी। पहली बात तो यह है कि यहां औफिसर्ज इस बात को कंट्राडिक्ट नहीं कर सकते और नम्बर दो बात यह कि बड़ी गैर–जिम्मेदारी की बात उन्होंने कही है। इस दफा डिफैन्स फंड जहां कही भी कलैक्ट हुआ है वहां बाकायदा पक्की रसीदों के जरिए इकट्ठा हुआ है। इसलिए इस तरह की बात कहना बिल्कुल गलत है।

Ch. Jai Singh Rathi: Absolutely wrong; absolutely wrong; not a single receipt has been given; absolutely wrong.

Sh. S.P. Jaiswal: May I draw your attention to the Rule according to which interruption is not permitted. I would request that if any remarks are made against certain Members, they be given an opportunity to controvert them so as to maintain the dignity and decorum of the House. Running commentary is not allowed; interruption is not allowed.

मुख्य संसदीय सचिव (श्रीमती शारदा रानी): मैडम, आन ए प्वांयट आफ आर्डर। अभी माननीय सदस्य अखबार दिखा–दिखा कर कह रहे थे कि सिरसा में यह हो गया और वह हो गया।

इसलिए, मैडम, मैं यह जानना चाहती हूं कि ये यहां अखबार डिसकस कर रहे हैं या बजट?

चौ. ओम प्रकाश: उनको टाईम की जरूरत नहीं है। आप उनको सीट पर बुला लीजिए, चेहरे के उतार–चढ़ाव से पता चल जाएगा। (विघ्न)

उपाध्यक्षा: देखिए, मैं चाहती हूं कि यह औगस्ट हाउस अच्छी तरह से और रैगुलर तरीके से चले। मैं नहीं चाहती कि कोई इर–रैगुलर चीज हो। इसलिए मैं चाहूगी कि जो भी यहां बोले वह मेहरबानी करके रैलेवैन्ट बोले। मैं यह भी चाहूंगी कि बीच में कोई इंट्रप्शन न हो। आप भी ओम प्रकाश जी रैलेवैन्ट बोलें और बजट के ऊपर बोलें। मैं हाउस को इन आर्डर रखना चाहती हूं, डिस–आर्डर में नहीं रखना चाहती। अगर आनरेबल मैम्बर इस तरह से बोलते रहे तो मैं उनको बोलने नहीं दूंगी।

Sh. S.P. Jaiswal: On a point of Order, Madam. While speaking on the 'General Discussion on the Budget', it is permissible for the Honourable Members to make a general survey and criticism of the Administration. And, at the discussion stage, there is no bar. You cannot stop or restrict them. This is one of the main attacks which the oppostion can make. This is also consistent with the Parliamentary Proctice.

उपाध्यक्षा: हर मैम्बर बजट पर बोलते हुए सरकार का क्रिटिसिज्म कर सकता है परन्तु पर्सनल क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता।

चौ. दल सिंह: डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप टाईम हमारा काटेंगी लेकिन आप इतना ख्याल रखें कि आप कितना टाईम लेती है।

उपाध्यक्षा: मैं क्या करूं। आप मुझेसे कहलवाते हो। (विघ्न)

चौ. ओम प्रकाश: उपाध्यक्ष महोदया, मैं जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर बोल रहा था और इनको बता रहा था कि किस तरह का रोल हमारी पुलिस का उन दिनो में रहा जबकि यह सारा देश एक मन में अपने देश की सीमाओं की रक्षा करने पर तुला हुआ था। सारे अपोजीशन के मैम्बरान और मुल्क का हरेक नागरिक प्राणों की आहूति देने के तैयार था। मेरा कहने का मतलब यह है कि जहां इस मुल्क के 55 करोड़ लोगों की यह हालत थी वहां इस सरकार के सदस्यों, हमारे मुख्यमंत्री, सरकारी कर्मचारियों और पुलिस के अफसरान की भी कुछ जिम्मेवारी थी। उन्हें भी नैशनल इंटीग्रेशन का सबूत देना चाहिए था। डिप्टी स्पीकर साहिबा, और मैं क्या बताऊ? आप फिर कहेंगी कि मैंने नाम ले दिया। 7, 8, और 9 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री सिरसा सब–डिवीजन के दौरे पर गए और मुझे हैरानी हुई इनकी तकरीर सुनकर जब इन्होंने कहा कि इलैक्शन कल भी हो सकते हैं और इलैक्शन एक साल के बाद भी हो सकते हैं लेकिन इंदिरा गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार के मुकाबले में यदि कोई और आपसे वोट मांगता है तो उसे चीन, पाकिस्तान और अमेरिका का एजेन्ट

समझिए। अजीब तमाशे की बात है कि इंदिरा गांधी कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टीज को चीन, पाकिस्तान और अमेरिका का एजेन्ट तसव्वर किया जाए। हमारे मुख्यमंत्री महोदय को यह समझ ही नहीं कि कोई चीज कहां और किस ढंग से कहनी चाहिए। पिछले सैशन में भी उन्होंने बुरी तरह से हमारे एक सम्मानित सदस्य को अमेरिका और चीन का एजेन्ट जाहिर करने की कोशिश की थी। उन्हें पता नहीं है कि ऐजन्ट की क्वालिफिकेशन क्या हुआ करती है। उपाध्यक्ष महोदया, यह था हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और हमारी सरकार का हाल और आज भी उसी ढंग से एक चीज इनके दिमाग में घर किए हुए है कि पुलिस के डंडे से ये हरियाणा के एक करोड़ लोगों को काबू कर लेंगे और इलैक्शन में फतह प्राप्त करेंगे, जिस तरह से मास्टर बनारसी दास गुप्ता ने दावा किया था। मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि जब नया इलैक्शन होगा, लोगों के सामने ये जाएंगे, लोगों की दुखती रग पर हाथ रखेंगे तो लोग इन्हें बताएंगे कि इन्होंने इस अर्से में लोगों के साथ क्या सलूक किया। जहां तक इलैक्शन में जीतने के दावे का ताल्लुक है, मैं कहता हूं कि यदि आज भी इस हरियाणा की 65 असैम्बली कंस्टिच्युऐंसीज में किसी एक से मुख्य मंत्री जी चुनाव लड़ लें तो आटे दाल के भाव का पता चल जाएगा। उपाध्यक्ष महोदया, यह तो ऐडमिनिस्ट्रेशन का हाल था, अब मैं इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ आऊंगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया, हरेक गांव को इलैक्ट्रीफाई करने का दावा किया जा रहा है ओर बताया जा रहा है कि हमने इलैक्ट्रिसिटी देने में बड़ा चमत्कार किया है। चमत्कार तो सचमुच, बड़ा किया है क्योंकि इसमें करोड़ों रूपया कमाया गया और इसके सबूत के तौर पर मै। आपको बताऊं कि फरीदाबाद में पुराना थर्मल प्लांट लगा हुआ था जिसकी जगह 60 मैगावाट का एक नया प्लांट लगाया जा रहा है। उस पुराने थर्मल प्लांट के सामान को उठवाने के लिए बोलियां लीं ओर चार फर्मो ने बिड दी। एक ने 14 लाख, एक ने 13 लाख एक ने साढे बारह लाख और एक ने बारह लाख की। सबसे कम बोली देने वाली फर्म को बारह लाख में वह ठेका दिया गया। इससे सीधा दो लाख का नुकसान स्टेट को हुआ। यही नहीं, उसके साथ शर्त यह नत्थी हुई थी कि सामान 6 हफ्ते के अन्दर–अन्दर उठा लिया जाए लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि वह सामान एक साल तक नहीं उठाया गया। यह हालत तो हमारे इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की है। मैं इसके विषय में आपसे क्या–क्या बताऊं जितना कहा जाये उतना ही थोड़ा है। उपाध्यक्ष महोदया इस सरकार का नया सामान खरीद कर पेट नहीं भरा तो इन्होंने एक नयी चीज शुरू कर दी है। पहले के जो ताम्बे के तार लगे हुए थे उनको उतार कर अब घटिया दर्जे के तार लगाने शुरू कर दिये हैं। अब उनको बेचकर अपना पेट भरना चाहते हैं। जो कुछ पहले कर चुके थे उससे भी इनका गुजारा नहीं हुआ। जो कुछ पहले अच्छा हुआ था उसको भी अब बुरा करने की कोशिश कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं किस–किस के मुताल्लिक जिक्र करूं। हरियाणा इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड के चेयरमैन को सारा हरियाणा और पंजाब जानता है कि वे किस प्रकार के आदमी हैं। इसी प्रकार से इस सरकार ने इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड में एक मैम्बर लगाये हुए है, श्री देवी प्रसन्न। जिनकी क्वालीफिकेशन अन्डर मैट्रिक है। पहले वे भिवानी आई.टी.आई. में होते थे, वहां से वे बरखास्त हो गये थे। यह अनपढ़ व्यक्ति आज ग्रेजुएट के इन्ट्रव्यू लेकर उनको सर्विस देता है। उनका अपना भांजा .....(शोर)

गृहमंत्री (श्री के.एल. पोसवाल): उपाध्यक्ष महोदया, जो व्यक्ति इस हाउस में मौजूद नहीं है और अपने को यहां पर डिफेन्ड नहीं कर सकता है उसका नाम नहीं लिखा जाना चाहिए।

Deputy Speaker: I would request the Hon. Member, not to mention the names here.

चौ. ओम प्रकाश: यदि आप कहती हैं तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। इसी तरह से हमारे एक बुजुर्ग मेम्बर हैं जिनकी उम्र 65 साल है। उनको भी इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड का मेम्बर लगाया हुआ है। कायदे कानून के मुताबिक तो साठ साल तक ही किसी को मुलाजिम किया जा सकता है परन्तु इन्होंने उसको यंग–ब्लड कह करके मैम्बर बनाया हुआ है। इसी 65 साल के मैम्बर को यंग–ब्लड कह कर कांग्रेस पार्टी का इलैक्शन लड़ने के लिए टिकट भी दिया जा रहा है (शोर)।

तीसरे मैम्बर हैं, जो हमारे पहले चीफ इंजीनियर हुआ करते थे। मैं उनका भी नाम नहीं लेना चाहता हूं। उन्होंने 12 लाख रूपये से बम्बई में एक कोठी खरीदी है। मेरे पास उस कोठी की फोटो भी मौजूद है। उस फोटो में उसके परिवार के सारे सदस्य भी खड़े हुये हैं। इस किस्म की धांधली इस ढंग से यहां पर बरती जा रही है। जहां तक कुरप्शन का सम्बन्ध है उसके विषय में तो आपसे क्या बताऊं बहुत ही कुछ कहा जा सकता है। अगर आप इजाजत दें तो मैं उस मेमोरेन्डम की, जो अपोजीशन के मैम्बरान की ओर से राष्ट्रपति को पेश किया गया है, शुरू की दो लाइनें और एक आखिरी लाई पढ़ देता हूं। उन्हीं लाईनों से सारा मैमोरेन्डम पढ़ा हुआ तसव्वर किया जाये। उन लाइनों से ही लोगों को पता चल जायेगा कि यहां पर कितनी कुरप्शन है।

Deputy Speaker: The Hon. Member cannot read anything in the House.

चौ. ओम प्रकाश: मैं आपकी हिदायत से बाहर नहीं जांऊगा। मैं इसे हाउस की टेबल पर रखता हूं और इसे पढ़ा हुआ समझा जाये। (शोर)

Deputy Speaker: Without my permission how can it be placed on the Table of the House? (Interruptions nad noise)

Ch. Jai Singh Rathi: It can be laid. This is provided in teh Rules here.

Deputy Speaker: I will see the Rules if it is provided in them. But I am not allowing it.

चौ. ओम प्रकाश: उपाध्यक्ष महोदया, आप गुस्से में हो जाती है और मेरा कीमती समय जाया हो जाता है। (विघ्न) क्योंकि हाउस फिर दोबारा तो बैठता नहीं (विघ्न) और मैं जिनके मुताल्लिक यहां कह रहा हूं उन्होंने दोबारा चुनकर आना भी नहीं है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, अब मैं एजूकेशन की तरफ आता हूं। यहां पर और बाहर जनता के सामने बड़े दावे किये जाते हैं कि हमने बहुत स्कूलों को अपग्रेड कर दिया लेकिन आज स्कूलों की हालत यह है कि वहां पर पूरा स्टाफ भी नहीं है। गवर्नमैंट टीचर्ज का जो हाल है वह तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उनके खिलाफ तो यह सरकार जब से आयी है तभी से है। अभी थोड़ी देर पहले सन्त दरद्वारी लाल जी ने टीचर्ज का जिक्र किया था कि उनकी बहुत बुरी हालत है। उपाध्यक्ष महोदया, जिस मुल्क का शिक्षक ही नाराज हो, जिससे हम तालीम हासिल करते हैं, जो देश के बनाने वाले होते हैं, उसके दुखी होने से उस देश का कल्याण नहीं हो सकता। इसी प्रकार से हमारी स्टेट की हालत है। सभी टीचर्ज का तो कसूर नहीं है, जिन्होने मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कोई बात की है उनके खिलाफ एक्शन लेते। कुछ थोड़े से कसूरवार टीचर्ज की वजह से चालीस हजार टीचर्ज को क्यों सजा दी जाये।

यहां पर यह कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट से चालीस लाख रूपए का हर महीने मुनाफा होगा। मुनाफे का अन्दाजा तो आप

इसी से लगा लगा सकते है कि जो टीचर्ज अपने घरों से दूर बैठे हुए हैं उनको महीने में एक बार तो जरूर घर आना पड़ता है। इसलिए चालीस हजार टीचर्ज हर महीने आठ लाख रूपया सरकार को किराये के रूप में देते हैं। शिक्षक तो इस देश का बिल्डर है। मास्टर बनारसी दास गुप्ता आप तो प्राइमरी स्कूल में मास्टर भी रहे हैं।

Deputy Speaker: Please address the Chair and not Sh. Banarsi Dass Gupta.

चौ. ओम प्रकाश: उपाध्यक्ष महोदया, अभी मैं ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा था। जब यह सरकार कहती है कि ट्रांसपोर्ट में मुनाफा हो रहा है तो फिर वहां पर टैक्सिज क्यों बढ़ाये जा रहे हैं। इस सरकार का तो यह वतीरा रहा है कि हर बजट में पहले लोगों की वाह–वाह हासिल कर लेती है और जनता के सामने कहती है कि हमने कोई नए टैक्सिज नही लगाये। बाद में आर्डीनेन्स के जरिए टैक्सिज लगा दिये जाते हैं। (घंटी की आवाज) अभी थोड़ी सी देर में मै। अपनी स्पीच खत्म कर देता हूं। इस सरकार ने सन् 1969–70 में बसों का किराया तीन फीसदी बढ़ाया था और पिछले चार साल के अन्दर इस सरकार ने चालीस से सौ फीसदी तक मार्किट फीस बढ़ायी है। बिक्री टैक्स तीन फीसदी बढ़ाये है और दूसरे टैक्सीज भी 6–7 फीसदी तक बढ़ाये है। मनोरंजन टैक्स भी चालीस से पचास फीसदी तक बढ़ाया है। लाउड स्पीकर पर कोई अढ़ाई गुना टैक्स बढ़ाया है।

इस प्रकार इस सरकार ने पांच करोड़ के नये टैक्सिज आर्डीनेन्स की शक्ल में लगाए हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बजट पेश करते समय तो जनता की वाह–वाह हासिल कर लेते है और उसके फौरन बाद टैक्स आर्डीनैन्स के जरिए लगा देते हैं। (घंटी की आवाज)

उपाध्यक्ष महोदया, मैं ज्यादा समय न लेता हुआ इतना ही कहूंगा कि इस सरकार ने अपने समय में बहुत ही बेकायदगी की है। इस सरकार ने अपोजीशन के लोगों को अपने मैजोरिटी के बलबूते पर कुचलने की कोशिश की है। इन्हें इस बात का ध्यान होना चाहिए कि अपोजीशन इस तरह से नहीं कुचली जा सकती। जहां याहिया खां ने मुजीब क लिए कब्र खोदी थी आज उसी कब्र में याहिया खां को दफनाया जायेगा। इसी तरह से मुख्यमंत्री श्री बंसी लाल ने ऐसा करने की कोशिश की है और वह भी उसी तरह से कुचला जायेगा। (अपोजीशन की तरफ से प्रशंसा)

श्रीमती प्रसन्नी देवी (इन्दरी): बहिन ओम प्रभा जी ने जो बजट हाउस में पेश किया है उसको पढ़ने से ऐसा महसूस होता है कि यह बहुत ही अच्छा बजट है। जिस प्रकार पिछले सालों में हरियाणा की मौजूदा सरकार ने विकास कार्यो को बहुत तेजी के साथ किया है उसी प्रकार से इस बजट से भी यही महसूस होता है कि हरियाणा की तरक्की, हरियाणा का विकास बहुत तेजी के साथ होगा। डिप्टी स्पीकर साहिबा, साढ़े तीन साल, पौने चार साल के अर्से में हरियाणा प्रदेश जिस तेजी के साथ

आगे बढ़ा है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। किसी एक क्षेत्र में नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। विरोधी दल के भाइयों के पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है सिवाए इसके कि खम्भों में पैसे खा गये, फलां चीज को ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। विरोधी दर के भाइयों की सरकार आठ महीने चली। आठ महीने के दौरान सिवाए पलटा–पलटी के इन्होंनें जनता की भलाई के लिए कोई काम नहीं किया। कुछ भाई तो पैसा बनाते रहे और कुछ भाई जैसे जनसंघ के हैं इन्होंने पैसे कमाने के लिए सड़कें बांट ली थीं।

इन्होंने उस समय इस तरह की बातें की थीं। आज हमारे सन्त हरद्वारी लाल जी शिक्षा के बारे में बड़ी नुक्ताचीनी कर रहे थे उनको शायद अपना समय भूल गया है जब .....

Sh. S.P. Jaiswal: On a Point of Order. Madam, can an Hon. Member while speaking on Budget refer to the functioning of the Government in the previous years? I want your ruling, Madam.

Deputy Speaker: Yes.

Sh. S.P. Jaiswal: Madam, according to this Book (by Kaul and Shakdher) speakign about previous Governments, is outside the scope of discussion on the Budget.

Deputy Speaker: Reference can be made.

श्रीमती प्रसन्नी देवी: डिप्टी स्पीकर साहिबा, यहाँ पर हरद्वारी लाल जी कह रहे थे कि इस सरकार ने एजुकेशन में जो तरक्की की है, वह कुछ नहीं है। जबकि मौजूदा सरकार ने पिछले साल में 300 के करीब नये प्राईमरी स्कूल खोले हैं। 100 प्राइमरी से मिडल स्कूल और 100 मिडल से हाई स्कूल अपग्रेड किये हैं। हमें इनका समय भी याद है। हमारी कांग्रेस सरकार के समय जो स्कूल अपग्रेड किये गये थे इन्होंने उनको भी खत्म किया था और साथ ही स्कूलों में भी फीस भी लगा दी थी। इनके पास अच्छे काम करने के लिये तो टाईम नहीं था लेकिन जब हमारी सरकार काम कर रही है, तो उसे देखकर नुक्ताचीनी करते है। हमारी सरकार ने जब बिजली दी तो कहीं भी यहा नहीं देखा कि यह अपोजीशन का हल्का है या काग्रेस का हल्का है, उसने तो केवल हरियाणा की जनता को देखा है ओर तमाम इलाकों में कोई कमी नहीं छोडी और सबको बिजली दी है। इसी तरीके से हमने सड़कें भी बनानी है। अगले एक साल तक उनको भी यही प्रोग्राम है कि हरेक गांव को सड़क जायेगी, चाहे वह अपोजीशन का हल्का हो या कांग्रेस के किसी भाई का हल्का हो। मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे इन भाइयों को इतने विकास के काम और वह भी इतनी तेजी के साथ होने के बावजूद क्या शिकायत है। कुर्सी वाली शिकायत इनको हो सकती है, उसके लिये मैं आपको बता दूं कि वह न तो इन्हें मिल सकती है ओर न मिलने की कोई आशा है। मुझे इस सरकार का बजट देखकर बहुत खुशी हुई है। हमारी सरकार जिस तेजी से विकास के काम कर रही है, वह सराहनीय

है और उसका यह समय अपने आप में एक मिसाल होगा। आने वाली पीढ़ियां इसे अनुभव करेंगी कि गांव–गांव में बिजली और सड़कें पहुंचाने वाली कोई बढ़िया सरकार होगी !

डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक ऐसा टाईम भी था और उसे मैंने भी देखा है कि बहुत से ऐसे इलाके थे जहां पर पानी की बहुत मार होती थी और उस मार से छः–छः महीने आने–जाने का रास्ता नहीं मिल पाता था। दूसरी तरफ वह इलाका भी था जहां पर कि पानी की कमी की वजह से कई–कई फसलों तक अनाज का दाना भी देखने को नहीं मिलता था। हमें अपनी सरकार पर फख है कि कुछ थोड़े–बहुत इलाकों को छोड़कर बाकी में बाढ़ के पानी की समस्या काफी हद तक हल कर दी गई है। यही नहीं उन इलाकों में जहाँ पर लोग पानी की कमी के कारण अन्न के दाने–दाने को तरसते थे और अकाल पड़ते थे, ज्यादा नहीं तो कम से कम एक सावनी की फसल के लिये तो अवश्य पानी का इतजाम किया गया है।

चौ. दल सिंहः इन्दरी की भी बता दो !

श्रीमती प्रसन्नी देवीः फिक्र न करो, वह भी बताऊगी। डिप्टी स्पीहकर साहिबा, पीने के पानी की पहले यह हालत थी कि लोगों को पीने के लिये पानी या तो ऊंटों पर या फिर रेलगाड़ियों से लाना पड़ता था और वह भी कई–कई मील से लाते थे। आज हमें खुशी है कि जहाँ पर कभी पीने के पानी के दर्शक नहीं होते

थे, पीने का पानी मिल रहा है। पिछले साल जमुना कैनाल के पानी से बहुत दूर–दूर तक तबाही हुई और उसमें मेरा भी कुछ इलाका शामिल है। हमारी सरकार ने उसके लिये काफी जगहों पर काम शुरू कर दिया है लेकिन फिर भी मैं आपके जरिये सरकार से यह प्रार्थना करना चाहती हूं कि आने वाली बरसात से पहले जहाँ–जहाँ पर पानी ने फसलों की तबाही की है, वहाँ–वहाँ जरूर कोई न कोई इतजाम किया जाये। आपके जरिये एक और प्रार्थना मैं सरकार से करना चाहती हूं।

मेरे इलाके में बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर कि गरीब हरिजनो ने कस्टोडियन लैड खरीदी हुई है। बाढ़ आने से कई जगह तो जमीन ही कट गयी हैं और बहुत सी जगह फसलें खराब हो गई हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप एक ऐसा हुक्म जारी कर दे कि अगर कोई इस वजह से लगान वगैरा की किश्त ने दे सके तो उससे अगली फसल पर वसूल कर लिया जाये। जिन लोगों की जमीन कट कर बह गयी है उनके लिये किसी दूसरी जमीन का इंतजाम किया जाये। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मौजूदा बजट को देखने से यह पता चलता है कि अगर इसी ढंग से जनता की तरक्की के लिये हमारी सरकार काम करती रही तो वह दिन दूर नहीं, हालांकि अब भी हरियाणा दूसरे राज्यों की निस्बत गिने–चुने राज्यों में से एक है, जब हर चीज मे ंसबसे आगे होगा। मै। सरकार से एक ओर प्रार्थना करूंगी कि जो इलाके किसी भी तरह से पीछे रह गये हैं, उसकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाये।

जैसे हमारी सरकार ने बिजली के लिये और फिर सड़कों के लिये फैसला किया है उसी प्रकार मैं आशा करती हूं कि बाढ़ के पानी का भी इंतजाम किया जायेगा। पशु–पालन की दृष्टि से या जन–स्वास्थ्य की दृष्टि से जिन इलाकों में दूसरे इलाकों के मुकाबले कम ध्यान दिया गया है, उनको प्रायरिटी दी जानी चाहिए। इसके अलावा, हमारी मौजूदा सरकार ने एक और कदम सबसे अच्छा उठाया है। पहले तो किसानों को 20–20 और 30–30 मील दूर तक अनाज मंडियों में लाना पड़ता था और फिर भी उसका भाव खरीदने वाले पर निर्भर करता था कि वह उसे किस भाव पर खरीदे ! लेकिन आज हमें इस बात की खुशी है कि किसान का अनाज खराब नहीं होता, उसे सरकार खरीदती है। असर किसी किसान का अनाज बारिश से भी खराब हो जाये तो भी सरकार उस अनाज को खरीदती है और जगह–जगह पर, छोटे और बड़े लैवल पर, ऐसी मंडियां बनाई गयी हैं जो अनाज खरीदती हैं। इसमें किसानों को बहुत बड़ी सहूलियत मिली है। हिन्दुस्तान के 90 फीसदी लोग देहातों में बसते हैं और देहात में बसने वाले लोग ज्यादातर जमीन पर निर्भर करते हैं। इसलिये सरकार ने जो कदम उठाया है वह बहुत जरूरी था और बहुत अच्छा कदम है। इन शब्दों के साथ जो बजट वित्तमंत्री महोदया ने हाउस के सामने पेश किया है मैं उसकी सराहना करती हूं और उनको धन्यवाद देती हूं। इसके साथ ही अपोजीशन के भाइयों से यह प्रार्थना करती हूं कि अगर उनके पास सराहना करने के लिये

कोई चीज नहीं है तो कम से कम अपने राज की बातें याद करके चुप तो रहने का कष्ट करें क्योंकि इसी में उनका फायदा है।

(इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

उपाध्यक्षा: श्रीमती शकुन्तला जी।

चौ. दल सिंह: डिप्टी स्पीकर साहिबा, बोलने का तो पहले भी मेरा टाईम था लेकिन जब आपने उन्हें अलौ कर दिया था तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बोल लें।

उपाध्यक्षा: अब तो मैंने नाम ले दिया है, उनको दो मिनट के लिये बोलने दें।

श्री भगवान दास सहगल: डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप भी अम्बाले की हैं और मैं भी अम्बाले का हूं। हमें भी तो टाईप दीजिये। हम अम्बाले वाले तो बोलने से रह गये हैं। हम भी हरियाणा में रहते हैं। हमारा भी तो कुछ कहने का हक है।

उपाध्यक्षा: जब किसी को टाईम दे दिया गया है, तो आप सबको आब्जैक्शन नहीं होना चाहिए। (शोर)

श्रीमती शकुन्तला (साल्हावास एस.सी.): उपाध्यक्ष महोदया, आप इन्साफ की चेयर पर बैठी हैं और आपके सामने

अभी–अभी समय का बहुत ज्यादा तकाजा, अपोजीशन की तरफ से हुआ है। सभी कहते है कि हमें टाईम मिलना चाहिए। मेरा भी यही ख्याल है कि वाकई अपोजीशन के मैम्बर्ज को टाईम मिलना चाहिए। आपको यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए।

उपाध्यक्षा: यह बात आप मेरे ऊपर छोड़िये।

श्रीमती शकुन्तला: उपाध्यक्ष महोदया, मैं सिर्फ इतना ही कहती हूं कि आइन्दा इस बात का ध्यान रखा जाये। यह बजट की किताब रखी हुई है जो बहिन जी ने कल हाउस में पेश की थी। इसके अन्दर सब बातें लिखी हुइ हैं। इनकी तरफ से आपने काफी सदस्यों को सुना भी है। मैं यह कहना चाहती हूं कि इन्होंने तो सब के गले में ढोल बाँधा हुआ है कि डम–डम करते रहो और नाच करते जाओ। यह सारी बातें जो यहाँ पर मैम्बर्ज ने कहीं, वही बातें कल बहिन जी ने सबको पढ़कर बतायीं थीं कि इसके अन्दर जो कुछ लिखा हुआ है वह यह है और ठीक है!

डिप्टी स्पीकर साहिबा, उन सब लोगों को बुलवाने से क्या फायदा है। यह तो सब

3.00 P.M.

एक ही बात बोलते हैं। जब मैंने इस बजट को पढ़ा तो मुझे बहुत ज्यादा दु:ख हुआ कि ऐसे अनुचित समय के अन्द और इतनी जल्दबाजी में इस बजट को रखने का फायदा क्या है। जब इस बजट को रखेने में अभी दो महीने का समय है फिर इस जल्दी के

अन्दर यह बजट कयों लाया गया। इस बात को सोचते हुअए मेरा ध्यान अपने देश और अपने हरियाणा प्रदेश की तरफ गया। आज हरियाणा के अन्दर और खासकर मेरे हल्के के अन्दर दो–चार गांव तो ऐसे हैं जहां कि हंडरेड परसेन्ट लोग फौज में हैं ओर बड़े–बड़े ओहदों पर हैं। अगर आप हमरे हल्के में जाएं तो उनके घर जाएं तो बाहर से ही पता चल जाएगा कि इस गावं के अन्दर बहुत ज्यादा शोक मनाया जा रहा है और दुख और शोक मनाने की बात भी है। आज ऐसे कितने घर हैं जो सुने हो गए हैं। जो शोक होता है वह दिन के अन्दर से होता है। लेकिन यह लोग ऐसे अनुचित समय में, जबकि पाकिस्तान ने हमारे देश के ऊपर हमला बोल दिया हमारे ऊपर लड़ाई थोप दी है, बजट पेश कर रहे हैं। यह ठीक है कि हारे बहादुर जवानों ने अपनी हिम्मत से और दिलेरी से पाकिस्तान के हमले को नाकाम कर दिया और इस प्रकार से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और हमारी विजय हुई। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि इस लडाई के अन्दर हमारी हानि नहीं हुई। हमारी करोड़ों रूपए की हानि हुई है, हजारों जवानों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, हजारों घर सूने हो गए हैं। अगर ऐसे समय के अन्दर कोई राजनैतिक पार्टी इस चीज का सहारा लेकर और जल्दबाजी के अन्दर कोई कदम उठाए तो मैं यह कहूंगी कि यह कोई अच्छा कदम नहीं है। इस आपत्ति के समय जबकि देश पर अभी खतरा है, और आपने देखा होगा कि हमारी प्राईम मिनिस्टर जहां कहीं भी जाती हैं वह अपने भाषण में यही कहती हैं कि अभी खतरा टला नहीं है, हमारी

सेनाएं सीमाओं से नहीं हटेंगी। फिर भी ऐसे समय के अन्दर यह राजनैतिक हवा देखते हैं। यह लोग पता नहीं हवा में देखते रहते हैं, पता नहीं यह किस हवा में उड़ते है, पता नहीं यह पार्टी हवा में ही उड़ती रहती है याह सिर्फ हवा में ही रहती है। अगर इन्होंने चार साल के अन्दर कुछ काम किया है तो इनको हवा को देखने की क्या जरूरत है।

श्री प्रभु सिंह: यह सबको देखते रहते हैं (शोर)।

श्रीमती शकुन्तला: आपको कोई नहीं देखता (शोर)।

श्री प्रभु सिंह: डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह बजट पर बोल रही है या मेरी आंखो की तरफ देख ही है। (शोर)

श्रीमती शकुन्तला: किसी सुन्दर चीज को देखा जाता है। भद्दी आंखों को कौन देखता है। भगवान ने आपको सुन्दर बनाया ही नहीं। आपकी तरफ कोई नहीं देखता। सुन्दर चीज को देखा जाता है भद्दी चीज को नहीं। (शोर)

श्री ओम प्रकाश गर्ग: आन ए प्वांयट आफ आर्डर, ***** (शोर)।

श्रीमती शकुन्तला: मुझे यह चार आंखे पसन्द नहीं है। (शोर)

एक आवाज: डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह शब्द एक्सपंज करा दिये जाएं।

उपाध्यक्षः ''यस'' यह जो प्वांयट आफ आर्डर था यह एक्सपंज होना चाहिये।

श्रीमती शकुन्तलाः उपाध्यक्ष महोदया, मैं यह कह रही थी कि यह बजट उचित सम के अन्दर नहीं रखा गया है। ऐसे समय में तो हमें अपने देश की रक्षा के लिए काम करना चाहिए। ऐसे समय में हमें अपने राज्य को कायम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, यह वह समय नहीं है। आज हमारे देश की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हमें उन बहनों या भाईयों के लिए अधिक से अधिक काम करना चाहिए जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए हमारी रक्षा के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं, जिनके घर सूने हो गए हैं, या जो हमारे फौजी भाई अपाहिज हो गए हैं। नका हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। इस बजट के अन्दर उन भाईयों के लिए कोई जिक्र नहीं है कि उनके लिए क्या किया जा रहा है। शुरू में थोडा सा लड़ाई का जिक्र जरूर किया है .....

वित्त मंत्री (श्रीमती ओम प्रभा जैन): बहन जी, इसमें सब कुछ लिया हुआ है आप पढ़ें तो सही।

श्रीमती शकुन्तलाः बजट में यह होना चाहिए कि हम उनकी क्या मदद कर रहे हैं।

उपाध्यक्षाः बजट में यह सारी बातें हैं आप बजट स्पीच पढ़ तो लें।

श्रीमती शकुन्तला: मैंने इसको पढ़ लिया है। इसमें कुछ भी नहीं है (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, मैंने यह सारी स्पीच पढ़कर देखी है। यह जो लड़ाई पाकिस्तान के साथ हुई है, यह जो युद्ध हुआ है उसमें कितने जवान मारे गए, कितने रूपए की हानि हुई, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं।

श्रीमती ओम प्रभा जैन: इसमें सब कुछ दिया हुआ है कि हम कितनी उनकी मदद कर रहे हैं आप पढ़ने की कोशिश तो करें।

श्रीमती शकुन्तला: मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। एक–एक जवान की कितनी हानि हुई है, करोड़ों और लाखों रूपए की हानि हुई है और आप उनको चार पैसे दें, पच्चीस पैस दें यहा कोई मदद नहीं है।

*Expunged as ordered by the Chair.

श्रीमती ओम प्रभा जैन: आप पेज 36 के पैराग्राफ को देख लें। इसमें सब कुछ दिया हुआ है।

श्रीमती शकुन्तला: उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान इस बजट की और दिलाना चाहती हूं। इनको हकूमत करते हुए चार साल हो गए हैं। जब हम पहले–पहले एम.एल.ए. बनकर आए थे तो हम यह समझते थे कि जो मिनिस्टर होते हैं यह चीफ मिनिस्टर होते है यह स्टेट के सारे हल्कों को चाहे वे अपोजीशन के हैं या अपनी पार्टी के हैं, उनको एक ही नजर से देखते हैं।

लेकिन हमारा वह अन्दाजा गल्त निकला। मैं अपने हल्के के बारे में कह सकती हूं कि वहां कुछ भी काम नहीं हुआ है। हां यह जरूर है कि इनके कागजों के अन्दर सारी कार्यवाही पूरी है। अभी बहन जी कह रही थीं कि पेज 36 पर लिखा हुआ है। मैं तो कहती हूं कि लिखा हुआ तो सब कुछ हैं, कागजी कार्यवाही सारी की सारी पूरी है लेकिन वास्तव में होता कुछ नहीं है। आप अपोजीशन मैम्बरों के हल्कों में जाकर देखिए तो वहां पर न नहर का काम हुआ है, न कोई अस्पताल का काम हुआ है और न शिक्षा का काम है जैसा यह कहते हैं कि हमने इतने स्कूल खोले, इतने स्कूल अपग्रेड किए हैं। मैं कहती हूं कि इन चार सालों के अन्दर मेरे हल्के के अन्दर कोई अस्पताल खेला हो तो खुरशीद अहमद जी बताएं।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री खुरशीद अहमद): हमने तो वहां मैटरनिटी वार्ड खोल दिया है। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला: मेरे हल्के में एक भी स्कूल अपग्रेड किया हो तो यह बताएं।

उपाध्यक्षा: आप कितना और टाईम लेंगी?

श्रीमती शकुन्तला: उपाध्यक्षा महोदया, अभी तो कुछ भी टाईम नहीं हुआ। मैं अभी बता रही थी कि अपोजीशन के मैम्बरों के हल्के में कुछ भी नहीं हुआ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं इस सरकार के और क्या–क्या कारनामे आपको बतलाऊं। जब कोई मिनिस्टर बन जाता है तो हम लोग समझते हैं कि यह लोगों को समानाधिकार देंगे। पर यहां पर हालत यह है कि हरिजनों के पास रहने के लिये मकान नहीं हैं और ये लोग खुद बड़े–बड़े बंगलों में रहकर ऐश कर रहे हैं। कहते हैं कि हम गरीबों के लिये कौलौनीज बना रहे हैं। आज हालत यह है कि जो हरिजन फर्स्ट क्लास जूते बनाकर देता है और मिनिस्टर साहब उनको अपने पैरों में सजाकर चलते हैं, उन गरीबों के अपने बच्चे नंगे पैरों घूमते फिरते रहते हैं। इसके अलावा जो हमारे किसान हैं, जो गेहूं पैदा करते हैं उनके खुद के खाने के लिए गेंहू नहीं है, यह तो मेहमानों के लिये है, इस बारे में अभी कल ही एक गुडगांव का रहने वाला आदमी मुझे बता रहा था। इस तरफ सरकार ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। इन गरीबों की तरफ भी सरकार को ध्यान करना चाहिये। इसी तरह से आप मकान बनाने वाले राज, मिस्तरी को देखिए, उन बेचारों के खुद के पास रहने के लिये मकान नहीं है, झोंपड़ियों में बेचारे रहकर गुजारा करते हैं। जो लोग समग्लिंग करते हैं, रिश्वतें खाते है, वे तो मौज कर रहे हैं और जो बेचारे मेहनत करते हैं, वे भूखे मरते है। यह सरकार जिसने गरीबी दूर करने का ठेका ले रखा है, इन्होंने कहा था कि हम समाजवाद लाएंगे, पर इन्होंने अभी गरीबों के लिये कुछ भी नहीं किया है। डिप्टी स्पीकर साहिबा जबसे इनकी सरकार बनी है, इन्होंने गरीब को और गरीब बना दिया है। इनके राज में गरीब आदमी की कहीं

भी सुनवाई नहीं है जैसे कि अभी चौधरी ओम प्रकाश जी ने एक केस बतलाया था। (शोर) (हंसी)

देखिये डिप्टी स्पीकर साहिबा, यहां पर ट्रेजरी बैन्चिज की तरफ से हंसी हो रही है। ये लोग मेरी बातों पर हंस रहे हैं, इनको तो शर्म महसूस करनी चाहिये कि वे क्या कर रहे हैं। वह वक्त कब आएगा जब हमारी सुनवाई होगी?

श्री प्रभु सिंह: कोई बात नहीं, किसी को इतना गर्व नहीं करना चाहिये दुनियां के आगे एक मिसाल है, याहिया खां जैसे जो प्रेजीडेंट बने बैठे थे, उसने कितने अत्याचार किये और मुजीब जैसे आदमी को काल कोठरी में बन्दर कर दिया लेकिन वह आ स्वयं काल कोठरी में बन्द है और मुजीब साहब आज बंगला देश के प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। इसलिये मैं कहती हूं कि ये लोग इतने घमंडी न बनें, इन लोगों को जरा ध्यान से काम करना चाहिये। हमेशा घमंडी का सिर नीचा रहता है। मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि सरकार को अपनी आपाधापी को छोड़ देना चाहिये और उन परिवारों के लिये काम करना चाहिये जिनके लाल इन लड़ाई में हमारी रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं। बस मैं यही कहती हुई अपना स्थान लेती हूं और आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे यहां बोलने का समय दिया।

(At this stage, a Member rose to speak.)

Deputy Speaker: One minute please. Kindly sit down. Sh. Om Parkash, when he was speaking, laid on the Table some paper, which I did not allow. There is a convention which I can quote before this august House.

"Generally speaking a private Member is not allowed to day a document or paper on the Table. He can, However, do so, if he is so authorised by the Speaker."

So, I did not allow that paper to be laid on the Table.

Ch. Chand Ram: This is on another subject, Madam.

Deputy Speaker: This is my ruling, Mr. Chand Ram.

चौ. जय सिंह राठी: मैडम डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपने तो दरम्यान का हिस्सा पढ़ा हैं आपने सारी बात नहीं पढ़ी। You have not red the whole of it. How is that connected with it?

Deputy Speaker: Please take your seat, मैं अपोजीशन में मैम्बरों को यह कहूंगी कि वे इस बात को बार–बार न बुलवाएं।

Sh. S.P. Jaiswal: Madam, Deputy Speaker, I am not being allowed to speak. I have risen a number of times.

Deputy Speaker: Members are being called according to the list given to me.

Sh. S.P. Jaiswal: I am not in that list. I am completely independent. So, if am not in that list, it does not mean that I should nto be allowed to speak.

महंत गंगासागर (झज्जर): हमारी वित्त मंत्री महोदया ने वर्ष 1972–72 का जो बजट पेश किया है, उस पर इस अगस्ट हाउस के सामने अपने विचार रखने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस बजट को पढ़ने से यह मालूम होता है कि यह बहुत ही प्रगतिशील बजट है और बहुत सोच समझ कर बनाया गया है।

चौ. जय सिंह राठी: मेरा प्वायंट आफ आर्डर है, मैडम। अभी–अभी आपने जो किताब पढ़ी है, उसको पढ़कर आपने कहा कि श्री ओम प्रकाश जी ने जो डाकूमेन्ट पेश किया था उसको मैंने हाउस में रखने की इजाजत नहीं दी है, वह कागज हाउस की प्रौपर्टी तो है नहीं वह मेहरबानी करके वापिस कर दिया जाए।

उपाध्यक्ष: मैंने तो उसी वक्त ही कह दिया था।

महंत गंगासागर: डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस समय जब हमारा देश एक बहुत बड़े सघर्ष से गुजर चुका है और जब हमारे राज्य को अभी पूरे तौर पर काम करने का अवसर मिला है, उस वक्त यह बजट आ रहा है। इसमें किसी भी नये टैक्स का न लगाया जाना यह साबित करता है कि हरियाणा राज्य की जो

सरकार है, वह जनता पर बगैर बोझा डाल हुए अपना काम चलाना चाहती है। कुछ विरोधी सदस्यों ने कहा कि यह सरकार आर्डिनेन्स के जरिये टैक्स लगाना चाहती है। यह उनकी भावना पहले से बनी हुई थी। यह गल्त बात है। पहले ही सरकार ने कोई गैर जरूरी काम नहीं किया है। विरोधी सदस्यों के ट्रांसपोर्ट के टैक्स व किरायों में बढ़ोतरी का जिक्र किया है पर मैं बता देना चाहता हूं कि किरायों मं बढ़ोतरी एक ही बार हुई हैं, बार–बार नहीं हुई है। पैसिंजर टैक्स भी इसलिये लगाया गया है क्योंकि बंगला देश के लिये हरियाणा सरकार ने सेन्टर को योगदान देना था। दूरे राज्यों के मुकाबिले में, हमारे राज्य में टैक्सों की गिनती ज्यादा नहीं है और जहां तक काम का ताल्लुक है, हमारी सरकार हिन्दोस्तान भर में प्रथम स्थान पर है।

चौ. चांद राम ने बिजली का जिक्र करते हुए कुछ दो गांवों का नाम लेकर कहा कि वहां पर बिजली नहीं दी गई है इसलिये हरियाणा में सौ फीसदी इलैक्ट्रीफिकेशन नहीं हुई है। मै। उनकी जानकारी के लिये अर्ज करता हूं कि यह जो उन्होंने आजादपुर का नाम लिया है अलाटीज की नई बसती है जिनको यहां पर जमीन अलाट की हुई है। कुछ लोगों ने वहां पर 10/15 झोपड़ियों को बनाकर टैम्परेरी रिहायश शुरू की है। वहां 11 के. बी. लाइन नजदीक से गई है और बिजली लग सकती है लेकिन आप जानते है। कि झोंपड़ियों में बिजली लगाना सेफ नहीं होता है इसीलिये वहां पर कोई सौ पचास लोग रह गये हैं और वे खुद

भी बिजली नहीं लेना चाहते हैं फिर न ही यह पूरे गांव के तौर पर है। दूसरे गांव की भी यही पोजीशन है। तो मैं अर्ज करता हूं कि असलियत कुछ और है लेकिन हाउस में कुछ और बताकर यह साबित करने की कोशिश करना कि हरियाणा में सौ फीसदी बिजली नहीं लगी है, सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है .....

श्रीमती शकुन्तला: आन ए प्वांयट आफ आर्डर। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आप से कहना चाहती हूं कि आप बातें सुन रही है लेकिन आप खुश मिजाज होकर सुनें और आप थोड़ा मुस्करा कर सुनें (शोर) मैं एक बढ़िया बात बताने लगी हूं मैंने अभी–अभी एक बात बताई थी आप ध्यान दें उस तरफ कि बिजली तो लगाई गौड़ साहब ने उसकी कार्यवाही की चेयरमैंन साहनी साहब ने .....

Deputy Speaker: This is no Point of Order. और मैं यह भी आनरेबल मैंबर से कहना चाहती हूं कि इस आगस्ट हाउस में प्रत्येक मैंबर को पार्लियामैंटरी प्रोसीजर का और मैनर्ज का पता होना चाहिये। You are talking to the Deputy Speaker who is in the Chair and I would like the Hon. Lady Member to know the Parliamentary manners. So while speaking with the Chair in future .....

चौ. चांद राम: डिप्टी स्पीकर साहिबा, वह अंग्रेजी समझती नहीं हैं इसलिये उनको अपनी भाषा में समझा दो। (हंसी)

Deputy Speaker: She understands it. I know it.

(Interruptions and noise)

श्रीमती शकुन्तला: मैं नहीं समझी कि आपने क्या कह दिया है।

Deputy Speaker: Please take your seat. (Interruption) Please sit down मैं लेडी मैंबर से कहना चाहती हूं कि उनको यहां बैठने और बोलने से पहले इन फयूचर, हाउस का कायदा और कानून जो होता है वह सीखना चाहिये। जो प्वांयट आफ आर्डर किया जाये वह रूल्ज के मुताबिक होना चाहिये यह नहीं कि प्वांयट आफ आर्डर कह कर जो कुछ मन में आया बोल दिया। जब कोई मैंबर रैलेवंट बोल रहा हो तो इस तरह बीच में उठकर इनट्रप्ट करना उचित मालूम नहीं होता।

चौ. जय सिंह राठी: आन ए पांयट आफ आर्डर, डिप्टी स्पीकर साहिबा। आपने जो रूलिंग कोट किया था उसकी साइटेशन मुझे दें दें ताकि मैं भी देख लूं कि वह कौन सा रूलिंग है और वह कौनसी किताब है?

Deputy Spekaer: It will reach you.

Ch. Jai Singh Rathi: Within a couple of minutes.

Deputy Speaker: Yes.

महंत गंगासागरः डिप्टी स्पीकर साहिबा, बिजली का जिक्र मैं कर रहा था कि बीच में यह सब कुछ आ गया। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अगर कोई ऐसी बात है तो कभी भी सरकार से प्रार्थना की जा सकती है कि फलां जगह जरूरत है और जहां जरूरत है ट्रांसफारमर लग सकात है इसमें दिक्कत की बात नहीं। ऊपर से कई सदस्यों ने कहा कि बिजली की तारें हैं लेकिन उनमें बिजली नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहिबा एक साल में कोशिश करके सौ फीसदी बिजली लगाई जाये यह बहुत बड़ा कार्य होात है। हमें अपने घरां में बिजली लगानी होती है तो भी एक दो महीने पूरी परह के काम करने में लग जाते है और सारी स्टेट को कवर करना एक बड़ा भारी मसला होता है। अगर थोड़ी बहुत खामियां मेनटैनेंस में हैं तो उसके लिये बोर्ड ने काम शुरू किया हुआ है ओर वे दिक्कतें दूर होती हा रही हैं जैसे कि हमें अपने यहां तजरूबा हो चुका है। इस तरह की बातें करना बेमतलब की नुक्ताचीनी वाली बात हैं जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि ला एंड आर्डर के मामले में हरियाणा सारे भारत में पहले नम्बर पर है। यहां पर किसी तरह की कोई एजीटेशन नहीं हालांकि इन्होंने पैदा करने की कोशिश की भी है। आगमैंटेशन कैनाल करनाल की तरफ बन रही है। आप देखें कि एक तरफ तो जनता की तरफ से मांग है कि पानी बढ़ाया जाये जैसे कि हमारे रोहतक के बारे में जिक्र आता है कि वहां पानी की कमी रहती है ओर इसके साथ यह भी दिक्कत रहती है कि किसी जगह वाटर लागिंग की वजह से जमीन खराब होती है तो कहीं

ऊंची जगह होने की वजह से पानी पहुंच नहीं सकता इसलिये जब तक नहर की आगमैंटेशन न की जाये यह दिक्कत दूर नहीं हो सकती लेकिन जब सरकार ने इस तरफ तवज्जुह दी और काम शुरू कराया तो हमारे कुछ मैंबर साहिबान ने करनाल जिला के उन एरियाज में एजीटेशन कराने की कोशिश की ताकि नहर आगमैंट न हो सकने से सरकार की बदनामी हो। मैं इसे ओछा हथियार की कहूंगा और इससे अच्छा तथा एप्रोप्रिएट लफ्ज मुझे ओर मिल नहीं सका है जो इस्तेमाल करूं। इस तरह से एक तरफ तो जनता का नुकसान करना और दूसरी तरफ सरकार के खिलाफ झूठी किसम का प्रापोगंडा करना ठीक बात नहीं, ओठी बात ह। लेकिन जनता सब कुछ समझती है। जनता तो काम चाहती है और अगर काम नहीं होता तो वह पसंद नहीं करती। यहां पर शहीदों का जिक्र आया है। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि आज जो भारत को दुनियां में ख्याति प्राप्त हुई है यह इन शहीदों के बलबूते पर मिली है और हमारे जवानों ने जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है उसकी बदौलत मिली है। यहां कहा गया है कि बजट में उसका जिक्र नहीं है। अगर वह गौर से देखें तो उनको पता होना चाहिये गवर्नर ऐड्रेस के सबसे पहले सफे पर यह चीज आई है। मुख्यमंत्री जी ने बार–बार सदन को आश्वासन दिया है कि हर बात में फौजी जवानों को प्राथमिकता दी जायेगी। इसलिये ऐसी बातें कहने से इनको कुछ मिलने वाला नहीं, अपना समय ही ऐसी निराधार बातें करके नष्ट करेंगे। हरियाणा में विकास के काम जोरों के साथ हो रहे हैं। सड़कें तो तकरीबन

60/70 फीसदी बन चुकी हैं और बाकी पर काम पूरे जोर के साथ जारी है। इसके अलावा छोटे–छोटे गांवों में भी बसें चलनी शुरू हो गई हैं और लोगों को यातायात के साधन मिल रहे है। नहरों में पानी की बढ़ोतरी हो रही है शकुन्तला जी ने जिक्र किया था कि उनके हलका में हस्पताल नहीं है। मैं कहता हूं बहन ही क्यों आप सही बात को छिपा रही हैं। झज्जर तहसील जिसमें हमारा दोनों को ही हलका है वहां पर बड़ा हस्पताल बन कर मुकम्मल हो चुका है और उसका वहां 10/15 दिन में उद्घाटन हो सकता है। सारा काम शुरू हो चुका है। तहसील लैवल पर हम सबके कामन हस्पताल हैं और इस तरह से हर गांव को तहसील लैवल पर भी सहूलितें मिल रही है।

आज स्कूलों की हालत स्टेट में काफी अच्छी है। जब ज्वांयट पंजाब में हम इकट्ठे थे उस टाईम को कौन भूला है। उस दिन ओर आज का मुकाबला करके देखें तो सारी तस्वीर सामने आ जाएगी। चार पांच साल के छोटे से अर्से के अन्दर हम कहां से कहां पहुंच गए है। आज हमें छोटे–छोटे गांवों में प्राइमरी स्कूल नजर आता है। अगर थोड़ा सा बड़ गांव हो तो उसमें मिडल स्कूल नजर आएगा। चार–चार, पांच–पांच, सात–सात मील के फासले पर हाई स्कूल मौजूद हैं। चौ. हरद्वारी लाल जी, जो आनरेबल सदस्यय हैं, उन्होंने एक बात कही कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है क्योंकि मास्टरों के लिए बहुत गलत पालिसी अख्तियार कर रखी है। इनके अलावा अभी–अभी किसी दूसरे आनरेबल

सदस्य ने, मुझे ध्यान नहीं रहा, यहां पर मास्टरों की वकालत की थी। इस तरह से वकालत करने से हम मास्टरों की कोई फेवर नहीं कर रहे बल्कि बे–मतलब अध्यापक वर्ग का पालिटिक्स में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। चौ. चांद राम भी हरिजनों की वकालत करते हैं। उन्होंने खाहमखाह अपने ही विरोधी सदस्यों की तरफ से ऐसी पोजीशन बना ली है जो ठीक नहीं। उन्होंने किसी अफसर को पालिटिक्स में घसीट करके उसकी बात कही कि सरकार ने उसके साथ धोखा किया हैं। उधर विरोधी सदस्य खड़े होकर उसी अफसर के खिलाफ कहने लगे जो मैं यहां पर कह नहीं सकता। जो कुछ उस विरोधी दल के सदस्य ने कहा वह ठीक नहीं। मैं समझता हूं कि किसी अफसर को पालिटिक्स में घसीट कर यह कहना कि सरकार उसके बारे में यह कर रही है, वह कर रही है, गलत चीज है, इस तरह उसका नुक्सान करते हैं। हम खाहमखाह ही खुशनूदी हासिल करते हैं, असल में हम तो उनका नुक्सान करते हैं। हमारे सरकारी कर्मचारी बड़ी सूझ–बूझ रखते हैं और अपने–अपने काम में पूरी योग्यता रखते हैं। अगर हम यह कहें कि फलां वर्ग ठीक काम नहीं कर रहा है तो उस वर्ग के साथ हम ज्यादती कर रहे हैं, यह ठीक बात नहीं है। अब आप हरिजन कल्याण की बात ले लीजिए। हालांकि वक्त की पुकार है कि हरिजनों के साथ कोई ज्यादती होने की बात नहीं हैं। हम देख रहे हैं, हरिजनों को हर जगह ऊंचा स्थान मिल रहा हैं। पंचायतों में जगह जगह पूरी परसैंटेज के लिहाज से और रिजवेंशन के लिहाज से उनको मैम्बरी मिलती है। यह सब हमारी

सरकार की और जनता की फराखदिली है। बहुत से भाई सरपंच बने हुए हैं, और कई ऊंचे पदों पर चले गए हैं, यह सब जनता की उदारता का सबूत है। अगर हम खाहमखाह इनकी वकालत करें तो फजूल बात है। हरियाणा मे ंएक रौ चल रही है जिससे कुछ भाई घबराते हैं। वह रौ यह है कि यहां पर हर जगह चारों तरफ डिवैल्पमेंट के काम जारी हैं। इनको नुक्ताचीनी करने के लिए कोई दूसरी बात मिल नहीं रही। अन्त में मैं यही कहूंगा कि वित्त मंत्री महोदया ने जो बजट पेश किया है यह बहुत उचित है, इसको पास किया जाए।

उपाध्यक्षा: मलिक चन्द गम्भीर बोलेंगे।

चौ. दल सिंह: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे टाईम नहीं लिा, मुझे भी बोलने का टाईम दिया जाए।

उपाध्यक्षा: जो मैंबर कभी–कभी बोलते हों उनको भी बोलने का टाईम देना है। मेरे पास लिस्ट है, इसमें इनका नाम लिखा हुआ है।

चौ. दल सिंह: यह तो धक्के शाही है (व्यवधान) मुझे टाईम मिलना चाहिए।

उपाध्यक्षा: आप बैठ जाइए, आपको पूरा टाईम दिया जाएगा।

डा. मलिक चन्द गम्भीर (यमुनानगर): डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने मुझे बोलने का समय दिया। सदन के सामने जो बजट पेश हुआ है इससे कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने हिन्दुस्तान पर एक हमला किया ओर उस हमले में हमारे हिन्दुस्तान के नौजवानों ने उनके दांत खट्टे किए। लेकिन इसके साथ ही साथ हमारे कुछ शूरवीर नौजवान अपनी कीमती जानें कुर्बान कर बैठे हैं। उन शहीदों के लिए हमारी सरकार ने कुछ सुविधाएं देने की बात कही है। लेकिन मैं समझता हूं कि अब जो युग आ रहा है, यह बदलता जा रहा है ओर अब वह समय नहीं रहा कि हर भगवे कपड़े पहनने वाले को नमस्कार करें। मिल्ट्री के भाई जो देश की रक्षा करते हैं, हमारी सेवाएं करते हैं, आज उनको पूजने का समय आ गया है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि सरकार इस किस्म के कानून बनाये, नियम बनाये ताकि मिल्ट्री के भाइयों को ज्यादा से ज्यादा सम्मान मिल सके क्योंकि सरकार ने बजट में उनको सुविधाएं देने की बात कही है। जहां तक ऐक्स–सर्विसमैन या उन लोगों का ताल्लुक है जो छुट्टी करके आ गए हैं, सरकार ने नौकरियां देने के लिए कहा है परन्तु उनके बच्चे जो सर्विस कर रहे हैं उनके लिए रिजर्वेशन का नाम तक नहीं लिया गया। जो हमारे भाई बुजुर्ग मिल्ट्री मैन सरहदों पर हमारी सेवा कर रहे हैं उनके बच्चों के लिए भी नौकरियों के अन्दर सुविधा होनी चाहिए।

एक बात मैं बसबसे आवश्यक कहना चाहता हूं। पंजाब गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन करके पंजाब सिक्योरिटी आफ लैण्ड टेन्योरज ऐक्ट को अमैंड किया है ताकि जो भाई मिल्ट्री में हैं उनकी जमीन सुरक्षित रह सके और उनके पीछे उनकी जमीन पर उनके मुजारे काबिज न हो सकें। वे तो मिल्ट्री में रहते थे और मुजारे काबिज हो जाते थे, इस चीज को दूर करने के लिए पंजाब गवर्नमैंट ने ऐक्ट में तरमीम की है ताकि उनकी जमीन मुजारों से खाली करवा ली जउए। हरियाणा सरकार भी इसी प्रकार का कोई कानून कोई आर्डिनैंस ऐक्ट में तबदीली करने के लिए जारी करे ताकि उन लोगों को सुविधाएं दी जा सकें।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस बजट में काफी कुछ कहा गया हैं। मैं थोडी सी बातें अपने हल्के के बारे में कहना चाहूंगा। रोड्ज के मुताल्लिक में विशेष रूप से कहना चाहूंगा। यह हर जगह महसूस किया जा रहा है, अनुभव किया जा रहा है कि रोड्ज को कब्र देने का जो कानून बनाया हुआ है वह ठीक नहीं है। रोड्ज का कब्र 500 से 1000 फुट तक के एरिए में दिया जाता है जिससे लोगों की बहुत सी जमीन कब्र में आ जीती है। लेकिन सैन्ट्रल गवर्नमेंट की रोड्ज कमेटी बनी हुई है, उनके रूल के मुताबिक 175 फुट का मोड़ दिया जाता है जिससे लोगों की बहुत सी जमीन बचाई जा सकती है। मैं समझता हूं कि सैंट्रल गवर्नमेंट की जो कमेटी बनी हुई है वह काफी काबिल और माहिर अफसरों की कमेटी है और हर बात का अन्दाजा लगा कर बनाई गई है।

इसलिए हरियाणा प्रदेश के रूल्ज और रेगुलेशन्ज को मदेनजर रखते हुए इस दिशा की तरफ ध्यान देंगे तो बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी। झगड़ा यही है कि एक मोड़ 500 से 1000 फुट के एरिए में देते हैं जिससे बहुत सी जमीन खराब हो जती है लेकिन सैंट्रल रूल्ज के मुताबिक इतनी जमीन नहीं आती। तो सरकार को भी ऐसे रूल्ज अपनाने चाहिए जिससे कम से कम जमीन मोड़ मे ंआए। इस बात पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए।

अब मैं हैल्थ डिर्पाटमेंट के बारे में अर्ज करता हूं। इसमें कोई शक नहीं कि हौस्पिटलज काफी बन गए हैं और बनने भी चाहिएं। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि जहां–जहां हौस्पिटलज बने हैं डाक्टर नहीं मिलते, अगर डाक्टर मिलते हैं तो दवाइयां नहीं मिलती। जमुनानगर के हल्के में दो हस्पताल बने हैं उनमें डाक्टर तो हैं लेकिन आप्रेटस नहीं है। जगाधरी में नया हस्पताल अप–ग्रेड हुआ है लेकिन बिल्डिंग ही नहीं बनाई गई। लोग तम्बुओं में पड़े हैं। जमुनानगर के हस्पताल की बिल्डिंग पहले ही म्युनिसिपल कमेटी ने बनाकर गवर्नमेंट के हवाले की है लेकिन वहां पर पूरी सुविधाएं नहीं हैं, डाक्टर भी नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस तरफ विशेष ध्यान दे।

जहां तक इरीगेशन का ताल्लुक है, जमीदारों को पानी देना चाहिए लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जमुनानगर का इलाका जिसमें से जमुना नहर निकाली गई है उस

इलाके के जमींदारों को पीन नहीं मिलता। एक इलाका जिसमें ऐ नहर खोदी गई हो और उसके इलाके के लोगों को पानी न मिले, यह बड़ी अफसोस की बात है। लोग बेचारे पानी के लिए तरसते हैं लेकिन नहीं मिलता। इन्होंने जो 50 मील लम्बी और 200 फुट चौड़ी नहर बनाई है उसके अन्दर लोगों की हजारों एकड़ जमीन खराब चली गई है। लोग अपनी जमीन के लिए तड़पते हैं। कुछ दिन हुए चौ. चांद राम और मैं वहां गए। हमने दखा किस तरह से लोग रोने लग गए ओर कहने लगे कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। कई एकड़ जमीन में तो भट्ठा लगा दिया गया और कुछ नहर के अन्दर आ गई। जिस जमींदार की चार एकड़ जमीन है उसमे ंसे एक एकड़ एक तरफ आ गई, एक एकड़ दूसरी तरफ आ गई तो आप बताएं उस गरीब को कितना नुक्सान हुआ। वह कैसे गुजारा करेगा। एक तरफ जमुना गुजरती है और दूसरी तरफ नहर गुजरती है। इनके बीच तकरीबन तीन मील का एरिया पड़ता है जिसको बहुत नुक्सान है। हमारी सरकार एक इलाके को खुशहाल करने के लिए दूसरे इलाके को तबाह करती है यह ठीक नहीं है। ठीक है, भगवान अगर हमें पानी देता है तो लीजिए लेकिन इसका यह मतलब नहीं है एक इलाके को खुशहाल करने के लिए दूसरे को तबाह कर दिया जाए। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से यह प्रार्थना है कि इस बात को ध्यान से सोये और इस पर विशेष ध्यान दे।

इसके साथ–साथ डिप्टी स्पीकर साहिबा, वहां जो टयूबवैल्ज लगाए जा रहे है वे एक हजार फुट गहरे और अठारह

इंच बोर के होंगे तथा 90 हौर्स पावर की मोटर उनमें लगेंगी जिससे वहां आलरेडी लगे हुए टयूबवैलों के पानी का लैवल नीचे चला जाएगा और इस टयूबवैल्ज के मालिकों को काफी नुक्सान होगा। इसलिए उनकी तरफ भी विशेष ध्यान देना चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारे प्रौविडैन्ट फंड कमिश्नर का जो दफतर है वह तीनों स्टेटों—चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब का कंबाइन्ड है। इसे रीजनल प्रौविडैन्ट फंड कमिश्नर के दफतर के नाम से अलग स्थापित करना चाहिए ताकि हमारी मिलों में काम करने वाले मजदूरों के फैसले आसानी से किए जा सकें। आजकल उनके केस काफी देर तक लटकते रहते हैं।

बसों के मुताल्लिक, डिप्टी स्पीकर साहिबा, यहां काफी कहा गया है। आगे से बसें कुछ बढ़ाई गई हैं, ठीक है बढ़नी भी चाहिएं लेकिन अभी भी बसिज के अन्दर सुधार की काफी आवश्यकता है। कुछ ऐसी बसिज चलती हैं जिनकी हालत बड़ी खस्ता है। मुझे आठ दस बसों में सफर करने का मौका मिला है। वेकभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंची बल्कि रास्ते में ही रह गई। ऐसी जो बसें चलतीं हैं उनके बारे में लोग यही सोचते रहते हैं कि आया ये वक्त से मंजिले मक्सूद पर पहुंचा सकेंगी या नहीं। तो इस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि लोग अपनी मंजिल पर ठीक ढंग से वक्त पर पहुंच सके।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरी कांस्टिच्युऐंसी जमुनानगर है जिसकी तरफ आजतक गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। ओवर–डैड ब्रिज का मसला दो साल से पास हुआ है, 31 लाख रूपयें सैन्कशन भी हुए हैं लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। वहां से गुजरने के लिए दो–दो, तीन–तीन घंटे इंतजार करनी पड़ती है। आपको यदि कभी वहां जाने का मौका मिले तो पता लगेगा कि वहां लोगों को कितनी दिक्कत है। इसका काम भी जल्दी शुरू किया जाना चाहिए।

वहां मंडी छोटी जगह बनी हुई है लेकिन वहां आजतक नई मंडी बनाने की कोशिश नहीं की गई। इसलिए मैं गवर्नमैंट से प्रार्थना करूंगा कि उस मंडी की तरफ खास ध्यान दें।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, ई.एस.आई. पैनल सिस्टम जगाधरी के अन्दर बंद कर दिया गया है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस सिस्टम को बंद करने से मजदूरों के अन्दर काफी दुःख फैला हुआ है और वे चाहते हैं कि हमारे यहां ई.एस.आई. पैनल सिस्टम को चालू रखना चाहिए। अगर गवर्नमैंट समझती है कि उसमें कमी है क्योंकि इसने दो डिसपैंसरियां वहां खोली हैं तो मेरा सुझाव है कि दोनों सिस्टमों को चालू रखा जाए। उससे भी पता लगा जाएगा कि कौन सा सिस्टम अच्छा है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपकी आज्ञा से, *अखबार की तीन कटिंग्ज जो कि मेरे पास हैं, सदन की मेज पर रखना चाहूंगा।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, अब मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए अपना स्थान लेता हूं, क्योंकि केवल इन बातों की ओर स्पैशली मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान दिलाना चाहता था।

चौ. चंदा सिंह (नीलोखेड़ी): माननीय डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारी खजना मंत्री ने जो बजट हमारे सदन में रखा है इससे प्रदेश की बहुत प्रगति होगी। जब से यह सरकार बनी है हमारी यही फाईनेन्स मिनिस्टर हैं और इनके बजट के बनाने के तरीके से हमारी स्टेट की काया पलट कर दी है। जीवन के हर शोअबा में निहायत तरक्की हुई है और यह प्रदेश हिन्दुस्तान भर में नम्बर एक पर आया है। हमने फोर्थ फाईव ईयर प्यान का निशाना आधे ही अर्से में पूरा कर लिया है। दूसरे प्रदेशों को सड़कें और बिजली जैसी चीजों को अपने पचास फीसदी लोगों को देने में अभी शायद दस साल लगेंगे लेकिन हमारे प्रदेश ने वही निशाना बहुत जल्दी पूरा कर लिया है। बिजली जैसी विज्ञान की इतनी बड़ी देन प्रदेश के हर गांव तक पहुंचा दी है। इस एक महकमे ने ही हरियाणा के प्रदेश को इतना बड़ा नाम दिया है जिसका कोई मुकाबला नहीं। कोई भी देश या स्टेट बगैर बिजली के आज के वैज्ञानिक युग में प्रगति नहीं कर सकता। डिवैल्पमेंट के लिए बिजली बहुत जरूरी है हमारे प्रदेश के अन्दर, डिप्टी स्पीकर साहिबा, हर क्षेत्र में ही प्रगति करने का प्रयत्न

*Not permitted by the Chair.

किया जा रहा है, केवल बिजली ही अकेली आईटम नहीं है। कहां पहले 20 हजार टयूबवैल और कहां अब 96 हजार टयूबवैल। बिजली की खपत तिगुनी ओर चौगुनी हो गई है। अन्य तमाम परियोजनाएं भी बड़ी तेजी के साथ पूरी की जा रही हैं जै बिजली के थर्मल प्लांटस का लगाना और व्यास सतलुज लिंक जैसी प्रशंसनीय स्कीम का पूरा करना। औगमैंन्टेशन कैनाल स्कीम भी डिप्टी स्पीकर साहिबा, लोगों के लिए बहुत फायदेमंद स्कीम है परन्तु मेरे दोस्त डाक्टर गम्भीर साहब ने कहा कि लोगों को व्यर्थ में ही उजाड़ा जा रहा है। वैसे तो डिप्टी स्पीकर साहिबा जनसंघ के सारे विधायक बड़े अच्छे हैं परन्तु इनके सोचने के ढंग में पता नहीं क्या फर्क है, वे देख नहीं सकते कि जिस जगह के ऊपर वे बसते हैं वहां कितना पानी का लेवल ऊपर आया है। अगर हम इनको इनके हाल के ऊपर छोड़ दें तो इस प्रदेश की सारी जमीन दलदल मे ंबदल सकती हैं इस औगमैन्टेशन स्कीम के चालू होने से पहले उस एरिया में बहुत कम फसलें उगती थीं और चना नाम की फसल तो उग ही नहीं सकती थी लेनिक आज वहां पर बहुत अच्छी फसलें ली जा रही हैं परन्तु इसके बावजूद भी ये देखे को अन–देखा करने की कोशिश करते हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमने आबपाशी, हैल्थ, ऐजुकेशन गर्जे कि हर क्षेत्र में तरक्की की है। आप ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की ही बात ले लीजिए, फोर्थ फाईव ईयर प्लान में हमारा टारगेट 27 लाख कुछ हजार टन का था परन्तु डेढ़ साल पहले ही उसे हमने 47 लाख और कुछ हजार टन, निशाने से कहीं ज्यादा पहुंचा दिया है। अकेले करनाल जिले

का इसमें बड़ा कंट्रिब्युशन है। टोटल प्रोडक्शन में, 72 परसैन्ट आलू में, गन्ने में 58 परसैन्ट, मक्की में 55 परसैन्ट और गेहूं में 35 परसैंट करनाल जिले का कंट्रिब्युशन होता है। तो इतनी ज्यादा तबदीली हमारे यहां हुई है। कहां पर दो लाख टन की पैदावार और कहां पर सन् 73 तक इसे 52 लाख टन कर देने की बात है? तो इर समस्या के साथ हम कोई सिसक–सिसक कर नहीं लड़ रहे हैं बल्कि तेज रफतार के साथ उसे दबाच लेते हैं।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, अब आप फ्लड समस्या को ही देख लीजिए। सरकार प्रताप सिंह कैरों सात–आठ साल पहले चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और सारे पंजाब के लिए उस समय 20 करोड़ की स्कीम बना करती थी। हम देखते थे कि लोग डैपुटेशन पर डैपुटेशन लेकर मालिया माफ कराने और तकावी हासिल करने के लिए आते थे मगर फिर भी कुछ नहीं होता था लेकिन हमारी सरकार ने इन तीन–चार सालों में लोगों को ज्यादा से ज्यादा चारा, बीज और तकावी मुहैया की है। आज एक आदमी की दिक्कत ऐसे उड़ी जा रही है जैसे सूरज निकलने से सारे का सारा अंधेरा दूर हो जाता है।

पशु पालन का काम भी बड़ी अच्छी तरह से यहां हो रहा है। हम तो समझते थे कि डेनमार्क और अमेरिका में ही अच्छे पशु हो सकते हैं लेकिन हरियाणा के अन्दर इस क्षेत्र में भी जो प्रगति हुई है उसने इस बात को झूठला दिया है! थोडे ही दिनों में वहां दूध या दूध से बनने वाली की चीजों चाहे वह मक्खन है,

पनीर है या कोई दूसरी चीज है कोई कमी नहीं रहेगी। गर्जे कि हरियाणा को जिस तरह पहले कहते थे कि यहां दूध की नदियां बहती थीं उसी तरीके से अब कुछ ही दिनों में यहां दूध की नदियां बहेंगी।

अब, डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप सड़कों को ले लीजिएगा। मैं बैठा–बैठा इताना खुश हो रहा था, जब हमारी वित्तमंत्री कह रही थी कि जिन गांव में आने–जाने के रास्ते नहीं थी उन गांव में सड़क प्रदान कर रहे हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं। अब तो हर गांव में बिजली होगी, सड़क जाएगी, उसके ऊपर बस चलेगी और इसके परिणामस्वरूप उन्नति की अथवा प्रौग्रैसिव विचारधारा गांवों तक जाएगी जिसका पहले नेात स्वप्न लेते थे। डिप्टी स्पीकर साहिबा, राम राज्य तभी होगा जब गांव का किसान इन सब चीजों से फायदा उठाएगा। जो चीज पहले हमारे बुजुर्गो ने सोची थी वह आज एक–एक करके की जा रही ह। अभी कुछ समय पहले बहिन शकुन्तला जी ने फौजी जवानों के बारे में कहा था। इस सरकार ने फौजी जवानों की भलाई के लिए पहले तो गवर्नर साहब के भाषण में बहुत कुछ कह दिया था और आज दोबारा फिर वित्तमंत्री जी ने जो अपनी बजट स्पीच दी है उसमें उन बातों को दोहराया है। उन्होंने कहा है कि हम फौजी जवानों को हर सुविधा प्रदान करने की कोशिश करेंगे। मै। तो यह कहूंगा कि हरियाणा सरकार अन्य सरकारों से आगे हैं अभी चौ. रणबीर सिंह जी ने भी कहा था कि हरियाणा के जवानों ने जितनी

बहादुरी इस लड़ाई में दिखायी है शायद हिन्दुस्तान के इतिहास में किसी भी एरिया के जवानों ने नहीं दिखायी होगी चाहे पहले जंग मुसलमानों के साथ हुई हो या दूसरों के साथ हुई हो। हिन्दुस्तान पर पहले भी मुसलमानों ने और अंग्रेजों ने हमले किये हैं चाहे वे पहाड़ों के रास्ते से आये, चाहे वे समुद्र के रास्ते से आये परन्तु इस बार हमारी फौजों ने चाहे वह थल सेना है, चाहे जलसेना है, चाहे वायु सेना है सभी ने बड़ी बहादुरी के साथ इस बार पाकिस्तान का मुकाबला किया है। उनको बड़ी भारी शिकस्त दी है। दुनियां के इतिहास में आजतक किसी ने यह नहीं सुना होगा कि एक लाख फौज ने सरन्डर किया हो, और उस फौज ने सरन्डर किया हो जिसके पास इतने विनाशकारी हथियार थे। उनके विनाशकारी हथियारों के मुकाबले में हमारी क्षमता बहुत कम थी क्योंकि उनको विदेशों से ही सारे हथियार मिले थे। लेकिन यह सारी दुनियां जानती है कि पाकिस्तान की फौज ने जो पाप किये थे, उससे उनके हथियार ओर उनकी आत्मा मलीन हो चुकी थी। उनके हथियारों में ओर उनमें लड़ने की हिम्मत नहीं थी। पाकिस्तान के फौजियों ने छोटे–छोटे बच्चों और जवान लड़कियों के साथ घोर अन्याय किया था। उस घोर अन्याय की सज उनको मिलनी ही थी और इसी कारण से उनकी हार हुई और उन्हें सरन्डर भी करना पड़ा। आज हमें अपने जवानों की वीरता पर बड़ा गौरव है।

जहां तक हरियाणा में डिफेन्स फन्ड का सम्बन्ध है वह पहले भी किसी प्रदेश से पीछे नहीं रहा है और न ही अब रहेगा। हरियाणा सरकार ने काफी पैसा डिफेन्स फन्ड में दिया है और जवानों की मदद के लिए भी काफी पैसा अलग रखा है। यह भी किसी से छुपा नहीं है कि जब हमारे जवान लड़ाई के मोर्चो पर जाते थे तो हरियाणा से गुजरने वाले फौजी जवानों के लिए लड़कियां और लड़के उनको जलपान कराते थे। इससे ही पता चलता है कि हरियाणा के जवानों में फौजियों के प्रति कितनी श्रद्धा हैं। मैंने यह पहले भी कहा है कि हमारी सरकार ने फौजी जवानों के लिए जो भी निर्णय लिए है वे बहुत ही अच्छे लिए हैं। जो जवान हमारे मोर्चो पर हैं उनको वहीं बैठे–बैठे ही यह पता लग रहा है कि हरियाणा सरकार हमारा कितना ख्याल रखती है।

हमारी सरकार ने स्वास्थ्यस के क्षेत्र में भी काफी प्रगति की है। सड़के और बिजली में कमाल ही करके दिखा दिया है। आज दूसरी किसी भी स्टेट में बिजली हर गांव में नहीं पहुंची है परन्तु हमारे प्रदेश में गांव–गांव में बिजली पहुंची हुई है। आज सड़कें और बिजली हर जगह पहुंच जाने के बाद यह कहा जा सकता है कि हरियाणा में दस्तकारी और इन्डस्ट्री लगाने के लिए बीज और जमीन तैयार हो चुकी है। जहां हमने खेती–बाड़ी में इतनी उन्नति की है वहां हम अपने छोटे उद्योग–धंधों ओर इन्डस्ट्री में भी तरक्की करना चाहते हैं। आज हमारे प्रदेश के अन्दर कितने ही आई.टी.आई. के संटर चल रहे हैं। वहां पर हमारे

विद्यार्थी ट्रेनिंग ले रहे हैं। ट्रेनिंग के पश्चात उनको उद्योग–धन्धों पर ही डिपैन्ड करना पड़ेगा। इसलिए हमारी सरकार जब इन्डस्ट्री की ओर भी काफी ध्यान दे रही है। हमारी सरकार विद्यार्थियों के प्रशिक्षण क लिए और भी कई केन्द्र खोल रही है। आज हमारी खेती–बाड़ी इतना बोझा नहीं उठा सकती है इसलिए अब तो सरकार को ज्यादा उद्योग–धंधे खोलने ही पड़ेंगे। हमारे यहां कई एक इन्डस्ट्रीयल कारपोरेशन बनी हैं। अब हमारे यहां, दूसरे प्रदेशों के लोग या हमारे प्रदेश के लोग जिन्होंने बाहर इन्डस्ट्री लगायी हुई थी, आ रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हमें जगह दो, हम हरियाणा में इन्डस्ट्री लगाना चाहते हैं। उनको पता है कि हरियाणा में इन्डस्ट्री लगाने से लाभ होगा। हरियाणा में आज ला एंड आर्डर की हालत अच्छी है और प्रदेशों की तरह से नहीं है। उनको यहां हर प्रकार की सहूलियत मिलने की भी उम्मीद है। उनको पता है कि हरियाणा में टैक्नीकल गाइडैन्स और दूसरी सुविधायें भी पूरी तरह से मिल सकती हैं। हमने कुछ लोगों को इन्डस्ट्री लगाने का निमंत्रण दिया है और कुछ को दे रहे हैं।

हमारी सरकार ने टैक्सिज तो बहुत ही कम लगाये हैं। इस बजट में तो कोई भी टैक्स नहीं लगाया है। अभी एक–दो भाइयों ने कहा कि यह सरकार टैक्स चोरी से लगाती है अर्थात बाद में आर्डीनेन्स से लगाती है यह बिल्कुल गलत और बेबुनियाद बात है।

हमारी सरकार अपनी ओर से दस्तकारी खोल कर उस पर भी पैसा लगाना चाहिती है और लगा रही है। कुछ दिनों में हमारी स्टेट हिन्दुस्तान में सबसे प्रगतिशील स्टेट होगी। अब वह दिन दूर नहीं है जब हमारी सरकार सब लोगों को जीवन की सारी सुविधायें प्रदान कर सकेंगी। अभी पिछले दिनों जब लड़ाई बन्द हुई तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन ब्यान दिया कि अब हमें फिर से उसी मोर्चे पर लगना है जिसके लिए हम पहले लड़ रहे थे। वह मोर्चा हमारा भुखमरी, बेरोजगारी और फिरकापरस्ती को दूर करने का है।

मैं वित्तमंत्री महोदया से एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि जहां उन्होंने बजट में सब चीजों के लिए पैसा रखा है ओर जन–जीवन की सुविधाओं के लिए पैसा रखा है वहां आजकल की जो शिक्षा प्रणाली है उसकी ओर भी ध्यान देना चाहिए। आजकल की जो शिक्षा की पालिसी है इसमें चेंज होना बहुत जरूरी है। आजकल की शिक्षा केवल क्लर्क ही पैदा करती है चाहे वह मैकाले की शिक्षा प्रणाली है और चाहे वह अंग्रेजों की चलायी हुई है। इस प्रणाली मैं चेज आना बहुत ही जरूरी है। हमारे यहां मैट्रिक और बी.ए. पास कितने ही लड़के फिर रहे हैं। एक पोस्ट निकलती है तो कई बी.ए. ओर मैट्रिक पास उसके लिए अप्लाई करते हैं। अब तो ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिसको पढ़कर किसी भी लड़के को दूसरों पर निर्भर न करना पड़े, वह अपने हाथ से अपना कोई काम कर सके। इस शिक्षा प्रणाली की

जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, इसलिए हमें उन बेकार नौजवानों के लिए, चाहे पब्लिक सैक्टर में चाहे प्राइवेट सैक्टर में, चाहे कोआप्रेटिव सोसायटी में, नौकरी तलाश करके देना ही होगा। आज बेरोजगारी की भरमार है। आज इस नौकरी से केवल दो–सौ, अढ़ाई सौ रूपये महीना ही वह कमा सकता है। यदि उसका अपना कोई दस्तकारी का धन्धा हो तो वह पांच सौ और हजार रूपये महीना कमा सकता है (घंटी) मैं अभी दो–तीन मिनट में ही अपना भाषण समाप्त करता हूं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, जो बिल्कुल साधनहीन हैं उनकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी सरकार को अपने कन्धों पर लेनी चाहिएं और उन्हें जीवन की सारी सुविधायें देनी चाहिएं।

सरकार ने जो दो करोड़ रूपया हरिजनों या पिछड़े हुए वर्ग के लिए रखा है यह बहुत कम है। इससे हरिजनों को काम चलने वाला नहीं है ओर न ही 160 वजीफों के देने से उनका भला होने वाला है। मैं तो यह कहूंगा कि सरकार को उनकी, उनके बच्चों की सभी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। फिर चाहे सरकार 225 करोड़ की बजाए 370 करोड़ का बजट बनाये या 470 करोड़ का बनाये। मैं तो यह चाहता हूं कि उन बेरोजगारों को रोजगार मिले और जिनके पास रहने का मकान नहीं है उनको मकान मिले। अगर यह बातें पूरी नहीं होंगी तो हमारा समाजवाद का लक्ष्य भी पूरा नहीं होगा।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हमारी सरकार ने पूरी कोशिश की है कि लोगों को हर सुविधा दी जा सके। अब मैं अपने हल्के के विषय में भी एक दो बातें कहना चाहता हूं। मैं जबसे इस असैम्बली में आया हूं तब से हमारे हल्के मैं सड़कें, स्कूल, बिजली सभी चीजें पहुंचा दी हैं। जितनी इन चार सालों के अन्दर हमारे हल्के में तरक्की हुई है उतनी, मैं तो यह कहूंगा कि जब से दुनिया बसी है अर्थात आदि काल से इतनी तरक्की कभी नहीं हुई होगी।

मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि नरवाना ब्राँच–करनाल लिंक पर अभी

4.00 P.M.

तक काम शुरू नहीं हुआ है। हमारे इरीगेशन एंड पावर मिनिस्टर पंडित रामधारी गौड़ और चौ. रण सिंह जी मौके पर जाकर इसे अनाउन्स भी कर आये है लेकिन अभी तक भी उस पर काम शुरू नहीं हुआ है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इसे जल्दी शुरू करवायें। एक बात और कह कर मैं बैठ जाऊंगा। पीने के पानी की प्रावधान के बारे में डाक्टर मंगल सैन जी जैसे आदमी यह सोचेंगे कि यह कोई मुश्किल बात नहीं हैं। मैं हाउस को यह बताना चाहता हूं कि इस सरकार ने डेढ–डेढ़ सौ मील लम्बी पाईप लाईन बिछा कर गांवों में पानी पहुंचाया है। बंसी लाल सरकार की यह एक बहुत बड़ी देन है। यदि पानी का महत्व पूछना है तो उन लोगों से जाकर पूछो जो पीने के पानी की वजह से ऐरिये को

छोड़कर चले जाते थे और सारी गर्मियों के महीनों में दूर–दराज के इलाकों में पानी के लिये इधर–उधर भटकने थे और खानाबदोशों का जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन आज वह अपने घरों में बैठे हुए मौज से पानी पीते हैं। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौ. रणधीर सिंह पदासीन हुए) इस सारी बातें कह कर मैं यह कहूंगा कि हमारे कई विरोधी दलों के माननीय सदस्य और डाक्टर मंगल सैन, जो यह सोचते है कि इनको ही लोगों ने चुनकर भेजा है, यह सोचना छोड़ दें। हरियाणा की तरक्की को देखकर इनके पेट में मरोड़ उठते हैं, यह सोचते हैं कि प्रदेश की तरक्की के अन्दर हम भी भागीदार होने चाहिए। कई बार इसमें हिस्सा लेने की हिम्मत और हौसला तो करते है लेकिन फिर शर्म आ जाती है। इनको हौसला नहीं होता कि बंसी लाल से यह रिक्वैस्ट करें कि हमें भी अपने दल में शामिल कर लो। कई मैम्बर ऐसा बार–बार सोच चुके हैं। डाक्टर मंगल सैन जी बड़ी–बड़ी डींगें मारते हैं और जब उनको और कोई रास्ता नजर नहीं आता तो कभी कानून की बात करते हैं और कभी अदालत के दरवाजे खटखटाते हैं। उन्होंने बहुत कोशिशें करके देख ली ओर इस सरकार के कामों में रूकावट डालने की भी कोशिश कर ली, लेकिन वह इसमें कामयाब नहीं हुए। इनमें जनता के पास जाने की हिम्मत नहीं है। कभी मैमोरैडम देते हैं तो कभी बिजली क अफसरों पर इल्जाम लगाते है। बहुत घबराई हुई आवाज में कहते है कि हमारे महा–मंत्री जी ने यह कहा था कि इस दफा तो 66 वोटों से काम चला लो, अगली दफा

जनता इन्हें घुसने नहीं देगी क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार ने कितने काम किये है। जनता के पास जाने की इनमें हिम्मत नहीं हैं। यह क्या करते है? अखबार वालों को एक दिन पहले बुलाकर कुछ कह देते हैं और अगले दिन अखबार को लेकर बोलते हैं कि यह मेरी बात नहीं है, यह इस अखबार में लिखी हुई है। इनको यह पता नहीं है कि यह अखबार तो केवल 10 फीसदी लोग ही पढ़ते है। मैं मानता हूं कि प्रजातन्त्र में अखबारों का बहुत बड़ा स्थान है लेकिन हमारे यहाँ अखबारों के बारे में आम लोगों को कुछ पता नहीं है। अगर इनमें हिम्मत है तो इल्जाम लगायें और जब इलैक्शन आयेगा, चाहे 1972 में आये, चाहे 1973 में आये, जनता के पास जाकर देखें। तब इनको पता लगेगा कि वहाँ बिजली आयी है या नहीं, नहरें बनी हैं या नहीं। दूध का दूध और पानी का पानी स्पष्ट हो जायेगा। जनता न तो इन अपोजीशन के भाइयों या श्री मंगल सैन के बहकावे में अपने वाली है और न ही बंसी लाल जी के बहकावे में आती है। वह तो यह देखती है कि उसके काम कौन करता है? प्रजातन्त्र में उसके कुछ अधिकार हैं वह अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जानती है। अभी–अभी पार्लियामैंट के मिड–टर्म पोल हुए हैं। उससे सब कुछ स्पष्ट हो गया है। आज मोरार जी देसाई यह कहते हैं कि हमने गल्लियाँ की हैं। उनकी पार्टी की ही एक बहुत तेज लेडी मैम्बर यह कहती है कि हमारे लीडरों ने भूलें की हैं। अभी तो पार्लियामैंट के इलैक्शनन्ज से ही ये लोग पछता रहे हैं जब असैम्बली का इलैक्शन होगा तब तो इनको बहुत पश्चाताप होगा। पुराने

हथियारों से ये नये युग में नहीं लड़ सकेंगे। आज दुनिया कहाँ से कहाँ चली गयी है और ये चन्द मुट्ठी भर लोगों की रक्षा के लए बातें करना चाहते हैं। पंडित जवाहर लाल नेहरू यह कहा करते थे कि यह सोलहवीं शताब्दी की बात करते हैं ओर रहते बीसवीं शताब्दी में है। बैलगाडियों का दिमाग रखते हुए, रेलगाडी में सफर करते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज हमें कोआर्डीनेशन करना पड़ेगा। जनता क्या चाहती है, यह जानने के लिये और नेतागिरी यदि करनी है, तो जनता के नजदीक रहना पड़ेगा न कि दूर दौड़ना पड़ेगा। जनता के साथ–साथ चलनपा पड़ेगा अभी वक्त है, कुछ सीख लें वरना ''फिर पछताए क्या होत है, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत।''

(इस समय बहुत से माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री सभापतिः राज सिंह दलाल।

चौ. दलसिंहः चेयरमैन साहब, आप उनको बोलने की इजाजत तो बेशक दे दो पर यह भी देख लो कि हमने जो स्पीकर्ज की लिस्ट सप्लाई की है, उसमें मेरा सबसे पहला नाम था।

श्री सभापतिः नैक्स्ट आपको काल करेंगे।

Sh. S.P. Jaiswal: Sir more time should be given to the Oppostion. The Ruling Party need hardly speak when they have presented the Budget and they will have the right to reply.

श्री सभापति: हाँ, मिलना तो चाहिए। मैं आपके साथ किसी हद तक सहमत हूं। लेकिन जो बिजनैस एडवाइजरी कमेटी का फैसला हुआ है ओर हाउस द्वारा मान लिया गया है अब उसको कैसे बदलें।

श्री फतेह चंद विज: चेयरमैन साहब, यहां बैठे हुए तो आपके यह विचार थे कि अपोजीशन को ज्यादा टाईम देना चाहिए।

श्री सभापति: मैं तो अब भी वही कह रहा हूं।

श्री एस.पी. जयसवाल: यह तो अपोजीशन के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी यदि उसको बोलने भी नहीं दिया जायेगा।

श्री सभापति: जरूर बोलने देंगे।

चौ. राज सिंह दलाल (महम): चेयरमैन साहब, कल बहन जी ने जो बजह पेश किया था, आज उस पर डिसक्शन हो रही है। यह बड़ी खुशी की बात है कि उसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया बल्कि उसमें डिवैल्पमेंट के लिये खास प्रोविजन किया गया है। पिछले तीन–चार सालों में इस सूबे ने बहुत तरक्की की है ओर जो इस साल का बजट है उसे देखकर मैं यह समझता हूं

कि हम आगे से आगे बढ़तें जायेंगे। अभी कुछ दिन हुए, पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हुई, इसमें कोई शक नहीं कि हिन्दुस्तान के लोग बगैर किसी पार्टी के और बगैर किसी मजहब के इसमें शामिल हुए और उसे जीता। यह इस हकूमत और इन्दिरा गांधी की हकूमत का हक है कि वह यह कहे कि हमने एक फैसला ठीक टाईम पर लिया। इस लड़ाई ने इनको ही नहीं बल्कि तमाम दुनियां को यह दिखा दिया है कि हिन्दुस्तान, की पालिसी आज किसी से भी कम नहीं है। यही बात जानकर अपोजीशन के भाई परेशान है वह यह कहते हैं कि हम इस जीत का फायदा इलैक्शन में लेना चाहते हैं। वह यह नही समझते कि हमारी पालिसी ठीक थी। ठीक पालिसी को ही लोगों ने वोट देने हैं। यदि आज इलैक्शन हों, तो लोग इसी पालिसी को वोट देंगे और अगर फिर कभी हों तो भी इसी पालिसी को देंगे।

अब मैं आपको बजट के सिलसिले में एक बात अपने हल्के की बताऊंगा मेरे गोहाना तहसील के कुछ इलाके में फल्ड आता है और कुछ इलाका खुश्क है। वहाँ पर नहरों को पक्का किया जाना चाहिए ताकि पानी जाया न हो। पिछले दिनों जब चीफ मिनिस्टर साहब मेरे इलाके के एक गाँव माहरा में गये तो उन्होंने यह एलान किया था कि गोहाना तहसील की नहरों को सबसे पहले पक्का किया जायेगा। मुझे पता है कि जो काम वह कहते हैं, कभी उससे पीछे नहीं हटते। इसलिये मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही गोहाना तहसील की तमाम नहरों को पक्का किया

जायेगा। कुछ माइनर्ज ऐसी हैं जो हर महीने चलती हैं। लेकिन हमारे यहाँ की माइनरज में कभी पानी नहीं आता। जब कभी हम पूछते हैं तो वहाँ के अफसरान यह कहते हैं कि इस दफा टेल पर पानी में कमी हो गई थी, अगली दफा टेल पर पानी दे दिया जायेगा। मैं यह समझता हूं कि इस बात को सिम्पल वे में नहीं लेना चाहिए कि 'इस दफा टैल पर पानी में कमी हो गई थी इसलिये पानी नहीं दिया जा सका, बल्कि जब कभी भी टेल पर पानी कम हो तो हमें उन अफसरों से इसका कारण पूछना चाहिए, जिनकी वहाँ पर जिम्मेदारी है कि किस वजह से टेल पर पानी कम हुआ हैं जब टेल पर पानी आए तो किसी अफसर की यह डयूटी होनी चाहिए कि वह यह सूचना दे कि टेल पर कितना पानी है। अगर किसी वजह से टेल पर कम पानी बताता है तो साथ ही उसमें वजह बतानी चाहिए कि फलां वजह से टेल पर पानी कम है ओर उस कारण को जल्दी से दूर किया जाए। अगर अगली दफा भी टेल पर पानी कम बताता है तो मैं समझता हूं कि कोई वजह नहीं कि ऐसे आदमी को फौरन वहां से बदला न जाए ओर उसके खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। पानी का कम होना कोई मामूली बात नहीं है। अगर पानी जमींदार को समय पर नहीं मिलेगा तो अनाज पैदा नहीं होगा ओर हमें अमेरिका की तरफ देखना पड़ेगा। आज जो अमेरिका ने अपना सातवां बड़ा भेजा है वह यह समझ कर भेजा कि हम उनसे अनाज मांगते हैं। एक सातवां बेड़ा हरियाणा मं भी है वह भी जहां जाता है वहां सफाई हो जाती है। मैं नाम तो नहीं लूंगा लकिन जब वह कांग्रेस में

आता है तो कांग्रेस को हानि देखनी पड़ती है और जब बाहर जाता है तो बाहर वालों को हानि देखनी पड़ती हैं। (व्यवधान)

एक आवाज: कौन सा है वह सातवां बेड़ा। (व्यवधान)

चौ. राजसिंह दलाल: आपको पता नहीं वह बहुत ऊंचा है सातवां बेड़ा। चेयरमैन साहब, अभी हमारे कुछ भाई इस लड़ाई के अन्दर शहीद हुए। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी बहन ओम प्रभा जी ने जो बजट पेश किया है उसमें उनके लिए बहुत अच्छा प्रोविजन किया है और हिन्दुस्तान में हरियाणा पहली स्टेट है जिसने सबसे ज्यादा उनकी इज्जत की है तथा हौसला अफजाई की है लेकिन फिर भी मैं कुछ चंद सुझाव देना चाहूंगा। मेरा पहला सुझाव यह है कि हम यह चाहते हैं कि जो भाई शहीद हुए हैं, स्कूलों में उनके फोटो के साथ उनकी जिन्दगी के हालात लिखकर रखने चाहिए ताकि वहां के बच्चे तथा वहां के आदमी यह देख सकें कि इन बहादुरों ने हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जानें तक कुर्बान कर दी थीं।

दूसरा सुझाव यह है कि उन शहीदों के जो लवाहकीन हैं, बच्चे हैं, भाई है, उनको मुलाजमत में खास किस्म की रियायत देनी चाहिए। एम्पलाएमेंट एक्सचेंज को यह हिदायत होनी चाहिए कि वह सबसे पहले उनके नाम नौकरियां के लिए भेजें। उसके लिए सीनियारिटी की पाबन्दी नहीं होनी चाहिए। इसी बारे में एक खास वाक्या मैं बता दूं। पिछले दिनों चौ. रणबीर सिंह के हल्के

का एक आदमी शहीद हो गया था, उसकी मौत की चिट्ठी फ्रंट से मेरे पास आई। उसका छोटा भाई जो जे.बी.टी. है वह मुलाजमत के लिए घूमता है। ऐसे केसिज में जो उनके सगे भाई हैं या उनके बच्चे है हमें चाहिए कि उनक लिए कायदे कानून ज्यादा सख्त न रखें जाएं। हम उनके लिए एक ही फायदा बना दें कि जहां कहीं भी ये फिटइन हो सकते हों। उनको फिटइन कर देना चाहिए। हमें उनकी फैमिलजी को प्लाट देने चाहिए ताकि वे आबाद हो सकें। हमें अपने देश की फौज पर फखर है और हरियाणा की फौज ने जो बहादुरी दिखाई है उस पर भी हमें बहुत फखर है। रोहतक जिले के जवान बहुत ही बहादुर हैं, मैं कोई मुकाबला नहीं कर रहा हूं क्योंकि तमाम जवान हमारे अपने देश के जवान है, हमारे अपने जवान हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा शहीद रोहतक जिले के हुए हैं इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि रोहतक में और झज्जर में तहसील के हैडक्वाटर्ज पर डिफेन्स कालोनी बनानी चाहिएं ओर जो शहीद हुए हैं उनकी फैमिलीज को उस कालोनी में एक प्लाट बगैर कीमत के देना चाहिए तथा उनको कर्जा दिया जाए ताकि वे अपने मकान बना सकें और अच्छी तरह से आबाद हो सकें। सरकार को ऐसी फैमिलीज को हर तरह की सुविधाएं देनी चाहिएं ताकि उनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकें क्योंकि अगर वे गांव में रहे तो मुझे डर है कि वे पढ़ने के काबिल नहीं बन सकेंगे।

मैं समझता हूं कि उन शहीदों की जो विधवाएं हैं, हमें उनका खासतौर से ध्यान रखना चाहिए। उनको सिलाई की या किसी और किस्म की ट्रेनिंग दिलानी चाहिए या कोई और कोर्स सिखाना चाहिए और उसके बाद उनको किसी काम में लगाना चाहिए। अगर हम उनकी विधवाओं को इस प्रकार की सहूलियतें नहीं दे सकते तो हमारे लिए यह एक शर्म की बात है। इसमें कोई शक नहीं कि हरियाणा सरकार और हमारे अफसर दिन रात इस बात में जुटे हुए हैं कि जो शहीद हुए हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें दें। इसलिए मैं समझता हूं कि मैंने जो यह चन्द सुझाव दिए हैं उन पर जरूर गौर किया जाएगा और उन पर अमल करने की कोशिश की जाएगी। इन लफ्जों के साथ मैं खत्म करता हूं और समझता हूं कि जो यह बजट पेश हुआ है, यह निहायत शानदार है और इसे हमको पास कर देना चाहिए।

श्री सभापति: ऐसा है कि समय का जो विभाजन हुआ था उसमें 2.25 घंटे विरोधी दल के सदस्यों का था। मैं समझता हूं कि दो–तीन विरोधी दल के सदस्य और बोल लें, चालीस मिनट के करीब बाकी हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि थोड़ा–थोड़ा समय ले लें जिससे दूसरों को भी बोलने का समय दिया जा सके।

चौ. दल सिंह: चेयरमैन साहब, यह फैसला हुआ था कि हमें प्रोपोर्शनेट टाईम और उसके अलावा बीस मिनट और मिलेंगे तो बीस मिनट और लगा दीजिए। इस तरह से 2.45 घंटे का टाईम बनता है।

श्री सभापति: जो हिसाब बताया है वह बीस मिनट शामिल करके ही बताया है।

चौ. दल सिंह (जुलाना): आप दोबारा हिसाब लगा लें, मैं तो थोडी ही देर बोलूंगा। चेयरमैन साहब, बजट के ऊपर बोलने हुए आज सरकारी बेन्चिज के सम्मानित सदस्य श्री बनारसी दास ने यह बात मानी है कि नहरों के महकमें में बड़ी भारी अन्धेरगर्दी है, उन्होंने यह भी तसलीम किया है कि यहां भ्रष्टाचार हैं, यहां पानी कम मिलता है, यहां आउटलेट्स की हालत ठीक नहीं है। जब सरकारी बैन्चिज के लोग ही यह मानते हैं कि काम ठीक नहीं हो रहा है, धान्धली है तो मैं समझता हूं कि इस विषय पर और ज्यादा बोलने का कोई लाभ नहीं है। चेयरमैन साहब, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई में हिन्दुस्तान की बड़ी भारी विजय हुई जिससे हमारी दुनियां के अन्दर शान बढ़ी है, इज्जत बढ़ी है लेकिन यह भी मानने की बात है कि हिन्दुस्तान का इसमें बड़ भारी खर्चा हुआ है। बंगला देश के शरणार्थियों पर करोड़ों रूपया खर्च हुआ है और बंगला देश को सहायता देने के लिए सरकार ने वादा किया है, इससे जाहिर है कि देश को अथाह धन की जरूरत है और मैं समझता हूं कि हरियाणा का बजट जो घाटे का आया है उसका यही कारण है। इन सब बातों को देखते हुए मैं यह महसूस करता हूं कि जितना भी धन इक्ट्ठा किया जाए, जितनी भी बचन हम कर सकें उतना ही अच्छा है। मैं आपका ध्यान 1962 की ओर दिलाना चाहता हूं जब चीन ने हमारे ऊपर

हमला किया था। उस समय पंजाब में सरदार प्रताप सिंह कैरों चीफ मिनिस्टर थे। उनकी मिनिस्टरी में 31 मिनिस्टर थे। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई उन्होंने 23 मिनिस्टरों को कह दिया कि घर जाओ। उन्होंने आठ मिनिस्टरों से अपनी बजारत चलाई ओर आज हरियाणा की सरकार के अन्दर मिनिस्टरों की इतनी बड़ी फौज है जबकि देश में एमरजेंसी है ओर रूपए की सख्त जरूरत है।

चेयरमैन साहब, ऐसी हालत में आप देखें कि इस सरकार के कितने खर्च बढ़ गये है और अगर यह कहा जाए कि हरियाणा प्रदेश के खजाने का बड़ी बेदर्दी से बर्बाद किया जा रहा है तो यह कोई गलत बात नहीं होगी। जितनी कमेटियां आज हरियाणा के अन्दर हैं, किसी और प्रदेश में नहीं हैं और एक–एक कमेटी के अन्दर ट्रेजरी–बैन्चिज के 10–10 मैम्बर हैं। एक ओर हम हैं, अगर कोई गल्त काम कर रहे हैं फिर भी इनको कसूरवार बताएंगे लेकिन दूसरी ओर यह लोग इतने गल्त काम कर रहे हैं फिर भी इनको कसूरवार नहीं कहा जाता। चेयरमैन साहब, इनकी और क्या–क्या बातें आपको बताऊं। जो मैम्बर साहिबान कमेटी की मीटिंगज में हिस्सा लेने के लिये आते हैं, उन सबको हरियाणा सरकार की तरफ से बसों के फ्री पासिज दिये हुए हैं और यही नहीं बल्कि हरेक मैम्बर को हिन्दोस्तान में रेल से सफर करने के लिये कूपन दिये हुए हैं ओर वे साल में सोलह हजार किलोमीटर का सफर फ्री कर सकते हैं पर यहां पर हम देखते हैं कि एक तरफ तो मुफ्त में सफर करते हैं और फिर सरकार से डयोढ़ा

किराया भी क्लेम कर लेते हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो गलत रिवायात है, उसको खत्म किया जाए। यहां तक ही नहीं जब हम मीटिंगज में आते हैं तो दो रोज पहले का डी.ए. लेते हैं और दो रोज बाद का डी.ए. लेते हैं, इस तरह से हजारों रूपया हमारी सरकार की गल्त पोलिसीज की वजह से यूं ही वेस्ट हो रहा है। इसी प्रकार हरियाणा सरकार ने किसी एक भाई को एग्रो–इन्डस्ट्रीज का चेयरमैन बना दिया है, किसी को लैंड मार्टगेज बैंक का चेयरमैन बना दिया है और किसी को मार्किटिंग फैडरेशन व हरियाणा माईनर इरीगेशन टयूबवैल कार्पोरेशन का चेयरमैन बना दिया है। तो चेयरमैन साहब, मैं बताना चाहता हूं कि इसी तरह से उनको हजारों रूपया तनख्वाह देते हैं, कोठी भी इन लोगों को मुफ्त में देते हैं, डी.ए. और टी.ए. की तो बात ही छोड़िये। इस किस्म के नाजायज खर्चे में आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। वित्तमंत्री महोदया यहां पर बैठी हैं। मैं उनसे से यह कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार को कोई खतरा नहीं है और इस एमरजेंसी में तो खतरे का सवाल ही पैदा नहीं होता तो फिर क्यो यू ही पैसा बर्बाद किया जा रहा है। चेयरमैन साहब, अगर वाकई इन्होंने देश का हितैषी बनना है तो मैं अर्ज करूंगा कि यह जो फिजूलखर्ची हो रही है, इसको खत्म किया जाए। आपको यह देखकर हैरानी होगी कि एक तरफ तो देश के ऊपर खतरा बना हुआ है, युद्ध हो रहा है और दूसरी तरफ यह लोग कमेटियां बना रहे थे इन्होंने 25 नवम्बर, 1971 को एक रूरल डिवेल्पमेंट बोर्ड बनाया है, जिसके 29 मैम्बर हैं। आप अन्दाजा

लगाइए कि ये क्या तरक्की करेंगे। सबसे अजीब बात तो यह है कि अपोजीशन का इसमें एक भी मैम्बर नहीं है। एक और कमेटी इन्होंने 9 दिसम्बर, 71 को बनाई, जिसका नाम पब्लिक रिलेशन्ज कमेटी है। यह कमेटी सिटिजन कौसिल के सिलसिले में बनाई है। इस कमेटी में कुछ वही मैम्बर हैं जो सिटिजन कौंसिल के मैम्बर भी है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह पब्लिक रिलेशन्ज कमेटी क्या काम करती है? सिवाये इस बात के कि वे चन्द लोगों को ऐसा करके खुश करते हों और कोई काम उस कमेटी के पास करने को नहीं है। एक और कमेटी इन्होंने बनाई है, जिसका नाम है कमेटी फार वेलफेयर आफ आर्मड फोरसिज एंड एक्स सर्विसमैन। चेयरमैन साहब, इसी काम के लिये तो पहले ही हर जिला स्तर पर एक डिस्ट्रिक्ट सोलजर्ज सेलरज एंड एयरमैन्ज बोर्ड बना हुआ है, उसका काम भी तो यही है जो कि इस कमेटी ने करना है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि फिर यह कमेटी क्या काम करेगी? यू ही पैसे को पानी की तरह बहाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इस हरियाणा सरकार को जनता के साथ बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं है। यहां तक ही नहीं, इन्होंने एक और कमेटी 28 दिसम्बर, 1971 को बनाई है जिसका नाम है—कमेटी फार कलचरल एफेयर्ज। चेयरमैन साहब, इस वक्त देश को पैसे की जरूरत है, देश पर आफत आई हुई है और यह फिजूल में कमेटियां बना रहे हैं। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस किस्म के नाजायज खर्च को बन्द किया जाना चाहिये। मेरी यह सजैशन है कि इस विधानसभा का एक सदस्य ज्यादा से ज्यादा दो कमेटियों का

मैम्बर हो। एक तरफ तो ये मैम्बर मुफ्त की सवारी करते हैं, और दूसरी तरफ ड्योड़ा किराया क्लेम करते हैं। अगर सरकार इस तरफ ध्यान दे तो काफी बचत हो सकती है। जहां तक डैमोक्रेसी का ताल्लुक है इसके बारे में तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका नामोनिशान ही इस सरकार ने मिटा दिया है। क्योंकि इन्होंने सभी जगहों पर अपने ही आदमियों को बिठा रखा है। इन्होंने लैंड मार्टगेज बैन्कम में, मार्किटिंग कमेटियों में, कोआपरेटिव सोसाईटीज के अन्दर अपने ही आदमियों को नामीनेट कर रखा है, इसकी क्या जरूरत थी। इन लोगों ने तो डैमोक्रेसी का जनाजा निकाल रखा है। जो गल्त बातें इन लोगों ने की हुई हैं, उनको आपको मानना ही पड़ेगा। एक और बात में आपके नोटिस में लाना चाहता हूं वह यह कि इन्होंने शूगर मिल्ज के डारेक्टर्ज ऐसे आदमियों को बना रखा है, जो कि उसके मैम्बर भी नहीं हैं। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि किसी भी गल्त काम के लिये सरकार को कोई कदम नहीं उठाना चाहिये। मैं आपका ध्यान हरिजन कल्याण निगम की तरफ दिलाता हूं। हमारी वित्तमंत्री महोदया ने अपने भाषण के अन्दर यह बात कही है कि हमने दो करोड़ रूपये की लागत से एक हरिजन कल्याण निगम स्थापित किया है और इस निगम ने जनवरी, 1972 से अपना काम भी शुरू कर दिया है। आप हैरान होंगे कि 30 दिसम्बर, 1971 तक 34 लाख रूपये को कर्जा मन्जूर किया गया और यह कहा गया कि इसमें से 13 लाख रूपये की राशि पहले ही दी जा चुकी है। इस काम के लिये इन्होंने एक फार्म भी प्रेसक्राईब किया हुआ है और

उसमें लिख्वाा है कि 50 हजार की रकम बिना किसी श्योरिटी के दी जाएगी और 15 हजार रूपया ट्रैक्टर के लिए, 10 हजार रूपये की रकम स्कूटर खरीदने के लिये दी जाएगी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह फार्म केवल चण्डीगढ़ के ही दफतरों में मिल सकते हैं और किसी जिला स्तर के दफ्तर में यह फार्म नहीं मिल सकते। आप अन्दाजा लगाइये कि एक गरीब हरिजन, इस फार्म को प्राप्त करने के लिये, गुडगांव और नारनौल से यहां आता है तो कम से कम उस आदमी के आने–जाने में 40 रूपये लग जाते हैं। नतीजा यह होता है कि पहले तो उसको दफ्तर नहीं मिलता ओर वह सैक्टरों में ही घूमघाम कर परेशान होता है और अगर दफ्तर किसी तरह मिल भी जाता है तो दफतर से केवल एक ही फार्म मिलता है। मैं नहीं समझता कि जिला हैडक्वार्टरज पर यह फार्म क्यों नहीं दिये जाते। अगर यह फार्म उन्हें वहीं मिल जाएं तो गरीब हरिजन को फिजूल में परेशान न होना पड़ेगा ओर नाजायज खर्च न उठाना पड़ेगा।

श्री प्रभु सिंह: चेयरमैंन साहब, मैं आपके द्वारा आनरेबल मैम्बर की जानकारी के लिये यह बता देना चाहता हूं कि हर जिला स्तर के दफतर में, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर आफिस में और तहसील आफिस में, हमने इस बारें में हिदायतें दी हुई हैं और वहां से यह फार्म हर वक्त मिल सकते हैं। अगर कर्जा दिलाने के लिये लोगों को पुरानी दलाली का स्वाद पड़ा हुआ हो तो चेयरमैन साहब, उन लोगों का इलाज मेरे पास नहीं है।

चौ. दल सिंह: चेयरमैन साहब, हो सकता है यह ठीक हों लेकिन जो कुछ मैंने कहा है वह भी करैक्ट है और मेरा वास्ता लोगों से पड़ता है, मैं लोगों से मिलता हूं, वे लोग चंडीगढ़ आकर फार्म लेकर जाते हैं। इन्होंने कोई खुफिया हिदायतें दी हों तो यह जानें क्योंकि इनके ही एजेंट वहां पर रहते हैं जो ऐसा काम करते हैं (विघ्न) मुझे पता है कि वहां पर जो डी.डब्ल्यू.ओ. और ए. डब्ल्यू.ओ. हैं वे कैसे आदमी हैं। वह सीधे तौर पर किसी हरिजन को कर्ज नहीं देते हैं। अगर यह हमारी बात की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते तो इनकी मर्जी है हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो हर वह बात कहनी है जो जनता की भलाई की हो और हमें हक है इस सभा में बात कहने का।

श्री प्रभु सिंह: सच कहो झूठ तो न कहो।

चौ. दल सिंह: मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी इनफर्मेशन गलत है अगर कोई हिदायत है तो वह खुफिया होगी। (विघ्न) अब मैं यह बात यहीं छोड़ देता हूं अगर आप नहीं मानते। ये कहते हैं कि 13 लाख रूपया तकसीम हो चुका है। वह कैसे तकसीम हुआ है और कौन ले गया है वह मैं बता देता हूं। इनके एक एजेंट हैं जो कि जिला कांग्रेस कमेटी हिसार के प्रेजीडैंट हैं वह हरिजनों के नाम से 19 ट्रैक्टरों के लिये 9 हजार रूपये फी ट्रैक्टर के हिसाब से ले गये हैं। एक और साहब हैं हिसार के जो 9 ट्रैक्टरों के लिये 9 हजार रूपये फी ट्रैक्टर के हिसाब से ले गये हैं। किसी हरिजन को ट्रैक्टर नहीं मिला है। मैं तो यह पूछता हूं

कि जब किसी हरिजन के पास जमीन ही नहीं है तो वह ट्रैक्टर चलायेगा कहां पर। फिर जो रूपया दिया गया है उसकी कोई श्योरिटी नहीं ली गई। वह सारा रूपया गबन होगा और आप उसे वसूल नहीं कर सकते। यह सारा रूपया हरिजनों के नाम पर दिया गया हैं और इन्होंने अपने रिकार्ड में हरिजनों का नाम लिख दिया कि वह उनको दिया गया है मैं कहता हूं कि हरिजन सारे इलाकों के गरीब है। चाहे काई हरिजन महेन्द्रगढ़ का रहने वाला है चाहे जींद या दादरी का रहने वाला है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक रूपया भी जिला जींद में इस निगम की तरफ से किसी हरिजन को नही मिला है। आप ही कह दें किस को मिला है .....

श्री प्रभु सिंह: जिला जींद की जितनी आबादी है उसके मुताबिक फंडज दिये गये हैं।

चौ. दल सिंह: मैं भी तो यही कहता हूं कि जब आप रूपया देते हो तो जिलों की आबादी के तनासब से फंडज रखे जायें। आप हर बात में एलान करते हो और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कोई बात अगर है तो मिसाल देकर बताओ कि कहां गड़बड़ हुई है रगड़ देंगे। यह सारी बातें हाउस के सामने हैं और मैं कहता हूं कि either Subedar Parbhu Singh should resign or I will resign, if it is proved that any money has been given to the Harijans in Jind District. क्या मजाक की बात करते हो (विघ्न)?

श्री प्रभु सिंह: यह तो डेढ़ महीने के बाद जाने वाले हैं मैंने तो उसके बाद भी रहना है। (इंसी)

चौ. दल सिंह: यह तो वक्त ही बतायेगा कि कौन जाने वाला है। आपने पहले भी देख लिया है फिर देख लेता। आपने काफी पहले जोर लगा कर देख लिया है जब आपकी सरकार एक साथ में रूपयों की थैली लेकर और दूसरे हाथ में शराब की बोतलें लेकर फिरती रही लेकिन डिफीट आपकी हुई। अब भी मेरा पक्का विश्वास है कि जितना चाहे जोर लगा लेना मेरी डिफीट नही होगी....

एक आवाज: जमानत जबत होगी। (विघ्न)

चौ. दल सिंह: जमानत आपकी ही जब्त होगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि जींद के किसी हरिजन को एक पैसा कर्ज का नहीं मिला है। मैं यह भी कह सकता हूं कि इस निगम का जो मैनेजिंग डायरैक्टर है वह निहायत ही सज्जन आदमी है। लेकिन इसमें पक्षपात से काम चलता है और रूपया उनको मिलता है जिनको आपका इशारा होता है। मैं कहता हूं कि इस किस्म की धक्केशाही और वह भी आप एक हरिजन होकर और उनका नुमाइंदा होकर करते हैं, मैं कहता हूं कि अन्याय की कोई हद नहीं है .....

श्री सभापति: आप कितना समय और लेंगे?

चौ. दल सिंह: बस मैं दो मिनट में खत्म कर देता हूं। मैं तो काफी तेजी से बोल रहा हूं ओर लिखने वाल लिख भी नहीं पा रहे होंगे। एक बात मैं शिक्षा के बारे कहना चाहता हूं। किसी भी मुलक की तरक्की का दारोमदार आने वाली पीढ़ी पर होता है। यदि किसी देश या प्रान्त के बच्चे शिक्षित होंगे तो वह प्रान्त या देश अवश्य तरक्की करेगा। उसके बारे में यह देखना होता हे कि उसके बच्चों को तालीम कैसी मिलती है। अगर हमारे बच्चे सही तौर से तालीमयाफता नहीं हैं तो लाजमी तौर पर हरियाणा तरक्की नहीं कर सकेगा। देखना यह कि बच्चों को सही तालीम कैसे दी जा सकती है, और वह कौन दे सकता है और आने वाली पीढ़ी की तालीमी तरक्की कौन कर सकात हैं? यह हमारे अध्यापक ही कर सकते हैं। लेकिन इस सरकार ने जो दुर्दशा अध्यापकों की कर रखी है वह बयान से बाहर है। उनको अपने घरों से 20–30 मील के फासले पर तबदील किया गया है जो बी.ए. बी.एड. हैं उनको जिला से बाहर भेजा गया है। कई ऐसे भी अध्यापक हैं जिनका पिता घर में अकेला है और बूट़ा है उसे देखने वाला, रोटी देने वाला कोई नहीं है। कई ऐसे अध्यापक हैं जिनकी अकेली बूढ़ी माता घर पर है, कई ऐसे हैं जिनकी पत्नी नहीं है, छोटे–छोटे बच्चे घर पर हैं ओर उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। कई ऐसे अध्यापक भी उनमें हैं जिनके मां है और बाप है केवल घर अकेली नौजवान पत्नी है और दूसरा कोई घर में काम करने वाला नहीं है और कई ऐसे भी हैं जो दूसरे गांवों में गये लेकिन रिहायश के लिये मकान तक नहीं मिला इसलिये उनके

लिये कोई और चारा नहीं रहा कि बीस मील जायें और बीस मील वापस घर आयें। क्या आप समझ सकते हैं कि ऐसे हालात में हमारे अध्यापक बच्चों को तालीम दे सकेंगे? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रोजाना चालीस मील सफर करने वाला अध्यापक कभी भी पढ़ाने में दिलचस्पी नहीं ले सकता और जिस अध्यापक को हर वक्त अपनी औरत बच्चों और माता–पिता की परेशानी रहती हो वह कभी बच्चों की पढ़ाई–लिखाई में दिलचस्पी नहीं ले सकता। मैं कहता हूं कि जब से सरकार की यह पालिसी चली है, हरियाणा में शिक्षा का भट्ठा बैठ गया है। मैं आपसे कहता हूं कि अगर एक अध्यापक गलती करता है तो उसे सजा दो लेकिन इतनी भारी तादाद का क्या कसूर है जो उनको बरबार करने पर तुले हो। एक अध्यापक का अकेला बूढ़ा बाप है, घर पर उसका सिवाए उस अध्यापक के कोई और सहारा नहीं, एक की घर पर अकेली बूढ़ी माता है, उसे कौन रोटी देगा, किसी के अकेले बच्चे हैं घर पर, बाप है, न मां है और न पत्नी है उनकी कौन देखभाल करेगा और आप ईमानदारी से बतायें कि आज सर्दी का मौसम है घर पर अकेली नौजवान पत्नी रजाई में करवटें ले रही है और बीस मील के फासले पर बेचारा अध्यापक करवटें ले रहा है (हंसी) मैं पूछता हूं कि क्या हक है सरकार को इस किस्म की ज्यादतियां करने का। अगर एक ज्यादती हो तब भी हम चुप रह सकते हैं लेकिन यहां तो ज्यादतियों को कोई हिसाब नहीं। आप सारे कर्मचारियों को डी.ए. देते हैं लेकिन अध्यापकों को नहीं देते है उनके डी.ए. में से साढ़े 18 रूपये से लेकर 50 रूपये महावार तक काटै जाते

हैं आप ही बातये कि इस मंहगाई में वह कैसे गुजारा कर सकते है? अगर सक अध्यापक को 200 रूपये मिलते हैं तो उसके डी.ए. से साढ़े 18 रूपये काटे जाते हैं। खैर कोई बात नहीं आप उनको जितना तंग करेंगे उतना ही वह आपकी सेवा करेंगे और वही आपकी गांठ बांधेंगे जो आप उनको इतना तंग कर रहे हो। (विघ्न) जहां तक उनकी कनफर्मेशन का सवाल है पहले एक सरटन पीरियड रखा गया था कि दो साल पिछली कांफिडैशल रिपोर्ट ठीक होनी चाहिये लेकिन अब कहते हैं कि जब से वह सर्विस में लगा है तबसे उसकी कांफिडैंशल रिपोर्टस ठीक होनी चाहिये और शुरू से उसकी कलास की परीक्षा के नतीजे अच्छे हों तब उसकी कन्फर्मेशन होगी इसका मतलब यह है कि न इतनी सारी रिपोर्टस अच्छी आयें और न किसी की कनफर्मेशन हो। इसका नतीजा यह है कि आ हजारों अध्यापक सिलेक्शन ग्रेड न मिलने की वजह से दुखी हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन गरीबों के साथ इतनी गैर इनसाफी न की जाये। हां जो कसूरवार हैं उनको आप बेशक सजा दें लेकिन सारे के सारे अध्यापकों का कोई कसूर नहीं उनको क्यों रगड़ते हो। अगर आप चाहते हैं कि हरियाणा शिक्षा में तरक्की करे तो आपको अध्यापकों को पूरा मान देना पड़ेगा उनके दिमाग की परेशानी दूर करनी पड़ेगी ओर उनके साथ इन्साफ करना पड़ेगा .....

एक आवाज: आपको क्यों परेशानी है?

चौ. दल सिंहः मुझे परेशानी इसलिये है कि वे हमारे प्रांत के रहने वाले हैं हमारे भाई हैं हमारे बच्चे हैं (घंटी की आवाज) अब इनके सलेबस की बात भी सुन लो। किताबें इतनी हैं कि एक बच्चा उनको उठा नहीं सकता है। मासूम छोटे–छोटे बच्चों पर एक गधे का बोझ लाद रखा है। किताबें भी सैशन शुरू होने के 3 महीने बाद तक मिलती हैं और फिर कहते हैं कि हरियाणा में तालीम की तरक्की करेंगे। आप बेशक घर–घर में स्कूल खोल दें लेकिन जब तक आप अध्यापकों का मान नहीं करेंगे तरक्की नहीं हो सकेगी। फिर एक और बड़ी अंधेरगर्दी चल रही है किताबों की कीमतों के बारे में। एक किताब जो पंजाब में बिकती है वही किताब हरियाणा में उससे दुगनी कीमत पर बिकती हैं यह जो बोर्ड को चेयरमैन है, मैं समझता हूं और कहता हूं He is a corrupt officer. I can say that boldly. मैं हैरान हूं कि कैसे ऐसी किताबों की एप्रूवल देते हैं कि पंजाब में वही किताब साढ़े चार रूपये की बिकती है लेकिन हरियाणा में वह 9 रूपये में बिकती है। वही किताब है, वही आथर है, उतने ही सफे उस किताब के हैं सिवाये पहले एक टाइटल पेज के सारी चीज वही की वही है लेकिन कीमत दुगनी पर बिकवाई जा रही है। पहले भी यह बात बाई थी और चीफ मिनिस्टर साहब ने कह दिया था कि इन्क्वायरी करोयेंगे लेकिन आजतक इन्कवायरी नहीं हुई वैसे ही सब कुछ चल रहा है। (घंटी की आवाज) मैं सरकार से नम्रता के साथ निवेदन करता चाहता हूं कि आपने अध्यापकों के साथ जो ज्यादतियां की हैं उनको दूर करें उनके साथ अच्छा बर्ताव करें, वे

आपके बच्चे हैं, आपके सेवक हैं जैसे और हैं उनको आप सेवा का मौका दें। इन्होंने कहा ाि कि देहाती स्कूलों में लेडी टीचर होंगे लेकिन किसी स्कूल में एक भी लेडी टीचर नहीं ठहरती जिसका परिणाम यह हुआ है कि दो–दो साल से स्कूल बिना लेडी टीचरज के खाली पड़े हैं औ पढ़ाई का सत्यानाश हो रहा है। (शोर)

श्री सभापति: पीछे देखिए। (व्यवधान)

Ch. Dal Singh: They should not be worried about it. (Interruptions).

श्री सभापति: आर्डर, आर्डर प्लीज। (बहुत से सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गए) आप जरा सदस्यों की तरफ तो देखिए कितने बोलने के लिए खड़े हो गए हैं।

Ch. Dal Singh: They are unnuecessarily worring. That is not my fault. थोडा सा टाईम और दें दें। बिजली के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। इन्होंने माना है कि जितनी करप्शन और भ्रष्टाचार बिजली महकमें में है उतीन कहीं नहीं है। सड़कों को भी आप देख लें, गांवों में जो सड़के बनाई गई हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी सड़क पर एक ईट पक्की नहीं लगी। तमाम सड़कों पर कच्ची ईटें लगी हुई हैं और रोड़ी दो इंच तक भी नहीं हे। इन्होंने उचाने से कर–सिन्धु, साल मील लम्बी सड़क बनाई है। उस सड़क की लम्बाई लगभग 4 मील है लेकिन इन्होंने 7 मील लम्बी दिखाई है और झूठे, बोगस ऐस्टीमेट्स दिए हैं। इस तरह से जनता का पैसा खराब किया जाता है। वजीर

साहब बता रहे थे कि जुलाना से नन्दगढ़ ओर एक दो और सड़कों के नाम ले रहे थे कि हमने बनाई हैं। यह सड़कें आगे बनाते जाते हैं और पीछे टूटती जाती हैं। इस तरह से हरियाणा की बरबादी करना चाहते हैं। अब मैं एक दो सजैशन्ज आपके सामने रखना चाहता हूं .....

श्री सभापति: आप ये सुझाव लिख कर दे दें यह स्पीच का पार्ट समझा जाएगा। (व्यवधान)

चौ. दल सिंह: इन्होंने किताब में लिख दिया है कि जीं में इंडस्ट्रीज लगायेंगे। मैं सरकार से अर्ज करना चाहता हूं कि जींद में इंडस्ट्रियल एस्टेट कायम की जाए और वहां पर बस–अड्डा बनवाया जाये (व्यवधान)।

श्री सभापति: आर्डर, आर्डर प्लीज। चौ. दलसिंह जी, अपने आगे पीछे देखिए कितने सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गए हैं, आप बैइ जाइए (व्यवधान)।

Ch. Dal Singh: Only one minute and I will take my seat. Kindly let me conclude my speech. चेयरमैन साहिब, ये जींद में उस जगह पर बस अड्डा बनाना चाहते हैं जहां पर आबादी नजदीक नहीं है, बिजली के कनैक्शन नजदीक नहीं हैं। बस–अड्डे के लिए जमीन उन छोटे–छोटे किसानों से ली जाती है जिनके पास दो–दो किल्ले जमीन है। जिनकी हजारों एकड़ जमीन है, सरप्लस पड़ी हुई है उनसे नहीं लेते। इस तरह हरियाणा की

जनता की तड़पा रहे हैं। सारे हरियाणा की जनता दुखी है, सरकार को छोटे किसानों की जमीन नहीं लेनी चाहिए।

Sh. S.P. Jaiswal: May I draw you attention, Mr. Chairman, to the fact that when it Member refuses to sit down, perhaps the remedy would be for the Chairman to stand on his legs. Then every Member should sit down.

श्री सभापति: चौ. कटार सिंह बोलेंगे। (इस समय कई सदस्य एक साथ बोलने के लिए खड़े हो गए)।

चौ. जय सिंह राठी: इनके तीन आदमी बोल कर बैठ चुके हैं। जब अपोजीशन वालों को बोलने का मौका दिया जाए (व्यवधान)

श्री सभापति: कांग्रेस पार्टी और आपका समय तकरीबन बराबर ही है। इसलिए आपके साथ अन्याय नहीं होगा .....

चौ. जय सिंह राठी: मुझे टाईम मिलेगा या नही? (व्यवधान)

श्री सभापति: अगर सारे एकदम खड़े हो जाएं तो मै। क्या कर सकता हूं।

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल): चेयरमैन साहब, चौ. दल सिंह जी ने जींद के किसी अफसर और चेयरमैन शिक्षा बोर्ड हरियाणा के बारे में कहा कि वह कुरप्ट है। वे हाउस के अन्दर

नहीं हैं, हाउस में जवाब नहीं दे सकते इसलिए इन शब्दों की हाउस की कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

Ch. Dal Singh: Sir, I have not mentioned any name.

श्री सभापति: अगर ऐसे शब्द कहे हैं तो आप बिदड्रा कर लें।

Ch. Dal Singh: So far as I understand, I am correct अगर आप महसूस करते हैं, let it be withdrawn.

डा. मलिक चन्द गम्भीर: लाल ए प्वांयट आफ आर्डर, सर। जब चौ. दल सिंह जी बोल रहे थे तो उन्होंने फार्म के मुताल्लिक कुछ कहा था ओर स्पीच के दौरान सूबेदार प्रभु सिंह ने जवाब दिया था। फार्म के मुताल्लिक बात आई थी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऐसा होता है, यह बिल्कुल गलत बात है .....

श्री सभापति: यह प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

डा. मलिक चंद गम्भीर: यह क्लीयर प्वांयट आफ आर्डर है जी।

श्री सभापति: आपने समय ले लिया है, बैठ जाइए।

श्री कटारसिंह छोकर (सम्भालका): चेयरमैन साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं जो आपने मुझे बोलने के लिए टाईम दिया। मैंने पोलिटिकस स्पीच तो नही करनी है, मैं जनरल बातों पर ही बोलना चाहता हूं। मैं अपने हल्के की, अपने क्षेत्र की कुछ

बातें सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। मैं पानीपत तहसील से आता हूं, पानीपत एक ऐतिहासिक नगर है। जहां हमारी सरकार ने सारे हरियाणा की तरक्की के लिए काम किया है, चाहे वह शहर हो, चाहे देहात हो, हर दिशा में प्रगति दिखाई है, वहां पानीपत एक ऐसा इलाका है, ऐसा नगर है जो नैगलैक्टेड रहा है। नैगलेक्टेड रहने के कुछ कारण हो सकते हैं। अगर हमारी सरकार पानीपत की तरफ मामूली सा ध्यान देने का कष्ट करे तो काफी सुधार हो सकता है। मेरा कहने का यह मतलब यह नहीं है कि पानीपत के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें यह इलाका नैगलैक्टेड रहा है। आप हरियाणा में जगह–जगह ऐसे स्थान पायेंगे जो टूरिस्टस को अट्रैक्ट करते हैं, यहां बहुत अच्छे टूरिस्ट स्पौट्स हैं। आज हरियाणा में जगह–जगह झीलें, रैस्टोरेंटस बनाये जा रहे हैं। लेकिन हमें खेद होता है जब हम देखते हैं कि टूरीजम के लिहाज से पानीपत का नाम नहीं पाया जाता। हमें पानीपत का नाम नहीं मिलता कि कहीं पानीपत के क्षेत्र में कोई ऐसी इनकरेजमेंट होने वाली है। हालांकि पानीपत को कई कारणों से इस तरफ डिवैल्पड होना चाहिए, सबसे पहले इसकी डिवैल्पमेंट होनी चाहिए। यह सारा देश जानता है कि पानी एक ऐतिहासिक जगह है। भारतवर्ष की तीन लड़ाइयां वहां लड़ी गई, बड़ा अच्छा मैदान है जहां पर देश की किस्मत के फैसले होते रहे हैं। यह जगह बहुत अच्छी टूरिस्ट स्पौट बन सकती है अगर सरकार थोड़ा सा रूपया खर्च कर दे। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि तो ऐतिहासिक मैदान है

और जिसका काला अम्ब का इलाका कहते हैं वहां तक सड़क पहुंच गई है लेकिन वहां पर जाने वाले यात्रियों को बैठने का, आराम करने की सुविधा का कोई इन्तजाक नहीं है। काला अम्ब से दूसरी जगहों पर आने–जाने के लिए कोई साधन नहीं है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि काला अम्ब से दूसरी ऐतिहासिक जगहों पर आने–जाने के लिए यात्रियों की सुविधा दे।

चौ. जय सिंह राठी: क्या आप पानीपत से लड़ना चाहते हैं जो वहां की बातें कर रहे है?

श्री कटार सिंह छोकर: इसी तरह से एक बड़ी ऐतिहासिक जगह बोलीशाह कलन्दर है और यह ऐसी जगह है कि यदि कोई यात्री जाना चाहे तो नहीं जा सकता क्योंकि यह शहर के बीच में है। बाहर से कोई सड़क ले जा करके इसको डिवैल्प किया जा सकता है। बोली शाह कलन्दर देखने के लिए हर साल बहुत से लागेग आते हैं। वहां पर मेला और बाजार लगता है। इसी तरह से नजदीक के गांव जहां बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई हैं। आज भी वहां पर ऐसी जगहें मौजूद हैं जो देखने के काबिल हैं और डिवैल्प हो सकती हैं। मेरी प्रार्थना है कि टूरिस्ट डिपार्टमेंट को थोड़ा पैसा इन चीजों की डिवैल्प करने के लिए दिया जाए ताकि पानीपत को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। सारे प्रान्त को भी इस बात का फख होगा क्योंकि पानीपत एक ऐसी जगह है जहां बहुत बड़ी–बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं हुई है।

इसी तरह से कुछ स्पोट्स के मुताल्लिक भी मुझे कहना है। मुझे यह दु:ख नहीं है कि स्पोर्टस की ऐक्टिविटीज के लिए और जगह क्यों पैसा खर्च हो रहा है लेकिन हम भी चाहते हैं कि हमारे इलाके में भी स्पोर्टस की ऐक्टिविटीज के लिए कोइ इंस्टिच्युशन बनाएं ताकि वहां के लोग भी इनमें हिस्सा ले सकें।

इसके अलावा, सभापति महोदय, मुझे कोआप्रेटिव डिपार्टमेंट के बारे में भी कुछ अर्ज करनी है। कोआप्रेटिव डिवैल्पमेंट हुई है, यह बड़ी सराहनीय बात है। जो मौजूदा कोआप्रेशन मिनिस्टर हैं उसके वक्त में काआप्रेटिव सिस्टम में बड़ा सुधार हुआ है। कोआप्रेटिव मूवमैंट हमारे देहात की जान है क्योंकि वहां प्रगति के लिए प्रांत से जितनी भी सहायता मिलती है या कर्जे मिलते है। वे कोआप्रेटिव सोसाईटीज के द्वारा ही मिलते हैं। इसमें बहुत सारी कमियां थीं जिनमें अब सुधार हुआ है। बड़ा सराहनीय सुधार चौ. सरूप सिंह ने इनमें किया है लेकिन कुछ पिछले झगड़े ऐसे हैं, खासतौर पर से हमारी तहसील में जिनकी तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। मिसाल के तौर पर ऐसी सोसाइटियां हैं जिनमें एक–एक आदमी ने सारे गांव के नाम से कर्जे लिए हुए है। और वे आदमी आज सरकार के लोगों को ऐक्सप्लायट करके, उनके पास चक्कर मार रके उस पैसे को खुर्द–खुर्द किए हुए हैं। ऐसी मिसालें भी हैं कि लोगों ने बिल्कुल कर्जा नहीं लिया, अंगूठा नहीं लगाया, मैम्बर नहीं बने लेकिन हजारों लोग मेरी तहसील में, हमारे इलाके में ऐसे हैं जिन्हें आज

लायेबल किया गया है कि तुमने कार्जा लिया है। उनमें अब वसूलियां होगी। ऐसी दो–चार सोसाइटियां हैं। इसलिए कोआप्रेशन मिनिस्टर से मेरी प्रार्थना है कि जो मरीज सोसाइटियां हैं उन पर विशेष ध्यान देकर हमारी तहसील में सुधार किया जाए।

सभापति महोदय, मैडिकल डिपार्टमैंट का जो बजट है वह भी बड़ा सराहनीय है। बजट में हम देखते हैं कि 30 सब्र–डिविजनल और तहसील हैडक्वार्टर्ज पर ओर तीन–चार डिस्ट्रिक्ट हैड–क्वार्टर्ज पर बड़े अच्छे अस्पताल बन रहे हैं। बड़ी अच्छी सुविधाएं लोगों को मिली हैं और काफी फायदा हुआ है लेकिन फिर भी कुछेक सुझाव मैं इस सम्बन्ध में देना चाहता हूं। हमारे जो प्राईमरी हैल्थ सैन्टर्ज हैं, जो डिसपैन्सरीज ब्लौक लैवल पर है उनमें जितने बैडज हैं उनमें ज्यादा मरीज वहां रहते हैं। जब ऐसा है कि जरूरत से ज्यादा लोग वहां रहते हैं और आंकड़े मंगवा कर यह बात सिद्ध हो जाए कि वह डाक्टर्ज ज्यादा आदमियों का इलाज करते हैं तो उनके बैडज की तादाद किसी हद तक बढ़ा देनी चाहिए। इससे फाईनैन्शियल इंप्लीकेशन कोई नहीं होने वाली क्योंकि आज भी अथोराइज्ड कैपेसिटी से ज्यादा इंडोर पेशैन्टस के तौर पर लोग वहां होते हैं। इस सम्बन्ध में कुछ थोड़ा विश्वास तो इस बजट में दिलाया गया है। मैं नहीं समझता कि ऐक्सरे की सुविधाएं सभी जगह दी गई हैं। अगर सभी जगह दी गई हैं या दी जाने वाली हैं जहां नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे इलाके में तो जितनी भी प्राईमरी हैल्थ सैन्टर्ज ब्लाक

लैवल पर हैं उनमें किसी में भी यह सुविधा नहीं है। अगर यह बात पूरी हो जाए तो लोगों को बहुत फायदा होगा और ऐक्सरे के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा।

इंडस्ट्रीज की बाबत में इतना अर्ज करना चाहता हूं कि जहां देश में चारों ओर इतनी प्रगति हुई है वहां रूरल इन्डस्ट्रीज की बाबत भी कुछ प्लानिंग करनी चाहिए। अभी इनको कोई विशेष एनकरेजमेंट नहीं दी जाती या लोग ही इससे फायदा नहीं उठाना चाहते। तो हमें ऐसा तरीका या मीन्ज ढूंढने चाहिएं कि देहात के लोग इनकी और आकर्षित हों। खाली जमीन से गुजारा नहीं होने वला है। रूरल इंडस्ट्रीज एवं छोटी इंडस्ट्रीज के प्रति किसी न किसी तरह से लोगां में शौक पैदा करना ही चाहिए ताकि देहात के जो फालतू आदमी हैं, जो ऐग्रीकल्चार में नहीं लग सकते, जो ऐग्रीकल्चरल लेबर में नहीं खपाए जा सकते, उनको रोजगार मिले। बेरोजगारी आज इतनी है जिसका कोई हिसाब नहीं। इसलिए लोगों को रोजगार देने और गरीबी हटाने का जो हमारा लक्ष्य है वे दोनों बातें इस ओर ध्यान देने से हल हो सकती हैं। खादी बोर्ड का मैं मैम्बर हूं और जैसा गोरख धन्धा वहां है उसका मुझे इल्म है। वह बड़ा अच्छा बोर्ड है लेकिन उसे वित्तीय सहायता के रूप में बहुत कम पैसा मिलता है। जो सहायता उसको मिलती है वह बहुत नाकाफी है। उसका इफैक्ट भी रूरल इंडस्ट्रीज पर मैं समझता हूं कोई खास नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आज जो हमारी विभिन्न विभागों में बिखरी हुई योजनाएं हैं, जैसे

इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की हैं, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज का जो सैल है उसकी हैं और उधर कोआप्रेटिव डिपार्टमैंट की हैं, अगर सारी योजनाओं को इकट्ठा करके इक्ट्ठे साधन जुटाए जाएं तो बहुत लाभ होगा। यह एक बड़ी जरूरी बात है। अगर यह हो जाए तो हो सकता है कि लोग छोटे–छोटे जो धन्धे हैं रूरल साइड में उनको अडोप्ट करें।

डेरीज की बाबत भी, सभापति महोदय, बजट में हमने हौसाले की बात देखी है। इसको देखते हुए यह अहसास होता है कि देहात के लोगों के लिए आमदनी के साधन बढ़ाने की कोशिश सरकार ने की है। जगह–जगह मिल्क प्लांट लगाए जा रहे हैं, जैसे जींद, अम्बाला और भिवानी में। दिल्ली के नजदीक के इलाके दिल्ली मिल्क सप्लाई कर सकते हैं लेकिन कुछ तजुरबा यह कहता है कि दिल्ली मिल्क सप्लाई करने में हम लोग कामयाब नहीं हुए। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि पानीपत के इलाके तथा करनाल जिले के लिए भी अपनी स्टेट की तरफ से कोई प्लांट लगाया जाए और यदि मिल्क प्लांट नहीं लग सकता हो तो दिल्ली मिल्क सप्लाई स्कीम जो है उसमें सुधार कराया जाए ताकि लोग फायदा उठा सकें। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) अध्यक्ष महोदय दिल्ली में दूध सप्लार्ठ करने में लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। वे मुसीबत में फंसे पड़े हैं। जिस रोज दूध सप्लाई किया जाता है उसके एक महीने बाद रिपोर्ट आती है कि तुम्हारे

5.00 P.M.

दूध की परसैन्टेज यह थी, इस प्रकार उनको बड़ा लौस होता है। वहा दूध उनके सामने टैस्ट नहीं होता है। वहां बड़ा गोरख धंधा बना हुआ है। जिस प्रकार से दूसरे जिलों में डेरी डिवैल्प की गयी है इसी प्रकार से हमारे पानीपत के इलाके को भी मौका मिलना चाहिए।

इस सरकार के आने के बाद इरीगेशन में बड़ी भारी प्रगति हुई है और भविष्य में भी सरकार बड़ा पैसाखर्च करने जा रही है। हमारे इलाके में अभी हाल में जो पक्की वैस्ट्रन जमना कैनाल बनी है जिसका अभी पिछले दिनों उद्घाटन हुआ है उससे हमारे इलाके के लोगों को बड़ा भारी फायदा होगा। जब यह कच्ची नहर थी तो इसका पानी आसपास की जमीन में जजब हो जाता था और उस इलाके में नमी रहती थी अब पक्की नहर बनने के बाद वह नमी खत्म हो जायेगी ओर जो लोगों को नुक्सान होता है वह बच जायेगा। इस नहर के पक्की होने के कारण दो सौ क्युसिक पानी भी बचेगा जो दूसरे एरिया को इरीगेट कर सकेगा। दूसरे जो जमीन पहले खराब हो गयी थी उसकी री–क्लैम किया जा सकेगा।

इसके अलावा ऐनीमल हैसबेंडरी साइड पर भी बड़ा अच्छा प्रोग्राम हमारी सरकार ने चलाया है। डेरी और एनीमल हैसबेंडरी हरियाणा की जान है। इनके लिए सरकार ने तरह–तरह की स्कीमें और योजनायें बनायी हैं जिससे एनीमल हैसबेंडरी बहुत

ज्यादा बढ़ेगी और लोगों को खुशहाल करने में बड़ी भारी मदद करेगी।

अब मैं कुछ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के विषय में कहना चाहता हूं। यह तो मैं मानता हूं कि इस सरकार के आने के बाद हरियाणा में रोडज बहुत ज्यादा बनी हैं और ट्रांसपोर्ट में भी काफी प्रगति हुई है। यह मैं मानता हूं कि लम्बे रूट्स पर तो सरकार ने काफी बसें चालू की हैं और कर रही है परन्तु जो छोटे रूट्स हैं उनकी ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार ने जो एक गांव से दूसरे गांव तक या किसी शहर से गांव तक आठ–दस मील के टुकड़े बनाये हैं उन पर बसें चलायी जायें ताकि उन रोड़स का सही फायदा हो सके। आजकल स्थिति यह है कि छोटे रूट्स पर दस दिन के लिए सरकार बस चला देती है और फिर बन्द कर देती है। गवर्नमैंट इस विचार से बन्द करती है कि वहां पर घाटा हो रहा है लेकिन उसका कारण यह होता है कि छोटे रूट्स पर सवारी तो होती हैं पर आमतौर पर कंडक्टर या तो सवारी को बैठाते नहीं या टिकट नहीं काटते हैं। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाये जिससे आठ–दस मील के टुकड़ों पर बसें चलायी जा सकें। इस सरकार ने लोगों को जहां इतनी सुविधाये दी हैं वहां यह सुविधा भी दी जाये।

बजट को पढ़ने से पता चलता है कि हमारी सरकार पब्लिक हैल्थ पर भी काफी पैसा खर्च करने जा रही है। बजट में

कहा गया है कि कुछ नगरों में सीवरेज सिस्टम चालू किया जायेगा और जहां पहले चालू किया हुआ है उसको पूरा किया जायेगा। मैं सरकार को यह याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे पानीपत शहर में बहुत पहले पार्टली सीवरेज सिस्टम शुरू हुआ था। वहां पर सरकार ने पैसा देकर नालियां भी बनायी थीं, पैसा न मिलने के कारण से उनको बीच में ही छोड़ दिया गया था। जब हमारी सरकार नये नगरों में भी सीवरेज सिस्टम चालू करना चाहती है तो हमारे पानीपत शहर में जहां पर सिकी हद तक काफी काम मुकम्मल भी हो चुका है और अधूरा होने की वजह से वहां पर लोगों को काफी असुविधाएं हो रही हैं। इसलिए लोगों की कठिनाइयों को देखते हुए सरकार को पानीपत में उन नहरों से पहले सीवरेज सिस्टम चालू करना चाहिए जिनको अब इस योजना में लेने जा रही है। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे यहां काफी पार्टली काम हो चुका है और गवर्नमैंट उस पर काफी पैसा खर्च भी कर चुकी है अगर वह काम पूरा न किया गया तो वह पैसा बेकार ही जाएगा।

हरियाणा के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारी सरकार ने रूरल सैनीटेशन बोर्ड कायम करने का फैसला किया है। वैसे तो सरकार का गांवों की ओर पहले ही ध्यान जाना चाहिए था। गांव की सफाई न होने के कारण से बहुत बुरी हालत है। किसी भी गांव में जाइये वहीं पर गन्दगी के ढेर पड़े हुए मिलते हैं और गांव में घुसने को दिल नहीं करता है। इस गन्दगी के रहने

का कारण ही यह है कि हमने लोगों को वे सुविधायें नहीं दीं जो मिलनी चाहिए थीं। हमने गांवों की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब और हैल्थ मिनिस्टर साहब को कई साल पहले एक केन्द्र दिखाया था जो एक संस्था द्वारा चलाया गया था। वहां पर एक सैनीटेशन स्कूल था। वहां पर सफाई की ट्रेनिग दी जाती थी और वहां पर सफाई के इनसटरूमैटस भी बनाये जाते थे जो देहातों में इस्तेमाल हो सकते हैं। अब वह स्कूल पैसे के अभाव में लगभग बन्द सा हो चुका है और सरकार की ओर से उस स्कूल को कोई एन्करिजमेंट नहीं मिली है। वह स्कूल ऐसी जगह पर है और उसमें अब भी ऐसा स्टाफ है और लग भी सकता है जिससे सरकार को काफी फायदा हो सकता है। अभी पिछले दिनों उन्होंने सफाई पखवाड़े को प्रोग्राम भी चलाया था। उन्होंने देहात के लोगों को बताया था कि किस तरह से गांव में सफाई रखी जा सकती है, कैसे वहां टट्टी बनानी चाहिए, किस जगह पर पशुओं के बान्धने की जगह बनानी चाहिए? इस तरह का प्रोग्राम उन्होंने किया था। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि उस स्कूल को फिर से सहायता देकर चालू किया जाये। आशा है कि सरकार जल्दी ही इस सैनीटेशन बोर्ड को चालू करेगी और देहात के लोगों को अच्छी जिन्दगी मिलेगी, बगैर सफाई के कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा भी है कि देहात में सफाई होनी चाहिए। इसलिए पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट ने जो प्रोग्राम बनाया है यह सारे देश में हरियाणा में सबसे पहला होगा। अभी तक किसी भी स्टेट में ऐसा बोर्ड नहीं

बना हुआ है। जब हम स्कूलों में पढ़ते थे तो हमारे मास्टर्ज हमें गावों में गली मोहल्लों में ले जाते थे और वहां पर गांवों की सफाई करवाते थे। पहले गांवों में सफाई का कम्पीटीशन भी होता था। गांव में जिस घर की सफाई अच्छी होती थी उसको बहुत अच्छा घर माना जाता था। आजतक भी उन घरों को जिनकी सफाई अच्छी होती थी बड़े फख से काह जाता है कि पहले इस घर में बहुत ही अच्छी सफाई होती थी बड़े फख से कहा जाता है कि पहले इस घर में बहुत ही अच्छी सफाई रहती थी। लेकिन आजकल कोई कम्पीटीशन नहीं होता है, कोई इनाम नहीं दिया जाता। इसमें फाइनेन्शल इम्पलीकेशन भी नहीं होती। इसलिए सरकार को इस ओर अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। जिस गांव की अच्छी सफाई नहीं होगी उस गांव के लोग अच्छी जिन्दगी बसर नहीं कर सकते। सफाई से रहने से दिमाग भी ठीक काम करेगा ओर डिवल्पमेंट भी होगी। जहां हरियाणा में इतने अच्छे काम हुए हैं और हम खुशहाली की तरफ जा रहे हैं, हरियाणा को एक हम वैलफेयर स्टेट बनाने जा रहे हैं, वहां पर देहात में सफाई भी जरूरी है। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट की ताइद करता हूं। इस छोटी स्टेट के लिए यह बहुत ही अच्छा बजट है, बड़ा प्रोग्रसिव बजट है। इस बजट से स्टेट को बहुत फायदा होने वाला ह। इस बजट के लिए मैं वित्तमंत्री महोदया को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा और प्रोग्रेसिव बजट बनाया हैं। मैं स्पीकर साहब का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का समय दिया।

(Sh. S.P. Jaiswal rose to speak.)

Mr. Speaker: Mr. Jaiswal, I have promised if minutes to the Deputy Speaker.

Lala Balwant Rai Tayal: Only five minutes.

Mr. Speaker: She wanted five minutes.

श्रीमती लेखवती जैन (अम्बाला शहर): स्पीकर साहब, वित्तमंत्री जी को मुबारिकबाद देने से पहले आपका शुक्रिया अदा करती हूं कि इस बार आपने मुझे बोलने के लिए पांच मिनट का टाईम दिया है।

स्पीकर साहब बहिन ओम प्रथा जी ने यह बहुत अच्छा बजट पेश किया है, यह लोगों की भलाई का बजट है। इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है।

स्पीकर साहब आज हमारे सामने बड़ा प्रश्न उन लोगों का है जो वीर, इस जंग में वीरगति को प्राप्त हुए हैं, घायल हुए हैं या लापता हैं। हमारी सरकार भी उसमें किसी के पीछे नहीं रही बल्कि मैं तो यह समझती हूं कि उसने ज्यादा से ज्यादा उनके लिये किया है। जब हम दूसरे प्रोविन्सिज के आँकड़े पढ़ते हैं कि उन्होंने अपने शहीद जवानों और शहीद अफसरों के लिये क्या किया है तो मैं फख हैं के साथ और विश्वास के साथ यह कह

सकती हूं कि हमारी स्टेट नम्बर वन पर है। जहाँ तक तरक्की के कार्यो का सम्बन्ध है, मै। उन्हें यहाँ पर दोहराना नहीं चाहती। मैं इतना जरूर कहूंगी कि आज इम इस चीज के लिये अपना सिर ऊचां कर सकते हैं ओर इस बात पर फख कर सकते हैं कि सारे देख में हरियाणा ही पहली स्टेट है जिसने गाँव– गाँव में इलैक्ट्रिसिटी पहुंचा दी है। आज कहने के लिये अपोजीशन चाहे कुछ भी कहे ओर यह भी इल्जाम लगाये कि अभी भी बहुत से ऐसे गाँव हैं जहां बिजली नहीं पहुंची है, मगर यह सत्य है कि हरियाणा के हरेक गांव को इलैक्ट्रिफाई कर दिया गया है। कहने के लिये तो कोई कुछ भी कह सकता है। कोई किसी को रोक नहीं सकता। अगर सूर्य निकला हुआ हो और कोई आदमी यह कह दे कि नहीं रात है और अन्धेरा है तो उसके कहने पर हम अपनी आँखें नहीं मूंद सकते। आखिरकार सच्चाई तो सच्चाई ही होती है। इसलिये हमारी सरकार जो काम कर रही है, उसे मैं बहुत सराहूंगी। किसी चीज के बारे में सजैशन दूं या अपीन कांस्टीचूयेंसी या जिले के लिये कोई बात कहूं, उसके अलावा मैं कोई बात नहीं कहा करती। आज जब मैं चेयर पर थी तो मैंने यहाँ पर हुई स्पीचिज सुनीं। उन स्पीचिज के अन्दर हमारे विरोधी दल के भाइयों ने रोज की तरह बहुत से इल्जाम लगाये। आज उनके पास इल्जाम लगाने के सिवाय कुछ नहीं है। उन्होंने एक ओर इल्जाम लगाया। उधर तो हमारे देश के नौजवान वीरगति को प्राप्त हुये हैं ओर इधर यह कहते हैं कि हमारी गवर्नमैंट इस जीत से इलैक्शन में फायदा उठाना चाहती है और .....

चौ. जय सिंह राठी: स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। बहिन जी जो बाल रहीं हैं, किस चीज पर बोल रही हैं यह कौन से बजट का हिस्सा है?

Smt. Lekhwani Jain: I know better.

Mr. Speaker: She can geneal remarks on the Budget.

चौ. जय सिंह राठी: स्पीकर साहब, मैं अभी भी प्वांयट आफ आर्डर पर हूं। इसी हाउस में चेयर की तरफ से यही रूलिंग आ चुकी है कि आप 'जनरल' नही बोल सकते।

Mr. Speaker: On Budget you can talk about general matters.

श्रीमती लेखवती जैन: स्पीकर साहब, मैं आपके सामने यह कहना चाहती हूं कि वह शब्द मुझे बहुत चुभे। मैं हाउस के सामने बड़े हौसले और साहब के साथ यह कह सकती हूं कि वे इस बात को भूल जायें। अगर हरियाणा में आज हम वोट माँगेंगे तो सिर्फ अपने कामों की वजह से या तरक्की के हमने जो काम किये हैं उनकी वजह से माँगेंगे। उस चीज के बहम को अपने दिल से ये बिल्कुल निकाल दें। पहली बात तो यह है कि अभी हमारे यहाँ इलैक्शन डिक्लेयर नहीं हुए कि हम इलैक्शन कराने जा रहे हैं। अगर हम करायें भी तो भी मैं उनको यह बता देना चाहती हूं कि अगर एक साल के बाद भी इलैक्शन हुए, तो जितनी सीटें आज हमने ली हुई हैं, उससे बहुत ज्यादा सीटें हम लेंगे। अभी तो

हमारा इलैक्ट्रिसिटी का प्रोग्राम ही पूरा हुआ है जब एक साल के बाद गाँव–गाँव में सड़कें चली जायेंगी तब देखना आपका क्या हाल होगा। आज जिनके बच्चे बीमार होते हैं या घर वाले बीमार होते हैं, सड़क की वजइ से शहर में दवा–दारू के लिये नहीं जा सकते, जब उनको सड़कें लि जायेंगी तो मरीज को शहर लाने और ले जाने में सहूलियत हो जायेगी। मैं अपोजीशन को चैलेन्ज करती हूं कि देहात के अन्दर वह शायद ही 5 प्रतिशत वोट ले सकें क्योंकि तमाम वोट बंसी लाल सरकार वाली कांग्रेस (आर) को जायेंगे। मैं सब कुछ जानती हूं, आखिरकार पुरानी तो नहीं करती, फिर भी कुछ दिनों से इस हाउस में हूं। मैंने वह गवर्नमैंट भी देखी है जब अपोजीशन वालों को, जो इस वक्त इतना क्रिटीसाइज करते हैं, एक मौका मिला था और गवर्नमैंट इनके हाथ में आ गयी थी। मैं इनके जमाने की ज्यादा चीजें तो नहीं बताना चाहती, सिर्फ एक चीज ही बताना चाहती हूं। यह एक ऐसी चीज थी जो बहुत जरूरी थी। इनके टाईम में बुढ़ापे की पैन्शन बन्द कर दी गयी थी।

Sh. S.P. Jaiswal: While speaking on the Budget, may I know whether a reference can be made to the deeds or misdeeds of the past Government? You may give you ruling.

Mr. Speaker: Yes, please, that can be done.

श्रीमती लेखवती जैन: स्पीकर साहब, इसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूं कि इससे पहले ऐसी चीजें यहाँ पर आती

रही हैं ओर यहां रवायात हैं कि हम इस चीज को कह सकते हैं। जब हमारी गवर्नमैंट के खिलाफ ये लोग एक–से–एक बढ़कर इल्जाम लगाते हैं तो मैं इन्हें बताना चाहती हूं कि आठ महीने के लिये जब इनकी गवर्नमैंट आयी तो उसके क्या कारनामे थे? माफ करना, मैं कोई गल्त शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहती .....

Ch. Jai Singh Rathi: On a Point of Order, Sir.

Mr. Speaker: I suggest, Mr. Rathi, let her speak. She has forgotten her Constituency points. So, let her go on.

श्री सत्य नारायण सिंगोल: बोलती तो उनके हक में हैं और बड़ी हमारी तरफ है। मैं तो सिर्फ जनता को यह बताना चाहता हूं कि ये उन्हीं की पार्टी की हैं।

श्रीमती लेखवती जैन: जनाब, न तो मेरे पास इतना टाईम है और न ही मेरी आदत है कि मैं किसी बात के लिये हाउस का समय बर्बाद करूं। हरिजनों के बच्चों को वजीफे देना कितना जरूरी है, मगर उस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर श्री हरद्वारी लाल जी ने, जिन्होंने हमरे एजुकेशन मिनिस्टर पर तरह–तरह के इल्जाम लगाये हैं, हरिजन बच्चों के वजीफे भी बन्द कर दिये थे, इससे ज्यादा गल्त और क्या चीज हो सकती है। स्पीकर साहब, आप कहेंगे कि आपने 5 मिनट का टाईम लिखा था। मैं 5 मिनट से ज्यादा बोलना नहीं चाहती पर क्या करूं इधर से इन्ट्रप्शन्ज हो रही हैं .....

श्री अध्यक्ष: 8 मिनट हो चुके हैं।

श्रीमती लेखवती जैन: मैं जिस चीज को कहने लगी थी वह यह है कि हमारी गवर्नमैंट ने जहां हरियाणा भर में अच्छे से अच्छे काम किये हैं, मैं इस बात से डिनाई नहीं करती ओर न ही इतनी थैंकलैस हो सकती हूं वहाँ अम्बाला में भी कुछ हुये हैं। अम्बाला में मिल्क प्लान्ट लगने जा रहा है और मैं यह भी मानती हूं कि दूसरे कामों में अम्बाला को तरक्की का पूरा हिस्सा दिया जा रहा है लेकिन मै। आपके जरिये अपने चीफ मिनिस्टर साहब से एक बात जरूर कहना चाहती हूं, बेशक मुझे कहें कि मैं लालची हूं कि हमें पानी की बहुत जरूरत है। यह मैं हमेशा ही कहती रही हूं। वित्तमंत्री साहिबा ने जो अपनी बजट स्पीच पढ़ी, उसमें गालिबन तमाम जिलों के नाम दिये थे कि यहाँ–यहाँ पर हम नलकूप लगाने जा रहे हैं। जब अम्बाले का नाम आया तो उन्होंने यह कहा कि हम नारायणगढ़ तहसील में नलकूप लगा रहे हैं। जनाब, मैं उनसे यह कहूंगी कि सारे अम्बाला जिले का क्या कसूर है? अगर सारे अम्बाला जिले में पानी है, तब तो आप बेशक नारायणगढ़ तहसील में ही नलकूप लगाइये, मगर जब नहीं है तो उसका भी ख्याल रखिए। मेरी कांस्टीचूयेंसी भी अम्बाला है और मुझे वहां का सब पता हैं। हमारी गवर्नमैंट पाने का पानी गाँव–गाँव मैं मुहैया कर रही है, मैं याद दिलाना चाहती हूं कि एक दफा चीफ मिनिस्टर साहब ने जगाधीर या जमुनागर के रैस्ट हाउस के अन्दर एक मींटिग की थी। उस मीटिंग के अन्दर उन्होंने

यह कहा कि हम, अम्बाल से जो कैनाल जा रही है, उस कैनाल के पानी को लिफ्ट करके अम्बाला को पानी देंगे।

श्री अध्यक्ष: बहिन जी, दस मिनट हो चुकें है .....

श्रीमती लेखवती जैन: स्पीकर साहब, मैं सारे सैशन में आज ही बोल सकी हूं ....

Mr. Speaker: I may tell you, Benan ji, that you are better off have me. So, please do not worry.

श्रीमती लेखवती जैन: जनाब, मैं सरकार से यह कहना चाहती हूं कि वह सिकी न किसी तरह से अम्बाला को, और नहीं तो कम से कम पीने का पानी और इररीगेशन के लिये पानी तो दें।

जनाब, मेरी एक छोटी सी मांग और है वह है कि अम्बाला के लोग चाहते हैं कि वहां पर एक आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी खोली जाए। ऐसे बहुत से लोग हैं जोकि अंग्रेजी इवाई खाना पसन्द नहीं करते हैं। जहां आपसे इतने अस्पताल खोले हैं वहां मेरे अम्बाला जिले की एक छोटी सी मांग को भी अवश्य पूरा करें। मैं अपनी बहन श्रीमती ओम प्रभा जैन जोकि वित्तमंत्री हैं उनसे एक बात कहना चाहती हूं कि आपने बजट के अन्दर बहुत कुछ रखा है, कोई चीज और कोई कौरनर ऐसा नहीं छोड़ा है जिसकी तरफ आपका ध्यान न गया हो। लेकिन अभी एक ऐसा तब्का भी है जिसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया है और वह तब्का है

हीजड़े (हंसी)। स्पीकर साहब, वे भी इन्सान हैं, और उनके अन्दर बहुत ज्यादा बैगरी है। अगर सरकार बैगरी खत्म करना चाहती है तो उनकी तरफ जरूर ध्यान दें। वे जबरदस्ती करते है, घरों में से बच्चों को ले जाते हैं और उनको युनिक बनाने की कोशिश करते हैं। सरकार की यह कोशिश रही है कि स्टेट के अन्दर से बैगरी खत्म हो जाए तो इस क्लास की तरफ जब तक ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक पूरी तरह बैगरी खत्म नहीं हो सकती। मैं एक और बात कहना चाहती हूं और वह है गांव की सैनीटेशन के बारे में। मुझे बड़ी खुशी है कि गवर्नमैंट उसके लिए एक बोर्ड बना रही है। मैं हमेशा ही यह कहती थी कि आप चाहे कितनी ही नहरें बना लें और दूसरी चीजें बना लें लेकिन जब तक गांवों की सैनीटेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा, जब तक गांवों की औरतों के टट्टी जाने का ठीक प्रबन्ध नहीं होगा तरक्की का कोई फायदा नहीं है। मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है कि इस सम्बन्ध में सरकार एक सैनीटेशन बोर्ड बना रही है।

श्रीमती ओम प्रभा जैन: स्पीकर साहब, बहन जी ने जिनका नाम लिया है अगर उनके बारे में ये कुछ सजैशन दें तो रहेगा।

श्रीमती लेखवती जैन: स्पीकर साहब, आप कहैंगे कि मैंने बहुत टाईम ले लिया है इसीलिए मैं अब खत्म करती हूं और अपनी गवर्नमेंट को मुबारिकबाद देती हूं कि उन्होंने इतना अच्छा बजट हाउस के सामने पेश किया है।

Mr. Speaker: I just want to make an observation as I owe a duty as a Speaker to my Deputy Speaker. There are two suggestions which she made last time. One was what she said just now.

Chief Minister (Sh. Bansi Lal): What? (Interruptions and laughter.)

Mr. Speaker: That I do not knw. That other suggestion which she made last time was about 'murghi khana'.

श्रीमती ओम प्रभा जैन: स्पीकर साहब, हमने मुर्गीखाने के नाम से इनको दूधखाना दे दिया है।

श्रीमती लेखवती जैन: स्पीकर साहब, मैंने लास्ट टाईम यह कहा था कि अम्बाला में मुर्गीखाना दिया है और कुछ नहीं दिया है।

चौ. जयसिंह राठी: आप मुर्गी भी खाती हैं।

श्रीमती लेखवती जैन: न मैं मुर्गी खाती हूं और न मुर्गी खाने के लिए .....

श्री अध्यक्ष: आनरेबल चीफ मिनिस्टर।

मुख्यमंत्री (श्री बंसीलाल): स्पीकर साहब .....

(At this stage Sh. S.P. Jaiswal was also standing to catch the eye of the Speaker)

Mr. Speaker: You will get time, Mr. Jaiswal.

A Voice: Is the Chief Minister intervening.

Mr. Speaker: Yes.

Sh. S.P. Jaiswal: May I through you request the Hon. Chief Minister to hear me before he invervenes. I have to say somethings and may be placing some facts before him. Therefore he may intervene after I have spoken.

श्री बंसीलाल: स्पीकर साहब, मैं इस विषय पर (व्यवधान) कोई बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, पूरे तौर से तो वित्तमंत्री ही जवाब देंगी लेकिन कुछ प्वांयट्स ऐसे हैं जिनका जवाब देना मैं मुनासिब समझता हूं। सदन में सवेरे से बजट पर जनरल डिस्कशन हो रहा है। डिस्कशन के दौरान कुछ अपोजीशन के माननीय सदस्यों ने सरकार के डिवैलपमैंट के कामों में कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी मैम्बरों की कांस्टीचुएन्सीज में डिस्क्रिमिनेशन का इलजाम लगाया। स्पीकर साहब, यह इलजाम अपोजीशन पार्टी के मैम्बरों ने सिर्फ इलजमा लगाने के लिए लगाया है। हकीकत यह है कि सरकार चाहे कांग्रेसी मैम्बरों की कांस्टीचूएंसी हो या गैर कांग्रेसी मैम्बर्ज की कांस्टीचुएंसी हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती। सरकार ने पहले फैसला किया .....

श्री हरि सिंह यादव: आन ए प्वांयट आफ आर्डर, स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत चीफ मिनिस्टर साहब का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे महेन्द्रगढ़ में डिस्क्रिनिनेशन हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: यह प्वांयट आफ आर्डर नहीं है। आप इस तरह इन्टरफियर न करें।

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, महेन्द्रगढ़ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य के दिमाग का संतुलन बिगड़ रहा होगा, सरकार के दिमां का नहीं। स्पीकर साहब, डिवैल्पमेंट का कोई काम हो सरकार कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती। इलैक्ट्रीफिकेशन के बारे में सरकार ने पहले निश्चय किया कि फलां तारीख तक हर गांव में बिजली पहुच जाएगी। उस तारीख तक हर गांव में बिजली पहुंच गई, फिर चाहे वह कांग्रेसी मैम्बर की कांस्टीचुएंसी थी या अपोजीशन मैम्बर की कांस्टीचुएंसी। इसी तरह अब सरकार ने फैसला किया है कि 26 जनवरी 1973 तक हरियाणा प्रांत के हर गांव तक पक्की सड़क पहुच जाएगी तो फिर वह किसी का भी गांव हो उसमें पक्की सड़क जरूर पहुंचा दी जाएगी। स्पीकर साहब, इसमें डिस्क्रिमिनेशन की बात कहां आती है। अलबत्ता मैं यह बात मानता हूं कि सरकार की बढ़ती हुई पापूलेरेटी से अपोजीशन बौखला गई है। स्पीकर साहब, जहां तक फल्डज का सवाल है चाहे किसी मैम्बर की कांस्टीचुएंसी हो, सरकार ने बाढ़ की रोकथाम के लिए बड़े इफैक्टिव कदम उठाए हैं और वे बड़े कामयाब रहे हैं। इसी तरह से आप नहरों के पानी को देखें। चाहे वह कांग्रेसी मैम्बर की कांस्टीचुएंसी है या अपोजीशन मैम्बर की कांस्टीचुएंसी है सभी जगह पानी देने का इरादा है।

स्पीकर साहब, सवेरे जिस समय चौ. हरद्वारी लाल एजूकेशन के बारे में बोल रहे थे (व्यवधान) पता नहीं कभी संत बना जाता है कभी चौधरी बन जाता है। मुझे ताज्जुब होता है कि वह आदमी एजूकेशन की बात करे जिसने एजूकेशन का पूरे प्रान्त में भट्टा बिठाया हो, जिसने हमेशा पढ़ाई उल्टी पढ़ाई हो। वह पढ़ा तो बहुत है मगर मुझे ऐसा लगता है कि चौ. हरद्वारी लाल जरूरत से ज्यादा पढ़ गए हैं। जरूरत से ज्यादा पढ़ने के बाद आदमी अपने दिमाग का संतुलन खो देता है। वह ला एंड आर्डर की बात कर रहे थे। मैं नहीं समझता कि ला एंड आर्डर में कहां खराबी है। आज की सरकार ने जिस ढंग से ला एंड आर्डर को कंट्रोल किया है वैसे पहले कभी नहीं किया था। स्पीकर साहब, शायद आपने भी सुना होगा, जिस सरकार में चौधरी हरद्वारी लाल थे उस समय चुनाव के अन्दर छारा गांव के जाटों को लाकर मलोहटी में हरिजनों के वोट डलवा दिये थे।

श्री अध्यक्ष: यह आपने ही बताया है।

श्री बंसी लाल: उस समय के ला एंड आर्डर से आज का ला एंड आर्डर बहुत ज्यादा अच्छा है। ऐसे आदमी को क्या कहें? अपोजीशन के मैम्बरों ने सरकार के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन का इलजाम लगाया है वह बेबुनियाद है और इन्होंने करेक्टर असिसिनेशन की पालिसी अपनाई हुई है। सरकार ने डिवैल्पमैंट के जो काम किए हैं वे जनता को नजर आ रहे हैं। अपोजीशन उसको रोक नहीं सकती। स्पीकर साहब, मैंने एक बात बारबार

दुहराई है और आज भी कहता हूं कि अपोजीशन के भाई अगर कोई अच्छी सजेशन देंगे तो सरकार उस सजेशन को जरूर मानेगी। सरकार को अपोजीशन की कोई अच्छी सजेशन मानने में झिझक नहीं होगी। डिप्टी स्पीकर महोदया ने कुछ सुझाव दिए हैं और आपने भी कुछ इंडीकेशन दिया है उन पर हम गौर करेंगे।

स्पीकर साहब, लड़ाई के अर्से में जितने ट्रक मिल्टिरी को दिये गये थे, उनके टोकन टैक्स की माफी की बात कही गयी। अभी तक तो मैं फैसला नहीं कर पाया था लेकिन मैं उनकी इस मांग को मानता हूं। जितने ट्रक मिल्टरी को काम के लिये दिये गये थे उन को एक क्वार्टर का टोकन टैक्स माफ कर दिया है। स्पीकर साहब, इसके इलावा कल चौ. चांद राम जी ने एक दो बातें कही थी, अच्छा हुआ कि वह अब हाउस में आ गए हैं और बे बड़े जोर से मुझे चेलेन्ज दे रहे थे कि दो गांवों में बिजली नहीं है और उन्होंने कहा था कि यह तो वह इस्तीफा दे देंगे और या चीफ मिनिस्टर इस्तीफा दे दे। वैसे तो उनकी यह बात ऐसी थी जैसे फूटा ठेकरा भरे बासन के साथ टकराने वाली होती है लेकिन हमने उसी वक्त इसकी जांच पड़ताल करवाई और इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड के चेयरमैन ने जो रिपोर्ट भेजी है, वह मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं और मैं समझता हूं कि इस जवाब को सुनने के बाद माननीय सदस्य को शर्म तो जरूर आती चाहिये। चेयरमैन अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं

"The facts are as under:-

1. Bothe the said 'Ababies' – Azadpur and Sarajgarh have no 'Hadbast' number nor are they mentioned in the Census Hand Book No. 2 of Rohtak district, 1961. As a matter of fact, these are parts of Chhuchhakwas and Chhuchhakwas has been duly electrified since 1958. These 'Abadies' from a part of Gram Panchayat of Chhuchhakwas and they have no Gram Panchayat of their own. Actually these are "Dhanis".

2. Azadpur (Dhani) is within a radius of 2 KM from Chhuchhakwas. It has about 30 huts and 4 pacca one room houses. Its population is in the neighbourhood of 300. Electricity is right at the door steps of this Dhani. As three tubewells near its abadi have been energized. There is no application or test report pending from this area, otherwise Board is in a position to release connections immediately.

3. Surajgarh (Dhani) has population of about 200. There are about 28 huts and 4 one/two room pacca houses. The 11 KV line is only 1.5 K.M. from the Dhani and the Board is in a position to give connections on demand. So far on application for connection has been received."

स्पीकर साहब, अब इसमें हमारा क्या कसूर है, पहली बात तो यह है कि सरकार ने 6669 गांव इलैक्ट्रीफई कर दिये हैं। दूसरा इस रिपोर्ट से यह साफ जाहिर है कि इन दोनों गांवों का कोई हदबस्त नम्बर नहीं है और न ही 1961 रोहतक की सैन्सस हैंडबुक में इसका कोई जिक्र किया गया है। असल में यह छूछकवास के ही भाग हैं जहां 1958 में ही बिजली पहुंचा दी गई थी ओर यह जो आबादी है यह छूछकवास की ग्राम पंचायत का ही

एक हिस्सा है, इनकी अपनी कोई ग्राम पंचायत नहीं हैं। वास्तव में ये घानीज हैं। जहां तक आजादपुर (घानी) का सम्बन्ध है, इसके बिल्कुल नजदीक ही बिजली गई हुई है और तीन चार टयूबवैल इस घानी के नजदीक एनरजाईड किये जा चुके हैं और इस वक्त कोई एप्लीकेशन, टैस्ट रिपोर्ट के लिये, कनैक्शन के लिये बोर्ड के पास पेन्डिग नहीं है।

स्पीकर साहब, इसके इलावा एक मैम्बर ने इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड के चेयरमैन पर थर्मल प्लांट को बेचने के और दूसरे कई तरह के इलजाम लगाये हैं। वे इलजाम बेबुनियाद और निराधार हैं। इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड का चेयरमैन एक शानदार आदमी है, उसके सब मैम्बर शानदार हैं बल्कि वह मैम्बर खुद उनके सहारे कुछ खाना चाहता था और उन्होंने उसको खाने नहीं दिया। इसके लिये तो उनको शाबाश मिलनी चाहिये। स्पीकर साहब, मैं तो कहना चाहता था कि आपोजीशन के जितने इलजाम सरकार के खिलाफ लगाये गये हैं, वे बिल्कुल बेबुनियाद ओर निराधार हैं और अगर अपोजीशन कोई अच्छा सुझाव देगी तो सरकार उनको जरूर मानेगी। स्पीकर साहब, एक और मैंबर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने डिफेन्स फंड के लिये पैसे इकट्ठे किये और कांग्रेस पार्टी को दे दिये। हकीकत तो यह है कि वह मैंबर और उसका **** और अब इलजाम हम पर लगाते हैं: स्पीकर साहब, जो डिफेन्स फंड

का पैसा इकट्ठा किया गया था उसका एक एक पैसा डिफेन्स फंड में गया और जा कांग्रेस पार्टी के नाम से पैसा लिया गया, वह कांग्रेस पार्टी को गया (शोर)

चौ. ओम प्रकाश: स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई इस हाउस का माननीय सदस्य या मुख्यमंत्री किसी ऐसे आदमी के खिलाफ इलजाम लगा सकते हैं जो कि इस हाउस का सदसय न हो? क्योंकि कई दफा ऐसी बात कही गई है, अब भी मेरा नाम आया ओर उसके साथ मेरे पिता का भी नाम लिया जा रहा है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए (शोर)

श्री बनारसी दास गुप्ता: स्पीकर साहब, यहां पर किसी का नाम तो लिया ही नहीं गया यूं ही चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है.....

चौ. ओम प्रकाश: स्पीकर साहब, मेरे साथ **** का भी नाम लिया जा रहा है, जोकि इस हाउस के सदस्य नहीं है।

Mr. Speaker: The reference to the father will be expunged.

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, एक्सपन्ज तो करवा दो पर **** स्पीकर साहब, जहां पर भी मैं दौरे पर जाता था और मेरे दौरे में जो डिफेन्स फंड का पेसा इकट्ठा होता था, उसका एक एक पैसा डिफेन्स फंड को गया ओर उसी तरह से एस.डी.ओ. के

हवाले कर दिया गया दूसरी तरफ जो पेसा कांग्रेस पार्टी के नाम से इकट्ठा हुआ वह कांग्रेस पार्टी को जाता रहा। इसके अलावा कई बार अपोजीशन की तरु से और इलजाम भी लगाये गये, बातें बनाने की कोशिश की गई कि हमारे साथ यह हो रहा है, वह हो रहा है। हमने तो स्पीकर साहब, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की। अगर किसी के साि कोई ज्यादती हो रही हो तो वे सरकार के नोटिस में लाएं, सरकार उस पर शीघ्र ही कार्यवाही करेगी और उसको इन्साफ देगी। इन शब्दों के साथ, मैं एक बार फिर अन्त में कहूंगा कि अपोजीशन ने जो इलजाम लगाये हैं, वे बेबुनियाद और निराधार हैं। अगर में कहूंगा कि अपोजीशन ने जो इलजाम लगाये हैं, वे बेबुनियाद ओर निराधार हैं। अगर अपोजीशन हमें कोई कन्स्ट्रकटिव सुझाव देती तो हम उन्हें मानने के लिये हर वक्त तैयार हैं।

चौ. चांद राम (बबैन ऐस.सी.): पर्सनल एक्सप्लेनेशन सर, स्पीकर साहब, मुझे यह मालूम ही था कि चीफ मिनिस्टर साहब कोई अच्छी भाषा इस्तेमाल नहीं करेंगे वह तो उनकी आदत ही है लेकिन मैं फिर वह बतला देना चाहता हूं कि सन् 1962 में जब इलैक्शन लड़े गये थे, उसमें सूरजगढ़ गावं के कई वोट थे और वह सन् 1962 से गांव है।

*Expunged as ordered by the Chair.

इन्होंने कहा कि 11 के.बी. लाईन सूरजगढ़ से डेढ़ किलोमीटर दूर है अगर वहां लोगों की मांग होगी, दरख्वास्ते आएंगी तो बोर्ड गांव में स्ट्रीट लाईट के कनैक्शन देगा .....

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, यह तो पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं है कोई खासत बात बताईये।

चौ. चांद राम: स्पीकर साहब, यह जो जवाब दे रहे हैं, यह गलत है।

Mr. Speaker: Could you allow me to clear this point?

चौ. चांद राम: स्पीकर साहब, आप उसको क्या कलीयर करेंगे डेढ़ मील से कोई आदमी अगर कनैक्शन लेना चाहता हैं तो उसका खर्चाउस पर डाला जाता है.....

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, यह बात गलत है। स्ट्रीट लाईट के वे हजारों कनेक्शन लेना चाहें तो हम विदआऊट फाइनेन्शयल जसअीफिकेशन दे देंगे।

चौ. चांद राम: स्पीकर साहब, अगर वे सीधी भाषा में यह कहते तो ठीक था।

Sh. Bansi Lal: I may clear one more point. Suraj Garh is a Majra. It is not a village itself.

चौ. चांद राम: स्पीकर साहब, जब इलैक्शन होगा तो इन्हें मालूम हो जाएगा।

Mr. Speaker: I have a suggestion in this regard. Why I said that, this, probably you do not knw. Suraj Garh belongs to my father-in-law. He has got some land there and some Chamars have settled down there. So what I say is that my suggestion is different. There are a numer of other small villages. There is one mangawas in the Constituency. It was established about 60 years ago but still it is a part of villge Jahaj Garh. So I would suggest Government may consider declaring these 'Dhanis' as villages where there is a population of 200 or more which will enable them to get electricity.

Sh. Bansi Lal: I may point out we cannot. Because when we declare a village a separate Revenue Estate there are certain formalities, there are certain criteria which have to be fulfilled. But so far as electrification is concerned these Dhanis are also given electricity and we are prepared to give electric connections. We say if anybody applies today he will get connection tomorrow.

Mr. Speaker: No extra expenditure?

Sh. Bansi Lal: Not at all. We say that all the 6669 villages in the State have been electrified. In that counting there is one village Chhuchhakwas and here is one voters' List for that. Azadpur and Suraj Garh are parts of Chhuchhakwas. Their voters are counted in chhuchhakwas Voters' List. These are not mentioned seaparately.

Ch. Chand Ram: This is not correct. Suraj Garh is a separate village.

Mr. Speaker: I have an experience of one such case. Mangawas is a village existing for 60 years. There are authorized Lambardars and a Panchayat.....

Sh. Bansi Lal: Have they a separate revenue estate?

Mr. Speaker: I don't think.

Sh. Bansi Lal: What I am clarifying is that we have electrifiedthe villages. If the people of Mangawas or any other village want electric connections we are prepared to supply electricity to them also.

Mr. Speaker: As far as the question of electrification is concerned, you are abosolutely correct. Mangawas has a population of 300/400. It is a separate village having its own Lambardars, Panchayat and so on but unfortunately this village is suffering because it has not been taken away from village Jahazgarh. This is a reasonably good village and it may be declared a separate village. This is my suggestion.

Sh. Bansi Lal: They should apply and we will sympathetically consider.

चौ. चांद राम: स्पीकर साहब, उन्होंने खुद कहा था कि दूसरा गांव आजादपुर है तीन सौ लोग उसमें बसते हैं शायद ज्यादा बसते होंगे लेकिन तीन सौ की इनफर्मेशन आई, मेरे ख्याल में तो ज्यादा आबादी है। वह कहते हैं कि वह छूछकवास का पार्ट

है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि तीन सौ की तो ग्राम पंचायत बन जाती है और फिर यह जो आजादपुर गांव है यह माडल विपेज बनने जा रहा है।

Mr. Speaker: So we should accept, it is not a separate revenue estate.

चौ. चांदराम: मेरी बात तो सिर्फ इतनी थी की वहां पर बिजली नहीं है।

Mr. Speaker: It has been clarified.

चौ. ओम प्रकाश: स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री महोदय ने एक इलजाम लगाया जिसमें यह कहा कि एक मैंबर और उसके पिता का यह धंधा रहा है और यही बात यह इस हाउस में बार–बार दोहराते हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि इस बारें में कोई भी इलजाम साबित करके दिखायें, सिर्फ बात कह देने से बात नहीं बनती कोई सबूत पेश करें जैसे कि हमने राष्ट्रपति को पेश किये हैं। मैं आफर करता हूं स्पीकर साहब कि आप अपने तौर पर इनक्वायरी करवा लें और अगर यह बात साबित हो जाये तो मैं बड़ी से बड़ी सजा भुगतने के लिये तैयार हूं। लेकिन इसके साथ–साथ मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि इसके साथ ही मुख्यमंत्री महोदय भी उस इनक्वायरी को फेस करने के लिये एलान कर दें। इनके खिलाफ करोड़ों रूपये की ऐलीगेशनज राष्ट्रपति के पास गई हुई हैं.....

Mr. Speaker: That is a suggestion not a point of personal explanation.

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, इनका और इनके बाप दाद का यही धंधा रहा है। इलजाम लगाने का जो काम है यह इनके खानदान का रिवाज है सारा हरियाणा ओर पंजाब इनके खानदान को जानता है।

चौ. ओम प्रकाश: जहां तक इनकी बदजबानी का ताल्लुक है उसके बारे में मैं क्या–क्या बताऊं। यह मुख्यमंत्री महोदय अगस्त के महीने में चौ. कटार सिंह के हल्का में गये .....

Sh. Bansi Lal: On a Point of Order. Sir. He is talking about Constituency. This is not personal explanation.

चौ. ओम प्रकाश: मैं तो इनकी बदजबानी की एक मिसाल बताना चाहता हूँ –

Mr. Speaker: (Addressing Ch. Om Parkash) Let me know what do you want to explain? There is no point in saying new things.

(Ch. Om Parkash then resumed his seat.)

Mr. Speaker: Mr. Jaiswal you will get nine minutes.

Sh. S.P. Jaiswal: Sir, I have risen atleast 20 times today and now I am to be given only 9 minutes. In this time I will nt be able even to start my speech.

Mr. Speaker: I have my reasons for this. The amount of time was agreed upon between the two sides and there are only nine minutes left to this side (Opposition). I am afraid you cannot get more than 9 minuts.

Sh. S.P. Jaiswal: I am an Independent Member and separate time should have been given to me. In these nine minutes I will not be able to say anything.

Mr. Speaker: Then you will be given time tomorrow.

Sh. S.P. Jaiswal: Sir, my time was earmarked by the Hon. Chairman.

Mr. Speaker: But no time is left now. If you do not want let Mr. Rathi speak.

Sh. S.P. Jaiswal: I request for atleast 20 minutes.

Voices: You start speaking, time will be given.

Mr. Speaker: I will give you 10 minutes.

Sh. S.P. Jaiswal (Karnal): Mr. Speaker, a lot of mention has been made about development in the State and a lot of money of the State is said to have been spent on these programmes of development. Sir, to see the effect; to see whether development has really taken place we should look into the effect of the development. This morning an Hon. Member or this House brought to the notice of this Hous that canalshave been made but there is not water; roads have been ade but before they proceed further portions which were made earlier are breaking; ther eis no maintenacne. Then Sir, about the electrictiy ther are a number of break-downs during the

working hours of the so-called electricity supply which is some times 9 to 10 hours out of 24 hours. I we recently in an area of Kalka where there was a break-down for two days, all this at a time when people require electricity for watering their fields of wheat. The reasons is the same; poles have been installed, the wiring has been done, the connections have been given but there is not enough power. If you remember, Mr. Speaker, I had in my last address to this House, drawn the attention of this House to the statement of the Chairman of Electricity Board itself in which he said that as a result of rural electrification which we have achieved this year ther are bound to be break-downs; there is bound to be short-supply; there is bound to be no electricity in several places. Then, Sir, speaking about thedevelopment, a part of it a very important part of the development which has not been mentioned by the Hon. Finance Minister inthe Budget Speech is corruption in the Administration. You heard some Hon. Members from this side and Mr. Gupta of the other side who spoke about corruption and said that corruption in the Administration of Haryana is rampant. Sir, the criteria of a good Government is propargation of democracy, good and healthy democracy; propagation of Rule of Law; and controlling and providing a good, clean Admininstration to the people. Sir, you have already heard about the tratment meted out to democracy in this infant State. You have also heard the speaker about the casualty of Rule of Law. I am now drawing your attention to the Administration, i.e. the manner in which the Administration in this State is functioning Sir, corruption is rampant in this State. Some of the places which are the sources of corruption are the Tehsildars in the State; S.D.O.s (Civil); Deputy Commissioners, Town Planners, the Periphery

Control Offices, the Improvement Trusts, the Public Analyist, the Electricity Department and Civil Supplies Offices. (Interruption and Noise). May I request, Sir, that there should be no interruptions.

Mr. Speaker: No interruptions please.

Sh. S.P. Jaiswal: Sir, one of the reasons for this corruption is the collection of funds through the Administratio by our Government which, I would, with all the emphasis at my command, request the Government to stop.

(Talking and interruptions in the House)

Mr. Speaker: No talking across the Tables, please.

Sh. S.P. Jaiswal: These Funds are the District Relief Fund, the Red-Cross Funds, the Savings Fund and so on. These Funds, Sir, are collected not voluntarily, I repeat not voluntarily. The people are coerced into contributing towards these Funds. I am aware of the Defence Fund which has been collectged in this State from the agriculturists and the other people. In the cases of the agriculturists, they have been made, by force, to pay three times to land revenue. The D.C.s, and the S.D.Os., have threatened them to contribute to the Defence Fund. (Interruptions by Sh. Banarsi Dass Gupta).

Mr. Speaker: No interruptions please.

Sh. S.P. Jaiswal: Sir as I was submitting these are some of the methods adopted to collect the money. Some of the other methods, besides these coercive measures, is the refusal or register sales. Tehsildars refuse to register sales unless money is paid. No 'Intkal' is made unless money is paid. This is so, although the Hon. Chief Minister, in the last session had given an assurance that no money shall be collected by the Tehsildars for any Funds at the time of registration and Intkal. This is still going on. It has not stopped at all, Sir. Then, Sir, the other method by which the money is collected is that the authorities concerned refuse to grant bails under Section 107/151 Cr.P.C., unless money is paid. I know of a case where Rs. 10000 were demanded for deposit in the Savings Scheme. To demand a sum of Rs. 10000 thus for the grant of bail is really shameful. (Interruptiosn and Noise). May I know, Sir, whether a running commeentary is allowed in the House when a Member is speaking?

Mr. Speaker: No interruption please. The Honourable Member should carry on.

Sh. S.P. Jaiswal: Sir, as I was saying, there is yet another thing. The S.D.Os., and the D.Cs., are openly refusing to grant arms licences to the citizens unless they pay. Are the citizens in Haryana let with no rights and no privileges? What have they got? They got nothing unless they pay for it. They cannot get an arms licence unless they pay for it. They cannot get intkal or registration doen without paying for it. It is indeed a most disgraceful state of affairs if the rights of the citizens are trampled upon like this. It this the socialism about which our Government is preaching and making

speeches every day. It cannot be denied that the citizens are left with not rights and no privileges. But, at the same time, you take away taxes from them, you take away income tax, you take away sales-tax, professional tax, property tax, house tax and numerous other taxes. Then you take away the very shirt from their backs by going to them and resorting to coercive measures for donating to the various Funds. This is something to which the Government must pay attention. This practive of collecting funds must stop. The citizens are paying enought as taxation. If the money is needed for the State, it should be collected by enacting suitable legislation. You collected funds for the Bangla Desh refugees for which you brought in taxation measure. This is what you should do. But, you must stop the coercive and disgraceful methods. I know how Tehsildars ar taking money. The Tehsildar says, “If you want a receipt, pay so much; if not, then pay so much.” This is highly undesirable. Therefore, if you want to collect funds, you should collect them through legislation and not by such coercive methods. Let Administrative machinery function in a manner where there is no collection by it by coercive measures. The second reason for corruption which I would like to point out is vesting absolute discretion in the administration. In the legislation, which have been recently passed, discretionary powers, absolute powes, are being vested in this administration. I would like to warn the Government through you. Sir, that this is the same administarion which was prevalent at the time to the British Government. The pattern of the Administration is the same. This is the colonial pattern of administration. In the colonical rule, the king id dnot come here to sign the documents and orders nor did the Viceroy. It was this administration through which the people

were ruled. In fact, anyone who gets into this Administrative pattern, develops the urge to rule and not to seve. The Administators are public servants and not officers and they must learn to seve the people. So, this administrative pattern must be changed so as to benefit the commonman.

Mr. Speaker: You have only two more minutes to speak.

Sh. S.P. Jaiswal: I may be given more time, Sir. As I was saying this the colonial apttern of Administation. The officers have unlimited powers, discretion and privileges. Unless you take away their privileges, and so their arrogance, there can be no improvement. You know, Sir, how the poor people live. They have not houses, as compared to this, the officers live in big Government Bunglows, where they pay only Rs. 80 or Rs. 100 as rent according to their pay. You cannot imagine. Sir, how the poor people in this country are living. Their conditions are miserable. You talk of development. I say there is no development. One of the Honourable Lady Members has right said that those who prepare shoes for others, have no shoes to wear. Similar is the case with agriculturists who produce so much for others, but have not wheat for themselves. You talk of development. But, in fact, you are taking away more and more money from them.

Mr. Speaker, Sir, there is no doubt that the administration has to be put right, and Sir, the function of this Government, the main function of this Government is to give clean administration to

6.00 P.M.

the people. Sir, I would submit that the Government should consider ways and means for bringing down these administrators, these public servants to the level of the public. Mr. Speaker, the Rajas and Maharajas have been brought down. Similarly we need to bring down the services because unless they come down to the level of the people whom they have to serve, they will nto do much for them. Unless they are brought down to the level of the people ther will be no change. What an irony of fate, Mr. Speaker, that the poor poeple who themsevles have no houses to live in and no food to eat and yet they are made to pay for the administrators houses, Rent Houses, their places of joy such as the Uchana Lake Project. They are pyaing for their big houses, for the luxurious houses worth over Rs. 1500/- per mensem, and their Rest Houses. I had proposed to the Hon. Chief Minister last time that these Rest Houses should be opened to the citizens. Let them be entitled to stay in these Rent Houses. Let them enjoy the facilities to the same extent as the public servants are enjoying. But his reply was that he did not wat to reduce these Rents Houses to the level of serais. If our citizens are entitled to stay only in serais, them let these public servants or so called officers also come down to the level of serais so that they know how the people live. It is then and then alone that they will know the problemsand troubles of the people. They should know the difficulties and problems of the people and they would know them only if they are brought down to the level of the people. If they are nto brought down to the level of the people, they will remain in different to their plight.

I notice, Sir, that you are looking towards me and the watch. I will, therefore, sit down. Thank you.

*Expunged as ordered by the Chair.

वित्तमंत्री (श्रीमती ओम प्रभा जैन): माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट के जनरल डिसकशन में हमारे काफी साथियों ने भाग लिया और उन्होंने सरकार की बातों की आलोचना भी की है और प्रशंसा भी की है। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि सदन के सभी वर्गों की ओर से, सभी दलों की ओर से हमारे वीर सेनानियों के प्रति श्रद्धांजति अर्पित की गई हैं जिन्होंने देश की इज्जत और देश की प्रतिष्ठा बनाने में अपने को शहीद किया। आज हम सब उन महान् आत्माओं के लिए नत–मस्तक हैं और ईश्वर से उनकी आत्माओं की शांति की प्रार्थना करते हैं।

स्पीकर साहब, यह सही है कि लड़ाई का बोझ हिन्द सरकार पर पड़ा मगर हरियाणा में, तकरीबन एक बोर्डर स्टेट होने के कारण यहां पर भी कुछ सिविल रिसपौंसिबिलिटीज और दूसरे तरीके के खर्च हुए जो कि सरकार ने और जनता ने बड़ी खुशी से वहन किए।

स्पीकर साहब, मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि लड़ाई के बाद बहुत डिफिकल्टी होती है और खासतौर से ऐसी हालत में जबकि अन्तर्राष्ट्रीय मुल्कों की ओर से हमको एड खत्म करने की धमकी भी रहती हो। हमको अपने पैरों पर स्वयं खड़ा होना है,

हमें आत्म निर्भर बनना है, चाहे ऐग्रीकल्चार की प्रोडक्शन है, चाहे इंडस्ट्रीज हैं और चाहे लोगों को दूसरी सुविधाएं देने की बात है। उन सुविधाओं को भी हमको स्वयं एकत्रित करना है और साथ ही साथ हमको किफायत भी करनी है ताकि हम अपनी अर्थ व्यवस्था को स्वयं ही बना सकें। स्पीकर साहब, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है ओर गर्व भी है कि हरियाणा में पिछले तीन–चार सालों में बहुत जबरदस्त और शानदार काम हुआ है। हमारे कुछ माननीय सदस्य बेशक आंखों पर पट्टी बांध लें, वह बात दूसरी है लेकिन जनता के बीच हर आदमी हरियाणा का ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान का बच्चा–बच्चा आज यह महसूस करता है कि हरियाणा के अन्दर बहुत प्रगति हुई है ओर यहां तक लोग करते है कि हरियाणा आज हिन्दुस्तान में सबसे खूबसूरत तस्वीर इस मामले में हासिल किए हुए है (विघ्न)।

स्पीकर साहब, बजट स्पीच में इस बात को कहा गया है कि हमारी पर–कैपिटा इन्कम बहुत बढ़ी है और मैंने यह भी कहा कि साल 1969–70 की प्राइसिज के हिसाब से बढ़ी है। आज हम हिन्दुस्तान में दूसरे नम्बर पर हैं जबकि तीन चार साल पहले हम महाराष्ट्र और गुजराम से पीछे थे। आज हम उनसे आगे निकल गए हैं। हरियाणा के अन्दर पर–कैपिटा प्लान ऐक्सपैंडीचर सबसे ज्यादा है। इसके अलावा, स्पीकर साहब, हमारे यहां फूड प्रोडक्शन के अन्दर जो एरिया है वह हिन्दुस्तान के टोटल ऐरिया का 1.4 प्रतिशत है लेकिन हमारे यहां फूड प्रोडक्शन 4.4 प्रतिशत हे जो

कि पर–कैपिटा के हिसाब से सबसे ज्यादा पड़ती है। इसी तरीके से, स्पीकर साहब, हमने जो बजट पेश किया है वह बड़ा ऐनकरेजिंग है। मुझे इस बात की खुशी होती है कि जो इस साल का हमारा खर्चा है वह री–आर्गेनाइजेशन से पहले समूचे पंजाब का, जिसके अन्दर हरियाणा शामिल था, जितना खर्चा होता था उससे ज्यादा है। (विघ्न)

चौ. जय सिंह राठी: आन ए प्वांयट आफ आर्डर, स्पीकर साहब। मित्तल साहब बोलने से रूकते नहीं, फाईनैन्स मिनिस्टर साहिबा बोल रही हैं और हम इनको सुनना चाहते हैं मगर मित्तल साहब सुनने नहीं देते।

श्री के.एन. पोसवाल: जनाब, यह ऐलीगेशन बिल्कुल गलत है। वे तो मुश्किल से आंख भी नहीं खोलते।

श्री अध्यक्ष: आपका मतलब है कि वे सोते रहते हैं। (हंसी)

श्री के.एन. पोसवाल: जी नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि वे बड़ी शांति और ध्यान से सुनते रहते हैं।

श्रीमती ओम प्रभा जैन: स्पीकर साहब, मैं यह अर्ज कर रही थी कि प्री–रीआर्गेनाइज्ड पंजाब जो था, जिसमें आज का मौजूदा हरियाणा ओर इससे डयोढ़ा पंजाब भी शामिल था, उसका सन् 1964–65 का बजट 255 करोड़ का था लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे बजट की रैवन्यू रसीट 250 करोड़ की है ओर

ऐक्सपैंडिचर 265 करोड़ का है। इससे आपको पता लग सकात है कि हरियाणा ने पिछले तीन–चार सालों में कितनी बड़ी भारी तरक्की की है। स्पीकर साहब, पंजाब के अन्दर फर्स्ट टू प्लांज में 279 करोड़ रूपया खर्च हुआ है और उसकी थर्ड प्लान, जिसका बाद में कुछ थ्हस्सा हरियाणा को मिला, 346 करोड़ की थी लेकिन अब हरियाणा का जो फोर्थ फाईव इयर प्लान हम बनाने जा रहे हैं वह 370 करोड़ से ऊपर का जाएगा। इससे किसी हरियाणवी को गर्व नहीं होगा और कौन नहीं मानेगा कि हमारे यहां प्रगति के चरण तेजी से उठेंगे। (व्यवधान)

स्पीकर साहब, मैं हाउस की इत्लाह के लिए बतलाना चाहती हूं कि हरियाणा बनने के बाद हमारे यहां 1968–69 का सारा बजट 126 करोड़ का था, 1969–70 का 140 करोड़ का हुआ, 1970–17 का 160 करोड़ का हुआ, 1971–72 का 179 करोड़ का हुआ और 1972–73 का 250 करोड़ का हुआ। मैं, स्पीकर साहब, यह भी बताना चाहती हूं कि यह पैसा टैक्सों के जरिए नहीं बल्कि सरकार की नीति की वजह से बढ़ा है। सरकार क नीति इतनी प्रगतिशील रही है कि जहां हमने ऐग्जिसटिंग टैक्सीज से अच्छी वसूली की है वहां हमने इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाया है जिसमें हमने फाइनेंशियल क्रेडिट को अधिक से अधिक इस्तेमाल करने की कोशिश की है।

स्पीकर साहब मैंने कुछ अखबारों में कमेन्टस पढ़े है। कुछ ने कहा कि बड़ा फीका बजट है। राठी साहब ने तो यहां तक

कह दिया कि भट्ठा की बैठ गया है। मेरी यह समझ में नहीं आया कि बजट का भट्ठे से क्या सम्बन्ध है? कई ने बड़ा फीका और निराशाप्रद कहा परन्तु मैं उनसे यही कहूंगी कि कम से कम वे कुछ तो सच कह देते। अगर ये ऐसे दिन नहीं आने वाले हैं कि इससे अच्छा और प्रगतिशील बजट ये पेश कर सकें।

चौ. जय सिंह राठी: आन ए प्वांयट आफ आर्डर सर। मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा और आपने पहले भी कहा हुआ है कि अगर कोई पर्सनल मामला हो तो उसके बारे में पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। अभी फाइनेन्स मिनिस्टर साहिबा ने मेरी किस्मत के बारे में कहा है इसलिए मुझे पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने का टाईम दिया जाये।

Mr. Speaker: This is not Point of Order. You can ask for time later for giving personal explanaation. But interruptions are not desirable. How will you feel when you are making a speech if somebody interrupts you? I would request the Members not to interrupt the Finance Minister when she is speaking.

श्रीमती ओम प्रभा जैन: मुझे बड़ा अफसोस है कि राठी साहब छोटी सी बात पर ही पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने के लिए खड़े हो गये। मैंने उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं कही है। एक पार्टी के मैम्बर दूसरी पार्टी के मैम्बर्ज को ऐसे कहते ही रहते हैं। इन्होंने हमारी पार्टी के विषय में इससे भी बुरे लफ्ज कहे होंगे।

चौ. जय सिंह राठी: आज तो मैं बोला ही नहीं, कल बोलूंगा तब कहूंगा।

श्रीमती ओम प्रभा जैन: स्पीकर साहब, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारे बजट का टोटल अमाउन्ट 126 करोड़ से बढ़कर 250 करोड़ तक पहुंच गया है। मैं हाउस को यह भी बता देना चाहती हूं कि सन् 1967–68 मे ंरेविन्यू रिसीट्स 6181 करोड़ रूपये की थी आज सन् 1972–73 में 141 करोड़ तक पहुंच गयी है। यदि आप टैक्सिज का हिसाब लगायें तो हमारी सरकार ने कोई लम्बे–चौड़े टैक्सिज नहीं गलाये हैं। हमने कहीं दो से तीन परसेन्ट किये या कहीं छः से सात परसेन्ट किये हैं। मैंने सारे टैक्सिज की लिस्ट को देखा है, कोई खास नहीं बढ़ाये हैं जो जनता को दुखने और तकलीफ देने वाले हों।

सन् 1967–68 में हमारा सांइटिफिक एजूकेशन एंड सोशल डिवल्पमैंट एक्टीविटीज पर 10 करोड़ 66 लाख रूपया खर्च होता था परन्तु अब हम 20 करोड़ और 38 लाख रूपया इस साल खर्च करने जा रहे हैं। इसी तरह से मैडीकल ऐंड हैल्थ पर तीन करोड़ 27 लाख रूपया खर्च होता था परन्तु अगले साल 10 करोड़ 56 लाख रूपया खर्च करने जा रहे हैं। कैपिटल एक्सपैंडिचर पर भी जोर दिया गया है। यह 1967–68 में नौ करोड़ 43 लाखथा अब 50 करोड़ से भी अधिक हो गया है यानी पांच गुना ज्यादा कैपिटल एक्सपैंडिचर बढ़ा रहे हैं। हम अपने सोशल सर्विसीज और दूसरे कामों को भी काफी बढ़ रहे हैं ओर मैं समझती हूं कि इससे

हरियाणा के अन्दर प्रगति करने मे बड़ी भारी सहायता मिलेगी। मुझे यह कहते हुए भी बड़ी खुशी होती है कि हमने अपने रिसार्सीज को राज्य की डिवैल्पमैंट में लगाया है। हमारे यहां बहुत सी कारपोरेशन्ज और बोर्डज भी बने हैं। कल चौधरी चांद राम जी प्रैस वालों को कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार की इन्डस्ट्री की पालिसी इन्डीविजुअल को लाइसेंस देने की है या प्राइवेट सैक्टर को स्ट्रेन्थन करने की है। मैं हाउस को यह बताना चाहती हूं कि हरियाणा बड़ा प्रगतिशील प्रान्त है जिसके अन्दर कारपोरेशन्ज ने बड़ा भारी रोल अदा किया है, कारपोरेशन्ज की बड़ी भारी इन्वैस्टमेंट है इन कारपोरेशन्ज से सरकार को काफी मदद मिली है। सरकार जहां अपनी तरफ से इन पर कुछ पेड–अप कैपिटल लगाती है वहां इनके लिए हमें इंस्टीच्यूनल क्रेडिट भी मिलता है। अब पोजीशन यह है कि सन् 1970–71 में जहां हमारी कारपोरेशंज और बोर्डज को लगभग 61 करोड़ यप्या मिला वहां 1972–73 में इंस्टीच्यूशनल क्रेडिट का 94 करोड़ रूपया पब्लिक सैक्टर द्वारा हम हरियाणे में इन्वैस्ट करने जा रहे हैं। यह बड़ी भारी अचीवमेंट है। मैं समझती हूं कि यह कारपोरेशंज पब्लिक के हितों के लिये हैं और स्टेट को इनसे बड़ा भारी लाभ हो रहा है।

हमारे यहां वेअर हाउसिंग कारपोरेशन भी है। कुछ मेम्बर साहिबान को इस विषय में शिकायत थी कि फसल स्टोर करने का प्रोपर इंतजाम नहीं है जिसकी वजह से फसल खराब हो जाती हैं मैम्बर साहिबान ने इस बजट में देखा होगा कि 61 लाख

रूपया इनके लिए करन्ट ईयर में दिया है और दो करोड़ से अधिक रूपया वेयर–हाउसिंग कारपोरेशन्ज में अगले साल लगाने जा रहे हैं।

एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन के जरिए हम बहुत ट्रैक्टर खरीद रहे हैं। अभी हम तीन हजार ट्रैक्टर बाहर से इम्पोर्ट करने का रहे हैं और साथ ही साथ स्माल फारमर्ज को भी ट्रैक्टर सर्विस बहुत अच्छी दे रहे हैं।

यहां पर बिजली, सड़कें और नहरों की भी चर्चा हुई। ये तीनों तीजें समाजवाद के चिन्ह हैं। हमारी सरकार ने इन तीनों बुनियादी जरूरतों को मुहैया करने का पूरा–पूरा प्रयत्न किया है। हरेक अर्थशास्त्र को जानने वाला मानेगा कि राज्य में अगर मूलभूत सुविधायें न हों तो राज्य की तरक्की नहीं हो सकती। इसलिए हमारी सरकार ने लोगों को मूलभूत सुविधायें प्रदान करने की पहले कोशिश की है। हमने नहरें और पीने का पानी महेन्द्रगढ़ और हिसार के इलाकों में पहुंचाना है जहां पर कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी यहां पर पानी भी आएगा। आज राजस्थान वाले ताज्जुब करते हैं, उनके बार्डर तक पानी पहुंच गया है, हरियाणा के गांव–गांव ने बिजली पहुंच गयी है। जब राजस्थान और पंजाब के आसपास क इलाके के लोग हरियाणा के गांव में बिजली चमकती हई देखते हैं तो बड़ा ताज्जुक करते हैं कि हरियाणा ने इतने थोड़े से समय में इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है। इसी प्रकार से सड़कों का प्रोग्राम बड़ी भारी तेजी के साथ

चल रहा है। जहां हमने अपने मीन्ज आफ प्रोडक्शन बढ़ाये हैं वहा हमने मीन्ज आफ डिस्ट्रिब्यूशन बराबर बांटे हैं। आज हमारी सरकार इस बात की इच्छुक है कि हरेक गरीब तबके के आदमी को फायदा पहुंचे। हमारी जितनी भी कारपोरेशन्ज बनी हैं, हम चाहते हैं उनके माध्यम से छोटे तबकों के लोगों को फायदा पहुंचे।

हमारे यहां डेरी डिवैल्पमेंट कारपोरेशंज बनी हैं। हमारा हरियाणा जहां पहले दूध–दही का खाना माना जाता था और गाय–भैंस दूसरे प्रदेशों को जाती थीं, उनके लिए हमने जींद के अन्दर एक मिल्क प्लान्ट लगाया है, इसी तरह भिवानी में भी लगा रहे हैं, अम्बाला में भी लगेगा। इस तरह से मिल्क प्लान्ट लाग कर हम छोटे छोटे दुधियों की कोआप्रेटिव सोसायटीज बनाना चाहते हैं। हम मार्जिनल फारमर्ज और स्माल फारमर्ज को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। हम इन लोगों को गाय और भैंस खरीदने के लिए लोन भी देना चाहते हैं ताकि ये अपनी आमदनी बढ़ सकें ओर इनको दूध की पूरी कीमत मिल सके।

इसके अलावा हमने हरिजन कल्याण निगम बनाया हुआ है। उसमें से भी हरिजनों को लोन दिया जायेगा। हमारी जो कोआप्रेटिव क्रेडिट सोसाइटीज और मिल्क सोसाइटीज बनी हुई हैं उनमें भी लोन मिलेगा। हमारी स्माल फारमर्ज एजेन्सीज अम्बाला, गुड़गांव में हैं और मार्जिनल फारमर्ज एजेन्सीज अम्बाला और हिसार जिले में हैं इनमें भी गरीब और निर्धन तबके के लोगों को लोन दिया जायेगा ताकि वे आर्थिक रूप से उठ सकें।

चौ. चांद राम जी ने कहा कि हरिजनों का अर्थ वर्क ही करना पड़ता है। ठीक है अर्थ वर्क करना पड़ता है परन्तु हम काम तो दे रहे है। हमारे यहां बड़ी तेजी के साथ नहरें खोदी जा रही हैं। अस्सी हजार के करीब लेबर वैस्टर्न जमन कैनाल पर लगी हुई हैं। इसके आलावा दूसरी नहरें जो हिसार और महेन्द्रगढ़ में खोदी जा रही हैं उन पर भी काफी लेबर लगी हुई है। आज के दिन पी. डब्लू.डी. एंड बी.एंड.आर. में अस्सी हजार से भी अधिक लेबर काम कर रही है केवल हमारी ही स्टेट के नहीं बल्कि दूसरी स्टेट्स के लोग की हमारे यहां काम कर रहे हैं। यह जरूरी नहीं है कि हम हरिजनों से मिट्टी का ही काम करवाना चाहते हों। हम उनको हरिजन कल्याण निगम से लोन दे कर या किसी अन्य तरीके से भी ऊपर उठाने का प्रयन्न कर रहे हैं। स्पीकर साहब हमारी स्टेट में मजदूरी और स्टेट्स के मुकाबले में ज्यादा है। मैं हाउस को यह बताना चाहती हूं कि हमने मिनिमम वेजिज एक्ट इस साल कई फैक्टरीज में एक्सटेन्ड किया है। हम चाहते हैं कि कम से कम हरेक फैक्टरी में वेजिज मुनासिब तौर पर मुकर्रर किय जायें।

स्पीकर साहब, हमने एक हाउसिंग बोर्ड भी बनाया है। उसका काम शुरू हो गया है। हमने स्टेट की तरफ से उसको 35 लाख रूपया दिया है और इसके अलावा 25 लाख रूपया सैन्ट्रल गवर्नमेंट के हाउसिंग एंड अरबन डिवल्पमेंट कारपोरेशंज की तरफ से भी मिला है। हमने और भी बहुत सी स्कीमें बनायी है ओर आप इस बात को ऐप्रिशिएट करेंगे और अपोजीशन के भाइयों को भी

करना चाहिए कि सरकार ऐसी गवर्नमेंट एजेन्सी बनाना चाहती है जिसमें लोगों का भी कोआपरेशन हो और सरकार का भी हो। उससे सरकार को भी फायदा हो और आम लोगों को भी फायदा हो।

हमारे हाउसिंग बोर्ड ने भी काफी तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि अगले साल 500 मकान लेबर के लिए और 500 मकान लो–इनकम ग्रुप के लोगों के लिए बन जायेंगे।

हमने ट्रांसपोर्ट के लिये कोई कारपोरेशन नहीं बनायी है। इसके बावजूद भी हमें ट्रांसपोर्ट में राष्ट्रीकरण के काफी फायदा हुआ है। यह सही है कि कई जगह हमारे यहाँ बसिज की कमी है लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हरियाणा को ट्रांसपोर्ट सर्विस आज हिन्दुस्तान के अव्वल नम्बर पर है। यही नहीं हमारा पर–किलोमीटर प्रोफिट भी बहुत ज्यादा है। हमारी बसें बिल्कुल ठीक टाईम पर चलती हैं। उनकी मेन्टेनैंस भी ठीक तहर से होती है, यह अलग बात है कि हमारे यहाँ कभी वौल्यूम आफ वर्क इतना हो जाता है कि हमारे लिये उसको कोप–अप करनो मुश्किल होता है। ट्रान्सपोर्ट के जरिये हमें जो आदमनी हुई है, उससे हमें यह अवसर मिला है कि हम उसे डिवैल्पमेंट के लिये खर्च कर सकें।

हमने अपने यहाँ एक माईनर इरीगेशन कारपोरेशन बनाई है। मुझे सदन को यह बताते हुए बहुत खुशी होती है कि

इस कारपोरेशन ने बहुत प्रैक्टीकल काम करके दिखाये हैं। चौ. लाल सिंह जी हमेशा इस बात की सरकार को दाद देते रहे हैं कि हम बड़ी तेजी से टयूबवैल लगाते जा रहे हैं। हमने बड़े–बड़े रिग्ज लगा कर, रौक्स के नीचे साढ़े तीन–तीन सौ फुट डी प तक जाकर खुदायी की है। आशा की जाती है कि एक–एक टयूबवैल तीन–तीन सौ एकड़ जमीन की सिंचाई करेगा। इस कारपोरेशन द्वारा अब तक 239 टयूबवैल लगाये जा चुके हैं और उनमें से 61 टयूबवैल्ज के पानी देना भी शुरू कर दिया है। इस स्कीम के अन्तर्गत इस वर्ष 300 टयूबवैल्ज लगाने की योजना है। इसके अलावा बल्लभगढ़ तथा पलवल में 100 टयूबवैल लगाने की भी एक योजना है। मारकण्डा और टाँगरी नदी के बीच में भी हम 100 टयूबवैल्ज लगाना चाहते हैं। यह अन्दाजा है कि यह प्रोग्राम अगले दो साल में पूरा हो जायेगा। इसके अतिरिक्त माईनर इरीगेशन टयूबवैल कारपोरेशन, वैस्टर्न जमुना कैनाल में और अधिक पानी मुहैया करने के लिये बड़ी तेजी के साथ काम कर रही है। इस साल के आखिरी माह, दिसम्बर तक माईनर इरीगेशन टयूबवैल कारपोरेशन द्वारा 180 टयूबवैल और लगाये जाने की आशा है। इनके जरिये 500 क्यूसिक पानी वैस्टर्न जमुना कैनाल में और ज्यादा चलेगा। इस तरह से 500 क्युसिक पानी तो यह मिलेगा और 500 क्यूसिक पानी वह मिलेगा जो पहले सीपेज में वेस्अ चला जाता था। इस प्रकार से वैस्टर्न जमुना कैनाल को 1000 क्यूसिक पानी और मिलेगा जिससे पहले यह महरूम रह जाती थी। हमारे यहाँ कोआप्रेटिव सोसाइटीज द्वारा कोआप्रेटिव क्रैडिट भी बहुत

भारी दिया गया है। मैं आपके द्वारा सदन को यह बताना चाहती हूं कि शार्ट एडं मीडियम टर्म एग्रीकल्चरल क्रैडिट के अधीन 18 करोड़ 50 लाख रूपया हम अगले साल में किसानों को देने वाले हैं। इसी प्रकार से लान्ग टर्म क्रैडिट 14 करोड़ रूपया माईनर इरीगेशन कारपोरेशन के लिये, ए.आर.सी. से लोन 314 लाख रूपया मैकेनाइज्ड फार्मिग के लिये, वर्ल्ड बैंक से जो लोन हमें मिला है वह है 6 करोड़ 95 लाख, वेअर हाउसिंग कारपोरेशन के लिये 45 लाख रूपया हमको अभी मिलना हैं मार्किटिंग फैडरेशन के लिये 28 करोड़ रूपये हैं। इस प्रकार से हमें, जो कोआप्रेटिव क्रैडिट ओर इन्सटीटयूशनल लोन्ज हैं, उससे बहुत भारी मदद मिल रही है। इस प्रकार हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल हम 94 करोड़ रूपये, जैसे मैंने कहा है, अपने खुद के रिर्सोसिज के ओवर एंड अबव, हरियाणा में लगाने वाले हैं।

जहाँ मैंने माईनर इरीगेशन टयूबवैल कारपोरेशन का जिक्र किया, वहाँ मुझे अपनी इंडस्ट्रियल डिवैल्पमैंट कारपोरेशन का भी जिक्र करना है। जो बजट पेश किया गया है और खासतौर पर से जो बजट स्पीच है, उसमें यह कोशिश की गयी थी कि हरियाणा में जो इंडस्ट्रियल डिवैल्पमैंट के काम हुये हैं, उन्हें एक डाकुमैंट की शक्ल में पेश किया जाये। मैं यह समझती हूं कि उन सब चीजों का एक बहुत एग्जाहस्टिव तरीके से जिक्र किया गया है। आप इस बात को देखिये कि हमारे यहां हरियाणा में पब्लिक सैक्टर में इंडस्ट्रीज लगाने के लिये गवर्नमैंट आफ इंडिया से फार

दी फर्स्ट टाईम कुछ लाइसैंस मिले हैं। हमें जो लाइसैंस मिले हैं उनमं ब्रिउसी, ग्लास बौटल्ज, टैनरी, सिगरेटस, स्टील, ब्लेड्स, नाइलोन, टिशु पेपर, मारबल्ज, और मैच बौक्स के हैं। इसके अलावा तीन और प्रोजैक्टस, फर्टीलाइजर कास्टिक सोडा और स्पंज आयरन पर भी हम काम शुरू करने वाले हैं। 1967–68 के बाद हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज की बहुत भारी तरक्की हुई है। पहले जहाँ हरियाणा स्टेट में हर साल 300–400 स्माल यूनिटस बढ़ते थे वहाँ 1970–71 और 1971–72 में एक–एक हजार स्माल यूनिट्स हर साल में बढ़े हैं।

Mr. Speaker: Behanji you have five minutes more. Do you want more time.

श्रीमती ओम प्रभा जैन: 5 मिनट और दे दीजिए।

Mr. Speaker: The House is extended by five minutes.

श्रीमती ओम प्रभा जैन: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा हाउस को यह बताना चाहती हूं कि हमारे प्रदेश में एग्रीकल्चर के अन्दर बड़ी भारी तरक्की हुई है। हमने लोगों को इरीगेशन की सुविधा दी, अच्छे बीच उपलब्ध किये और प्रोक्योरमैंट के साधन उपलब्ध किये। हमें फूड कारपोरेशन आफ इंडिया से बहुत देर बाद पैसा मिलता है। हमें अपनी स्टेट के साधनों से ही या किसी अन्य प्रकार से, बैंकों आदि से पैसा लेकर अनाज परचेज करना पड़ता है। पिछली बार हमारे यहाँ 80–90 करोड़ रूपये की परचेज हुई

और इस प्रकार फार्मर्ज को अनाज की ठीक प्राईम मिली और उस इंतजाम से बहुत भारी फायदा भी हुआ। जहाँ 1967–68 में कुल 27–28 लाख टन अनाज पैदा हुआ था, वहाँ 1970–71 में 47 लाख टन से भी अधिक का एक रिकार्ड उत्पादन हुआ है। इंडस्ट्रीज में जो लेबर ओरिएन्टिड इंडस्ट्रीज हैं, हम उनको तरजीह देते हैं और साथ ही साथ स्माल इंडस्ट्रीज में स्माल कैपिटल सरकुलेशन के साथ–साथ, लेबर के लिये भी पूरी फैसिलीटीज देना चाहते हैं।

हमारे यहाँ पर फाइनैंशियल कारपोरेशन ने 455 यूनिटस को पिछले 3 सालों के अन्दर 8 करोड़ रूपये से भी अधिक के लोन्ज दिये हैं। इन यूनिट्स में अधिकतर छोटे यूनिट्स शामिल हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ एक्सपोर्ट के लिये इंडस्ट्रियल प्रोडक्टस भी बहुत बढ़े हैं। 1970–71 में हमारे यहाँ से 12 करोड़ रूपये से भी अधिक के सामान के एक्सपोर्ट होने की सम्भावना है।

स्पीकर साहब, मैं आपको बताऊं, इकनोमी के 2–3 ही पहलू हुआ करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर को है, इंडस्ट्रीज का है या एग्रो–इंडस्ट्रीज का है। एग्रो–इंडस्ट्रीज में डेयरी डिवोल्पमैंट भी आती हैं। मैंने भी और मुख्यमंत्री जी ने भी यह कहा है कि हम व्हाईट रैवोल्यूशन लाना चाहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ग्रीन रैवोल्यूशन तो आया हुआ है। व्हाईट रैवोल्यूशन के लिये ज्यादा से ज्यादा मिल्क सप्लाई की कोशिश की जा रही है।

इसके अलावा, छोटे तबके के लोगों को सुविधाएं देने के लिये हमने बहुत से उपाय किये हैं। जिस प्रकार से गवर्नमैंट आफ इंडिया की जो स्माल फार्मर्ज डिवैल्पमैंट एजेन्सिज और मार्जिनल फार्मर्ज एंड एग्रीकल्चरल लेबर एजेन्सिज की स्कीम थी, इसके द्वारा आपने देखा होगा, 2 करोड़ रूपया अगले साल में डिसबर्स किया जाएगा। अम्बाला में स्माल फार्मर्ज एजेन्सिज द्वारा लगभग 28000 लोग लोन के लिये आइडैन्टीफाई हुये हैं जबकि गुडगांव में 11000 स्माल फार्मर्ज को लोन देने के लिये आइडैन्टीफाई किया गया है। हम उनको इन जिलों में पम्पिंग सैट्स की सुविधा, लैंड रिफार्म की सुविधा, गाय–भैंस खरीदने की सुविधा और दूसरी सारी चीजें के लिये सुविधा देना चाहते हैं। इन एजेन्सिज के जरिये हम अपनी स्टेट के मध्यम और छोटे वर्ग के लोगों के और नजदीक पहुंच सकेंगे।

हमारे यहाँ हरिजन कल्याण निगम की खास तौर से चर्चा हुई है। इसके बारे में पिछले कई सालों से इस हाउस में यह आवाज उठ रही थी कि इसे बनाया जाये। अब सरकार ने यह कदम उठाया है और इसके जरिये जो छोटे–छोटे काम करने वाले हमारे भाई हैं और जो खुद जूते या चमड़े का काम करना चाहें या जमीन खरीदना चाहें, उनको इससे सुविधा मिलती है। सरकार ने पहले दफा 20 लाख रूपये का इतना बड़ा प्रोवीजन उनके लिये किया है। आपको शायद मालूम होगा कि हरिजनों के लिये कम्युनिटी सैंटर्ज के लिये फार दी फर्स्ट टाईम, इस साल के बजट

के अन्दर कुछ पैसा दिया गया है। हमारे सुबेदार साहब (श्री प्रभुसिंह) ने कहा है कि इस पैसे को और भी बढ़ाया जाये। मैं इस बात का प्रयत्न करूंगी कि हम इस मामले में उन्हें और भी ज्यादा सुविधा दे सकें।

एजुकेशन के बारें में मैं आपको बताना चाहती हूं। बैकवर्ड क्लासिज और हरिजनों को एजुकेशन देने के लिए कुछ स्पैशल स्टैप्स लिये गये हैं। इस तरीके से आप देखिये कि हमारी प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों लोकसभा के इलैक्शन के दौरान, देश को जो गरीबी हटाओं का नारा दिया है, हम उस ओर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मंगल सैन जी चाहे इसका मजाक बनायें, लेकिन मैं बताऊं कि यह हमें अच्छे सजैशन दें। जैसे मुख्यमंत्री जी ने भी यहाँ कई बार कहा है कि हम अपोजीशन की हर अच्छी बात को मानने के लिये तैयार हैं वैसे ही मैं भी यही कहती हूं कि ये यहां सजैशन दें कि इकोनौमी को अच्छा बनाने के लिये क्या कदम उठाये जा सकते हैं, हाउस उनका स्वागत करेगा।

चौ. जय सिंह राठी: आप हमारी बात तो मानती हैं नहीं।

श्रीमती ओम प्रभा: राठी साहब, आप तो बात ही ऐसी करते हैं। आप अच्छी सजेशन दें तो हम जरूर मानेंगे। आप आज रात को सोच लें और कल को सजेशन दे देना।

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, ये मंडे तक सोच लें और मंडे को दे दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज।

श्रीमती ओम प्रभा: स्पीकर साहब, गरीबी दूर हटाना एक बहुत मुश्किल काम है और खासकर हिन्दुस्तान जैसे मुल्क के लिए जहां पर कि लाखों, करोड़ों इन्सानों के सामने गरीबी की बड़ी भारी समस्या है। हर राज्य सरकार का आज यह फर्ज बनता है, और खासकर इस लड़ाई के बाद जबकि हिन्दुस्तान की सरकार पर ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है और उन्होंने फारेन ऐड को खत्म करने का एक नया दृष्टिकोण अपनाया है, कि हमारी पार्टी और हमारी प्राईम मिनिस्टर जो प्रोग्राम चाहती हैं उसको पूरा करने के लिए हर तरीके से कोशिश करें, समाजवाद का जो हमने नारा दिया है उसको पूरा करें। समाजवाद का मतलब यह होता है कि सबको अपरच्यूनिटी बराबर की दें। हमारी अधिक से अधिक यही कोशिश है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दें। मैं समझती हूं कि हमारी सरकार ने वैसे तो हर क्षेत्र में काफी काम किया है लेकिन इरीगेशन के लिए खास तौर से काम किया है। जूई कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल, बीरेन्द्र नारायण चक्रवर्ती कैनाल बनाकर हमने उन लोगों को पानी दिया है जोकि पानी के लिए तरसते थे। आज आप वहां जाकर देखें कि उस इलाके का कितना रूप बदल गया है। जूई नहर से छह हजार एकड़ भूमि को सिचाई हुई है। वैस्टर्न जमना कैनाल आगमैन्टेशन प्रौजैक्ट एक बड़ी

सिंचाई परियोजना है। इस स्कीम के अनुसार पानी की सप्लाई का बढ़ाया जाएगा। हम व्यास सतलुज लिंक योजना के फैसले का इंतजार कर रहे हैं उस फैसले से हमें और भी पानी मिल जाएगा और फिर हरियाणा का रूप ही बदल जाएगा। कुछ मैम्बर्ज ने डिस्क्रिमीनेशन की बात की है, मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहती हूं कि चाहे अपोजीशन मैम्बर्ज को कोई बैकवर्ड एरिया हो या हमारी पार्टी के मैम्बर्ज का बैकवर्ड एरिया हो हम सबको ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। हम हरिजनों और बैकवर्ड क्लासिज को भी ऊपर उठाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। हरिजनों को सरविसिज में पूरा रिप्रेजेन्टेशन दे रहे हैं। हरिजन लड़के अगर किसी नौकरी के लिए एक बार नहीं मिलें तो उस पोस्ट को दुबारा एडवरटाइज किया जाए, ऐसा हमने कहा हुआ है। उनको हम नौकरियों में कंसेशन दे रहे हैं।

स्पीकर साहब, मैं एक बात और कह कर खत्म करती हूं। आज इस बात की बहुत चर्चा की जाती है कि हरियाणा का बजट डेफिशिट में है। मैं यह मानती हूं कि 1972–73 को 15 करोड़ रूपए का डेफिशिट बजट पेश किया गया है, पिछले साल ग्यारह करोड़ का डेफिशिट था, उससे पहले साल बारह करोड़ का डेफिशिट था। स्पीकर साहब, डेफिशिट होने के बावजूद हमने हरियणा की जनता को नए टैक्स के बोझ से नहीं दबाया है। यह डेफिशिट को परमानेन्ट नेचर का नहीं है। कालिज में जब एक लड़का पढ़ने जाता है तो उस पर काफी खर्चा रकना पड़ता है उस

समय तो इन्वैस्टमैंट होती है और किसी रिटर्न की आशा नहीं की जाती है इसी प्रकार हरियाणा एक नई स्टेट है, अभी तो इसको चार ही साल हुए हैं। अभी इस पर इंवैस्टमेंट करने की जरूरत है। इसका रिजल्ट हमको अवश्य मिलेगा। कुछ ही सालों में हमारी इकोनमी बहुत साउन्ड हो जाएगी। हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है उसमें डेफिशिट फाईनैनसिंग बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। 250 करोड़ रूपए के बजट में 15 करोड़ रूपए का घाटा होना कोई बड़ी बात नहीं है। सैन्ट्रल असिस्टेंस ने बढने के बावजूद हरियाणा ने कितनी तरक्की की है, हमारी इकोनौमी का यह एक स्वस्थ चिन्ह है। अन्त में अपोजीशन वालों से मैं यही कहना चाहती हूं कि वे कम से कम गवर्नमेंट के डिवेलपमेंट के कामों की दाद दें और सरकार का इस मामले में साथ दें। मुख्यमंत्री जी ने यहां सदन में और बाहर भी बार–बार यही कहा है कि अगर अपोजीशन वाले कोई अच्छा सुझाव दें तो हम जरूर मानेंगे। मुख्यमंत्री जी ने करप्शन के विषय में भी जवाब दिया था। करप्शन के सम्बन्ध में वे कोई चीज बताएं। हमारे पास विजीलेंस डिपार्टमेंट है, पुलिस है, सी.आई.डी. है, ऐसे मामलों की जरूर इन्कवारी कराई जाएगी। इतना कहकर मैं समाप्त करती हूं।

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 9.30 A.M.

6.35 P.M.

(The Sabha then adjourned till 9.30 A.M. on Friday, the 14th January, 1972)